वर्ष 72 ▸ अंक 325 ▸ पृष्ठ 12
रीवा, शनिवार 23 अगस्त, 2025
भाद्रपद कृष्ण पक्ष 15, विक्रम संवत् 2082
नगर ▸ मूल्य 5 रुपए

विश्व का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला अखबार

दैनिक जागरण

www.dainikjagranmpcg.com

> किसी देश की महानता और उसकी नैतिक प्रगति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है।
> -महात्मा गांधी

डॉग लवर्स की जीत: सुप्रीम कोर्ट ने बदला फैसला- सभी कुत्तों का टीकाकरण व नसबंदी जरूरी

आवारा कुत्तों की आजादी बरकरार सिर्फ खूंखार रहेंगे शेल्टर होम में

नई दिल्ली, जेएनएन। डॉग लवर्स को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामले में राहत देते हुए उन्हें शेल्टर होम भेजने के अपने ही फैसले को बदल दिया है। कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाता है, उनकी नसबंदी और टीकाकरण कर जहां से उठाया है, वहीं वापिस छोड़ दिया जाए। हालांकि, रेबीज से संक्रमित और आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों को शेल्टर होम में ही रखा जाए। कोर्ट ने आदेश दिया कि कुत्तों को पब्लिक प्लेस में खाना न दिया जाए और नगर निगम इसके लिए अलग जगह बनाए। कोर्ट ने कहा कि ये आदेश दिल्ली समेत पूरे देश में लागू होगा। कोर्ट ने 11 अगस्त के 2 जजों की बेंच के उस आदेश को बेहद कठोर बताया, जिसमें सभी आवारा कुत्तों को 8 हफ्तों में दिल्ली-एनसीआर के आवासीय क्षेत्रों से हटाकर हमेशा के लिए शेल्टर होम में भेजने का आदेश दिया था। जस्टिस विक्रम नाथ,जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की स्पेशल बेंच ने 14 अगस्त को डॉग लवर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

जुर्माना आम लोगों के लिए नहीं: याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वकील विवेक शर्मा ने कहा कि आदेश में जिन दंडों का जिक्र हुआ है, वे नागरिकों के लिए नहीं हैं। उन्होंने बताया, आदेश में 25 हजार रुपए और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का यह आदेश गैर-सरकारी संगठनों और स्वतः संज्ञान मामले में हस्तक्षेप करने वालों के लिए है, आम लोगों के लिए नहीं हैं, इसका मकसद आदेश को पढ़कर समझा जा सकता है। इन धनराशियों का उपयोग कुत्तों के कल्याण के लिए किया जाएगा।

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुक्रवार को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर पशु प्रेमियों ने खुशी में मिठाई बांटकर एक-दूसरे का मुंह मीठा किया।

कोर्ट के आदेश की अहम बातें

पब्लिक फीडिंग बैन: सार्वजनिक जगहों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर सख्त मनाही होगी। नगर निकायों को हर नपा वार्ड में फीडिंग जोन बनाने होंगे। उल्लंघन पर कानून के तहत दंडनीय होगा।

आक्रामक कुत्तों को संभालना: रेबीज के लक्षण या आक्रामक व्यवहार दिखाने वाले कुत्तों को क्वारंटीन और आश्रय गृहों में रखा जाना चाहिए, न कि उन्हें छोड़ा जाना चाहिए।

उपचार के बाद वापसी: आवारा कुत्तों को नसबंदी, टीकाकरण और दवा देने के बाद उनके मूल इलाकों में वापस छोड़ा जा सकता है।

गोद लेने को प्रोत्साहन : शख्स और पशु प्रेमी आवारा कुत्तों को गोद ले सकते हैं, लेकिन यह तय करना उनकी जिम्मेदारी होगी कि उन्हें सड़कों पर वापस न छोड़ा जाए।

फैसले का राष्ट्रव्यापी दायरा: कोर्ट ने सभी राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों को मामले में पक्षकार बनाया है, और आवारा कुत्तों के मैनेजमेंट के संबंध में एक समान राष्ट्रीय नीति तैयार करने के मकसद से हाई कोर्ट्स में लंबित सभी समान मामलों को अपने अधीन कर लिया है। अगली सुनवाई 8 हफ्ते बाद अक्टूबर के लिए लिस्ट कर दी है।

पशु प्रेमी 25 हजार, दो लाख जमा करें एनजीओ

आवारा कुत्तों की भलाई पर होगा खर्च

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि आवारा कुत्तों के मामले में कोर्ट से संपर्क करने वाले व्यक्तिगत कुत्ता प्रेमियों और गैर सरकारी संगठनों को क्रमशः 25,000 रुपए और 2 लाख रुपए न्यायालय रजिस्ट्री में जमा कराने होंगे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने साफ किया कि ये राशि सात दिनों के अंदर जमा करनी होगी, अन्यथा याचिकाकर्ता या हस्तक्षेपकर्ता को मामले में आगे पेश होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने साफ किया कि एकत्र की गई धनराशि का उपयोग आवारा कुत्तों के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के निर्माण में किया जाएगा, जिसको जमीन पर लागू करने का काम संबंधित नगर निकायों के तत्वावधान में किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कानूनी हस्तक्षेप केवल अदालती कार्यवाही तक ही सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर ठोस कल्याणकारी उपायों में तब्दील हो।

> मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। यह पशु कल्याण और जन सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एक कदम है।
> ■ **राहुल गांधी**, नेता प्रतिपक्ष

> पिछला आदेश न केवल अमानवीय था, बल्कि उस मानवीय उद्देश्य के भी खिलाफ था, जिस पर सभी विश्वास करते हैं। कोर्ट ने गलत फैसले को ठीक कर दिया है।
> ■ **प्रियंका चतुर्वेदी**, सांसद शिवसेना

> मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं। जहां तक बात खूंखार कुत्तों की है। अदालत ने इसकी पहचान नहीं बताई है। इसे परिभाषित करने की जरूरत है।
> ■ **मेनका गांधी**, भाजपा नेता

बिहार एसआईआर: सुप्रीम कोर्ट का आदेश

मतदाता सूची में नाम जोड़ने आधार मान्य

नई दिल्ली, जेएनएन। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर पर शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह हटाए गए वोटर्स को लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने के लिए फिजिकल आवेदन भी स्वीकार करे। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आधार कार्ड समेत फॉर्म 6 में दिए गए 11 दस्तावेज में से कोई भी जमा किया जा सकता है, इनमें ड्राइविंग लाइसेंस, पासबुक, पानी का बिल जैसे डॉक्यूमेंट शामिल हैं।

सर्वोच्च अदालत ने एसआईआर की सुनवाई के दौरान राजनीतिक पार्टियों को मामले पर चुप्पी साधने के लिए भी फटकार लगाई और पूछा कि मतदाताओं की मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं। आपको आगे आना चाहिए। अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।

हैरानी: 1.6 लाख बूथ एजेंट आपत्तियां आईं सिर्फ दो

कोर्ट ने चुनाव आयोग से कई सवाल पूछे। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा-राजनीतिक दलों की निष्क्रियता हैरान करने वाली है। राज्य की 12 पॉलिटिकल पार्टियों में से यहां मात्र 3 पार्टियां ही कोर्ट में आई हैं। वोटर्स की मदद के लिए आप क्या कर रहे हैं। कोर्ट ने इस बात पर भी हैरानी जताई कि राजनीतिक दलों के लगभग 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट होने के बावजूद उनकी ओर से केवल दो आपत्तियां ही आई हैं।

भारतीय मूल के व्यवसायी ने प्लेन में किया नाबालिग से रेप

कोर्ट में बोला-खुद पर काबू नहीं रख पाया

नई दिल्ली, जेएनएन। भारतीय मूल के व्यवसायी ने मुंबई से स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख जा रही फ्लाइट में 15 साल की एक नाबालिग लड़की से रेप की बात स्वीकार की। कोर्ट में उसने कबूल किया कि वो खुद पर कंट्रोल नहीं रख सका। उड़ान के दौरान वह बच्ची उसके बगल में सो रही थी। भारतीय मूल के आरोपी को डेढ़ साल की निलंबित सजा दी गई, जिससे वो जेल से रिहा हो गया। अब उसे भारत डिपोर्ट किया जाएगा। ज्यूरिख के सरकारी वकील के मुताबिक, प्लेन में लड़की ने आरोपी के साथ थोड़ी देर बातचीत की थी और फिर सो गई। इसके बाद आरोपी ने लड़की के कंधे पर हाथ रखा और उसे गलत तरीके से छूकर यौन शोषण किया। घटना से लड़की सदमे में चली गई और न तो बोल पाई, न ही विरोध कर पाई। बाद में उसने हिम्मत दिखाते हुए फ्लाइट अटेंडेंट से गुहार लगाई। फ्लाइट अटेंडेंट ने तुरंत पुलिस को खबर दी और लड़की को दूसरी सीट पर भेजा। फ्लाइट के ज्यूरिख पहुंचने पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

आरोपी ने कोर्ट में स्वीकार किया कि उसे पता था, लड़की नाबालिग है। उसने कबूल किया कि लड़की ने कोई सहमति नहीं दी थी। कोर्ट ने उसे रेप और नाबालिग के यौन शोषण का दोषी पाया। फिर भी उसे डेढ़ साल की सस्पेंडेड सजा दी गई, जिसका मतलब है कि उसे जेल नहीं जाना पड़ेगा, बशर्ते वह भविष्य में कोई अपराध न करे।

संक्षिप्त खबरें

संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में घोषित किया अकाल

तेल अवीव, जेएनएन। वैश्विक भूख निगरानी संस्था ने शुक्रवार को कहा कि गाजा शहर और उसके आसपास के क्षेत्र आधिकारिक तौर पर अकाल से पीड़ित हैं। निकट भविष्य में यह अकाल और बढ़ता जाएगा। संस्था के इस आंकलन से

इजरायल पर फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवीय सहायता पहुंचने देने को लेकर दबाव और अधिक बढ़ेगा। आईपीसी यानी एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण प्रणाली ने कहा, 5 लाख 14 हजार यानी एक चौथाई फिलिस्तीनी अकाल का सामना कर रहे हैं। सितंबर के अंत तक यह संख्या 641,000 हो जाएगी, इनमें से 280,000 लोग गाजा के उत्तरी क्षेत्र में हैं, जिसे गाजा गवर्नरेट के रूप में जाना जाता है। आईपीसी ने कहा, दो सालों से चल रहे युद्ध के बाद क्षेत्र अब अकालग्रस्त हो गया है। यह पहली बार है, जब आईपीसी ने अफ्रीका के बाहर दुनिया में कहीं अकाल दर्ज किया। संस्था ने कहा, अगले महीने तक अकाल की स्थिति डेर अल-बलाह, खान यूनिस के मध्य दक्षिणी क्षेत्रों तक फैल जाएगी।

श्रीलंका: पूर्व राष्ट्रपति विक्रमसिंघे गिरफ्तार

कोलंबो, जेएनएन। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को पुलिस ने सरकारी धन का दुरुपयोग करने के मामले में गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप है कि 2023 में राष्ट्रपति रहते हुए वे अपनी पत्नी प्रोफेसर मैत्री विक्रमसिंघे के दीक्षांत समारोह

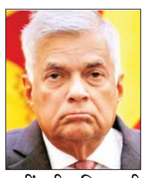

शामिल होने लंदन गए थे। पुलिस का कहना है कि लंदन में उनकी कोई आधिकारिक यात्रा नहीं थी, फिर भी इसे सरकारी खर्चे पर किया गया। इस यात्रा में 10 लोगों का ग्रुप शामिल था और 1.69 करोड़ रुपए खर्च किया गया। उस समय विक्रमसिंघे क्यूबा, अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर थे, जिसके बाद वे निजी यात्रा के लिए ब्रिटेन चले गए थे। उन पर अपने पर्सनल बॉडीगार्ड को भी सरकारी खजाने से सैलरी देने का आरोप है। विक्रमसिंघे सुबह वित्तीय अपराध जांच विभाग में पूछताछ के लिए पहुंचे थे। 4 घंटे चली पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वे श्रीलंकाई इतिहास में गिरफ्तार होने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं।

दीवार गिरने से 3 की मौत

डेवलपर, ठेकेदार पर एफआईआर दर्ज

जागरण, इंदौर। स्मार्ट सिटी कॉलोनी में बीते 18 अगस्त को दीवार गिरने से तीन मजदूरों की मौत के मामले में राजेंद्र नगर पुलिस ने डेवलपर, सुपरवाइजर, ठेकेदार की सुरक्षा उपकरणों को लेकर लापरवाही सामने आई। पुलिस ने तीनों दोषियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की है और जल्द ही तीनों की गिरफ्तारी होगी। टीआई नीरज बिरथरे के मुताबिक, शिवसिटी के गेट नंबर-3 के आगे स्मार्ट सिटी कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है।

ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, फैंटेसी गेमिंग पर लगेगा ताला

मानसून सत्र में सरकार ने पेश किया था बिल

नई दिल्ली, जेएनएन। संसद के हालिया मॉनसून सत्र में पास हुआ ऑनलाइन गेमिंग बिल कानून बन गया है। लोकसभा,राज्यसभा से पारित ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। अब यह कानून बन गया और प्रावधान लागू हो गए हैं। यह कानून लागू होने के बाद फैंटेसी लीग, कार्ड गेम्स, ऑनलाइन लॉटरी, पोकर, रमी और सट्टेबाजी पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया है। ऑनलाइन गेमिंग बिल 20 अगस्त को लोकसभा, 21 अगस्त को राज्यसभा से पारित हुआ था। बिल आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था। कानून के आने से देश की ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है। ड्रीम 11 और माय इलेवन सर्किल जैसे फैंटेसी गेमिंग ऐप्स ने प्लेटफॉर्म पर रियल मनी गेम्स पर रोक लगा दी है। देश में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री कुल 3.8 अरब डॉलर होने का अनुमान है। नए कानून से इस उद्योग का भविष्य खतरे में है। वैष्णव ने बिल पेश करते हुए कहा था, बिल के तीन सेगमेंट हैं। दो सेगमेंट को सरकार प्रमोट करेगी, रियल मनी गेमिंग पर रोक लगेगी। मंत्री ने रियल मनी गेमिंग को समाज के सामने बड़ी चुनौती बताते हुए कहा था कि सरकार को समाज व राजस्व में से किसी एक को चुनने की बात आए, तो सरकार ने हमेशा समाज को प्राथमिकता दी है।

आरिफ मसूद को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

विशेष संवाददाता, भोपाल। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ एसआईटी की जांच फिलहाल नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार को स्टे देते हुए मसूद को बड़ी

राहत दी है। पिछले दिनों मप्र हाईकोर्ट ने भोपाल के इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज मामले में एफआईआर और एसआईटी से जांच के आदेश दिए थे। इस पर विधायक मसूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय एसआईटी का भी गठन किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विधायक मसूद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, जहां शुक्रवार को उन्हें बड़ी राहत मिली। जस्टिस जेके महेश्वरी की बेंच ने हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट में विधायक मसूद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, विवेक तन्खा और वरुण तन्खा पेश हुए।

संसद की सुरक्षा में चूक कैंपस में पहुंचा शख्स

नई दिल्ली, जेएनएन। संसद भवन की सुरक्षा में शुक्रवार को सेंध का मामला सामने आया। एक व्यक्ति दीवार कूदकर संसद भवन में घुस गया और गरुड़ द्वारा तक पहुंच गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे तुरंत दबोच लिया। अब उससे पूछताछ की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी सुबह 6.30 बजे रेलभवन के पास पेड़ की मदद से दीवार पर चढ़ा और कूदकर अंदर घुसा। हालांकि, घटना के समय संसद में कोई सांसद मौजूद नहीं था। संसद का मानसून सत्र गुरुवार को खत्म हो गया था और राज्यसभा और लोकसभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था।

प्राचार्य की मारपीट से छात्रा का दांत टूटा, एफआईआर

बच्चों का आरोप-नशे में करते हैं पिटाई

जागरण, मैहर। प्रदेश के मैहर में सरकारी स्कूल के प्राचार्य पर बच्चों ने नशे में स्कूल आकर हाथ-पैर दबवाने और मारपीट के आरोप लगाए हैं। बच्चों का कहना है कि प्राचार्य बेहोश होने तक पीटते हैं।

एक छात्रा को तो प्रिंसिपल ने ऐसा पीटा कि उसका दांत टूट गया। मामला शासकीय पूर्व मावि उमरी फिफरी थाना नादन देहात का है। यहां पदस्थ प्राचार्य शिवराज सिंह बघेल ने पांचवीं की छात्रा को इतना बेरहमी से मारा कि उसका दांत टूट गया। मुंह खून से लाल हो गया। छात्रा घर पहुंची और परिजनों को घटना बताई। परिजन और अन्य पीड़ित बच्चे थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने प्राचार्य बघेल के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित छात्रा आंशिक प्रजापति ने बताया कि सर ने उसे इतना मारा कि दांत टूट गया। मुंह से बहुत सारा खून भी निकला। दूसरी पीड़ित छात्रा प्रिया प्रजापति ने आरोप लगाया कि प्राचार्य नशा करने के बाद बच्चों पर सारा गुस्सा निकालते हैं और बच्चों को बेहोश होने तक पीटते हैं। यह घटना कई महीनों से चली आ रही है।

एलआईसी ऑफ इंडिया प्रस्तुत कर रहा है स्पेशल रिवाइवल कैम्पेन लेट फ़ी में कन्सेशन के साथ.

अवधि 18/08/2025 से 17/10/2025

जल्दी! इस मौके को जाने न दें.

आपके बीमे की सुरक्षा को वापस हासिल करने और उसका लाभ लगातार लेते रहने का मौका.

कुल देय प्रीमियम	% विलम्ब शुल्क में रियायत	रियायत की अधिकतम सीमा*
₹1,00,000 तक	30%	₹3000
1,00,001 से 3,00,000 तक	30%	₹4000
3,00,001 व अधिक	30%	₹5000

*नियम व शर्तें लागू

पॉलिसियों को अदा न किए गए पहले प्रीमियम की तिथि से 5 वर्षों के अंदर पुनर्चलित किया जा सकता है.

कृपया अपनी नज़दीकी एलआईसी शाखा या एजेंट से संपर्क करें. हमसे जुड़े रहें. एलआईसी में अपना मोबाइल नंबर, ईमेल, एनईएफ़टी और पैन नंबर अपडेट करें.

डाउनलोड कीजिए एलआईसी मोबाइल ऐप LIC digital | विज़िट करें:licindia.in | कॉल सेन्टर सर्विस (022) 6827 6827 | IRDAI Regn No.: 512

अधिक जानकारी के लिए अपने एजेंट/नज़दीकी एलआईसी शाखा से संपर्क करें या अपने शहर का नाम SMS करें 56767474 पर.

हमें फौलो करें: LIC India Forever | हमारा वॉट्सएप नं. 8976862090 कहिए 'Hi'

LIC भारतीय जीवन बीमा निगम LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA हर पल आपके साथ

धोखेधड़ी वाले फ़ोन कॉल्स तथा झूठे/भ्रामक प्रस्तावों से सावधान रहें. आईआरडीएआई या इनके कर्मचारी बीमा व्यवसाय जैसे कि बीमा पॉलिसियों की बिक्री, बोनस की घोषणा या प्रीमियम्स के निवेश, राशियां लौटाना जैसी कोई भी गतिविधियों में शामिल नहीं होते हैं. जिन पॉलिसीधारकों या संभावित ग्राहकों को ऐसे फ़ोन कॉल्स मिलें, वे कृपया पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज करें. कृपया बिक्री के समापन से पहले बिक्री पुस्तिका को ध्यान से पढ़ लें.

LIC/MI/2025-26/15/Hin

डिंडोरी जिले में 64 मजदूरों की 19 दिन की मजदूरी बकाया, सरपंच-सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप

जागरण, डिंडोरी । जिले के बजाग जनपद की ग्राम पंचायत गीधा में पंचायत स्तर पर भ्रष्टाचार और मजदूरी भुगतान में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। शुक्रवार को उप सरपंच, जनपद सदस्य, पंच और मजदूरों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की।

मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया : जनपद सदस्य नीता राजपूत और उप सरपंच नंद कुमार राजपूत ने सरपंच पार्वती धूमकेती और सचिव लाल सिंह मार्को पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि वर्ष 2024-25 में कराए गए सीसी सड़क निर्माण में 64 मजदूरों को 19 दिन की मजदूरी का भुगतान अब तक नहीं मिला है।

घटिया निर्माण और मनमानी का आरोप : ग्रामीणों का आरोप है कि छापर नाला में बनाए गए दो चेक डेम बेहद घटिया क्वालिटी के हैं। सोकता गड्ढों का निर्माण अधूरा छोड़ दिया गया, लेकिन सप्लायर को पूरा भुगतान कर दिया गया। इसके अलावा पुराने पंचायत भवन का सामान महज 15 हजार रुपये में नीलाम कर दिया गया।

सचिव पर भी गंभीर आरोप : ग्रामीणों ने बताया कि हाट बाजार की वसूली और यूकेलिप्टस पेड़ों की बिक्री से प्राप्त राशि का भी दुरुपयोग किया गया है। खेत तालाब का काम कराए बिना ही सरपंच ने राशि अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत सचिव अक्सर नशे की हालत में रहता है और लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज करता है।

कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन : तहसीलदार आर.पी. मार्को को सीईओ अनिल कुमार राठौर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान पंच प्रहलाद, नंदिनी बाई, हरिवती, अहिल्या बाई, राजकुमारी, सोमती, मूलचंद, शिवबालक और सविता समेत कई ग्रामीण महिलाएं भी मौजूद रहीं ।

कर्मयोगी अभियान के तहत दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण का हुआ समापन

जागरण, डिंडोरी । भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय एवं मध्यप्रदेश शासन के जनजातीय कार्य विभाग के संयुक्त तत्वावधान में आदि कर्मयोगी अभियान के अंतर्गत जनजातीय समाज के विकास एवं परिवर्तन के लिए × दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण दिनांक 20 अगस्त से 22 अगस्त 2025 तक कन्या शिक्षा परिसर डिंडौरी के सभागार में प्रशिक्षण का समापन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ कलेक्टर श्रीमती नेहा मारव्या ने किया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारी, कर्मचारी, गैर सरकारी संगठन एवं सामुदायिक आधारित संगठन को सेवा, समर्पण एवं संकल्प के मंत्र के साथ तैयार करना है, ताकि वे शासन की योजनाओं को पात्र जनजातीय परिवारों तक प्रभावी रूप से पहुंचा सकें। आदि कर्मयोगी अभियान रेस्पोंसिव गवर्नेंस प्रोग्राम के तहत ब्लाक स्तरीय प्रोसेस लैब के सफल बनाने हेतु दिनांक 20 अगस्त से 22 अगस्त 2025 तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में 5 विभागों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हुए। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनरों द्वारा विकासखंड स्तरीय मास्टर ट्रेनरों को व्यक्तित्व विकास, प्रशिक्षण सत्र के आयोजन की विधि एवं ब्लॉक स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति संबंधी मार्गदर्शन प्रदान किया गया।मुख्य अतिथि के द्वारा आदि कर्मयोगी अभियान में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारी कर्मचारियों को शपथ दिलाई कि ''हम आदि कर्मयोगी, संविधान को साक्षी मानकर, यह शपथ लेते हैं कि, आदि कर्मयोगी के रूप में, अपने दायित्वों के साथ-साथ, मैदना स्तर पर, अनुशासन और इमानदारी से, विशेष पिछडी जनजाति, एवं अंतिम छोर के, हर व्यक्ति को, शासन की योजना का, लाभ पहुंचाएंगे''। प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे सुपरवाइजर महिला बाल विकास श्रीमती गिरी मेडम, श्रीमती दयावती गौलिया, श्रीमती रेखा मरावी, बीएसी अमरपुर श्री मूलचंदानी आदि के द्वारा अपना अपना प्रशिक्षण का अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि हमने अपने जीवन में पहली बार इस प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिससे स्वयं के साथ-साथ हम दूसरे लोगों को भी बेहतर से बेहतर अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए गांव के लोगों को शासन की योजनाओं से अधिक लाभ दिलाने में सफल होंगे। श्रीमती दयावती गौलिया ने गीत गाकर प्रशिक्षण एवं शासन की मंशा का सार प्रस्तुत किया। अंत में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री राजेन्द्र कुमार जाटव ने सभी को धन्यवाद देते हुए कहा कि हम सब ने जो प्रशिक्षण में सीखा है उसे बेहतर से बेहतर अनुभव के साथ शासन की योजनाओं को ग्रामीण अंचलों में निवासरत लोगों को लाभान्वित करने का प्रयास किया जाए। भारत सरकार की आदि कर्मयोगी अभियान का उद्देश्य अंतिम छोर पर खडे व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि शासन की योजना का हर व्यक्ति को लाभ मिल सके। प्रशिक्षण समापन कार्यक्रम में सहायक नोडल अधिकारी एवं सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग श्री राजेंद्र कुमार जाटव, प्राचार्य कन्या शिक्षा परिसर श्री रामविशाल, प्राचार्य सीएम राइज नरिया श्री बंशबहोर द्विवेदी, श्री मनमोहन महोबिया, स्वप्निल अवस्थी, समस्त शिक्षक सहित विभिन्न विभागों के जिलाधिकारी एवं ब्लॉक स्तरीय मास्टर ट्रेनर उपस्थित रहे।

कृषि सखी एवं कृषकों को प्राकृतिक खेती की बताई विधि

मंडला । कृषि विभाग की आत्मा परियोजना अंतर्गत वरिष्ठ कृषि विकासखंड बीजाडांडी कार्यालय में प्राकृतिक खेती जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। विकासखंड तकनीकी प्रबंधक मोहित गोल्हानी ने कृषकों को प्राकृतिक खेती अंतर्गत जीवामृत बिजामृत नीमास्त्र बनाने की विधि की जानकारी दी। कार्यक्रम में उपसंचालक कृषि अश्विनी झारिया ,सहायक संचालक कृषि आर डी जाटव व.कृ.वि अधि.संगीता श्रीवास्तव ने श्री अन्न रागी फसल की मिनी किट कृषकों को वितरण की गई ,उद्यान विस्तार अधिकारी देवी सिंग पटेल कृषि विस्तार अधि.पुष्पेंद्र वर्मा ,स्वेता डेहरिया अनिल मुनिया दिलीप भूरीया कृषक उपस्थित रहे।

डॉक्टर गायब, स्कूल की पढ़ाई कमजोर, अधिकारियों पर गिरी गाज

डिंडोरी । मध्यप्रदेश के डिंडौरी जिले में उप जिला मजिस्ट्रेट (एसडीएम) रामबाबू देवांगन ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करंजिया, हायर सेकेंडरी स्कूल गोरखपुर एवं बजाग का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य केंद्र करंजिया में बीएमओ डॉ. गोपाल मरावी एवं डॉ. आस्था द्विवेदी अनुपस्थित पाए गए। कार्य के प्रति लापरवाही मानते हुए एसडीएम ने दोनों चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित करने के निर्देश दिए।वहीं गोरखपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में निरीक्षण के दौरान साफ-सफाई, शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था, पुस्तकें और अध्ययन स्तर की समीक्षा की गई। इस दौरान शिक्षा का स्तर कमजोर पाया गया, जिस पर एसडीएम ने प्राचार्य एवं संबंधित विषय शिक्षकों को सुधार लाने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगली बार निरीक्षण में किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। एसडीएम ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि मूलभूत सुविधाएं और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है और इस दिशा में किसी भी प्रकार की लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ग्राम पंचायत गीधा में सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव, पंचों ने लगाई गंभीर आरोपों की झड़ी

जागरण, डिंडोरी । मध्यप्रदेश के डिंडौरी के जिले बजाग जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत गीधा में सरपंच पार्वती बाई के खिलाफ निर्वाचित पंचगणों ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। पंचों ने यह प्रस्ताव जिला पंचायत डिंडौरी के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को सौंपा ।पंचों ने आरोप लगाया है कि सरपंच द्वारा पंचायत के कार्यों में निरंतर लापरवाही, अनियमितता और मनमानी की जा रही है। इसके कारण ग्राम पंचायत की विकास योजनाएँ प्रभावित हो रही हैं तथा जनहित से जुड़े कार्यों की अनदेखी की जा रही है ।पंचगणों के अनुसार, ग्रामवासियों की शिकायतों और आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे पंचायत की गरिमा एवं विकास कार्यों पर प्रतिकूल असर पड़ा है। साथ ही, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी पारदर्शिता का अभाव बताया गया है ।निर्वाचित पंचगणों ने संयुक्त रूप से मांग की है कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 21 के तहत नियमानुसार विशेष बैठक आहूत कर मतदान कराया जाए, ताकि सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लिया जा सके।

आगामी पर्वों के संबंध में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक संपन्न

जागरण, मंडला । पुलिस अधीक्षक श्री रजत सकलेचा एवं सीईओ जिला पंचायत श्री श्रेयांश कूमट की उपस्थिति में गणेश उत्सव, मिलाद-उन-नबी एवं आगामी पर्वों के संबंध में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जिला योजना भवन में हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर श्री राजेन्द्र कुमार सिंह, नगरपालिका अध्यक्ष श्री विनोद कछवाहा, जनपद पंचायत अध्यक्ष मंडला श्री संतोष सोनू भलावी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री शिवकुमार वर्मा, मंडला एसडीएम श्रीमती सोनल सिडाम, एसडीओपी श्री पीयुष मिश्रा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी तथा समिति सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में सभी त्यौहार आपसी भाईचारे एवं सौहार्दपूर्वक मनाने का आग्रह किया गया। बैठक में पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पंडालों में बिजली के तारों की सुरक्षा रखी जाए एवं लोहे के खम्भों पर विद्युत कनेक्शन सावधानीपूर्वक लगाएं। विद्युत लाइन के नीचे प्रतिमा की स्थापना न करें। प्रतिमाओं का विसर्जन निर्धारित कृत्रिम विसर्जन कुंडों में ही किया जाए। तैराक की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन करें। किसी भी प्रकार का जुलूस निकालने के पूर्व सक्षम अधिकारी से लिखित में अनुमति प्राप्त करें। मार्गों पर समुचित साफ-सफाई एवं पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करें। पुलिस अधीक्षक श्री सकलेचा ने निर्देशित किया कि ऐसे स्थान जहां पर प्रतिमा पंडाल स्थापित होने से आवागमन बाधित होता है, उन स्थानों को अनुमति प्रदान न करें। संबंधित अधिकारी गणेश उत्सव समिति की सूची बनाकर संबंधित थाने में उपलब्ध कराएं। बैठक में मिलाद-उन-नबी के संबंध में भी चर्चा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए गए। बैठक में घरों में स्थापित भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए नगरपालिका परिषद की ओर से वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने के संबंध में चर्चा की गई। इसके लिए चिन्हित स्थानों पर चलित अथवा स्थाई रूप से कुंड या ड्रम की व्यवस्था किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नगरपालिका अध्यक्ष श्री विनोद कछवाहा ने धार्मिक पर्वों के दौरान नगरीय सड़कों पर आवारा पशुओं की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित कराया एवं सीएमओ नगरपालिका से तत्संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने के लिए कहा। बैठक के दौरान मंडला एवं महाराजपुर दोनों थाना क्षेत्रों में क्षेत्रीय आयोजकों के साथ पुनः बैठक कराने के संबंध में निर्देशित किया गया।

खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर की मांग, पूर्व विधायक राकेश गिरी ने की एमएसएमई मंत्री से मुलाकात

टीकमगढ़। टीकमगढ़ जिले के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से टीकमगढ़ विधानसभा के पूर्व विधायक राकेश गिरी ने गुरुवार को मध्यप्रदेश शासन के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्री चैतन्य काश्यप से भोपाल में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान पूर्व विधायक ने जिले की विशेष परिस्थितियों और कृषि उत्पादन को ध्यान में रखते हुए कहा कि टीकमगढ़ में गेहूं, दलहन और तिलहन का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन उपयुक्त प्रसंस्करण इकाइयों के अभाव में किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता।

खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर की मांग : राकेश गिरी ने मंत्री से आग्रह किया कि टीकमगढ़ में खाद्य प्रसंस्करण क्लस्टर की स्थापना की जाए। इसके माध्यम से किसानों को अपनी उपज का मूल्य स्थानीय स्तर पर ही प्राप्त होगा और उन्हें बड़े शहरों या अन्य जिलों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे कृषि उपज की बर्बादी भी रुकेगी और उत्पादन को नया बाजार मिलेगा।

स्वच्छ वार्ड-सुव्यवस्थित शहर, यही है नगर पालिका का संकल्प : सीएमओ भदौरिया

टीकमगढ़। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ओमपाल सिंह भदौरिया ने शुक्रवार को शहर के वार्ड क्रमांक 27 और नवीन बस स्टैंड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वार्डवासियों से संवाद कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली और मौके पर मौजूद अधिकारियों को उनके निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिए। वार्ड भ्रमण के दौरान नागरिकों ने नालियों पर अतिक्रमण और गंदगी की शिकायतें रखीं। इस पर सीएमओ ने तत्काल सफाई हवलदार को नालियों से अतिक्रमण हटाकर नियमित सफाई कराने और व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वार्डों में स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त करना नगर पालिका की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सीएमओ भदौरिया ने इसके बाद नवीन बस स्टैंड का मौका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने शौचालयों की सफाई व्यवस्था देखी और इसे और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। साथ ही स्टैंड पर अनियमित ढंग से लगे फल-फ्रूट और सब्जी के ठेलों को व्यवस्थित कराया तथा परिसर की तत्काल सफाई करवाई। उन्होंने कहा कि बस स्टैंड शहर की छवि को दर्शाता है, इसलिए यहां स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखना आवश्यक है। निरीक्षण के दौरान सफाई हवलदार राकेश करौसिया भी मौजूद रहे। वार्डवासियों ने सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया के जनहितैषी दृष्टिकोण और सक्रियता की सराहना की।

नव नियुक्त कांग्रेस जिलाध्यक्ष अध्यक्ष की स्वागत रैली कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार

जागरण, मंडला । जिले की राजनीति में गुरुवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जब जिला कांग्रेस कमेटी मंडला के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष पूर्व विधायक डॉ. अशोक मर्सकोले का भव्य स्वागत गाजे-बाजे और विशाल रैली के साथ किया गया। गौरतलब है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संगठन सृजन अभियान के तहत निवास विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक डॉ. मर्सकोले को मंडला जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है।इस नियुक्ति के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा गया और इसे संगठन के लिए एक मजबूत कदम माना जा रहा है। स्वागत रैली का प्रारंभ राजपूत ढाबा (कटरा) से हुआ। इसके बाद रैली का काफिला उत्साह और नारों के बीच राजुल होंडा, बिंझिया तिराहा, लालीपुर चौराहा, बस स्टैंड,अंबेडकर चौक,रेडक्रॉस भवन, बैगा बैगी चौक और नेहरू स्मारक होते हुए आगे बढ़ा।जगह-जगह लोगों ने फूलमालाओं और आतिशबाजी के साथ नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का स्वागत किया। अंततः रैली का समापन धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व वाले महिष्मति घाट (रपटा) पर हुआ।इस भव्य कार्यक्रम में जिले भर से कांग्रेस के विभिन्न विभागों और प्रकोष्ठों के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में शामिल हुए। कार्यकर्ताओं का जोश और एकजुटता देखने लायक थी। कई जगहों पर महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस और एनएसयूआई,शहर कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस,वरिष्ठ पदाधिकारीगण,एवं कार्यकर्ताओं ने अलग-अलग अंदाज में स्वागत कर माहौल को और भी ऊर्जावान बना दिया। कांग्रेस जनों का कहना है कि डॉ. अशोक मर्सकोले की नियुक्ति से जिले के संगठन को नई दिशा और मजबूती मिलेगी।कार्यकर्ताओं ने विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में मंडला जिले में कांग्रेस पार्टी और अधिक सक्रिय एवं मजबूत होगी। स्वागत समारोह के दौरान पूरा नगर कांग्रेस के नारों से गूंज उठा और रैली ने उत्सव का रूप ले लिया। इसे लेकर पार्टीजनों में गहरी संतुष्टि और उत्साह साफ तौर पर झलक रहा था।

कल्दा में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन आज

पवई । कलेक्टर सुरेश कुमार के निर्देश पर शनिवार, 23 अगस्त को कल्दा में सुबह 11 बजे से जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर में आम जनता की समस्याओं के निराकरण सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं का तत्काल लाभ प्रदान करना सुनिश्चित किया जाएगा। इस दौरान ग्रामीणजनों को सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी। जिला कलेक्टर के निर्देशानुसार शिविर आयोजन के दो दिवस पूर्व से कल्दा में आधार केन्द्र भी संचालित किया गया। इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने आधार नामांकन और अपडेशन कार्य करवाया। शिविर के सफल आयोजन के लिए संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए गए हैं। जन समस्या निवारण शिविर में उत्तर वनमंडल कार्यालय के अधिकारियों सहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जनपद पंचायत सीईओ पवई, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, श्रम पदाधिकारी, अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला समन्वयक जनअभियान परिषद, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं विद्युत मंडल के कार्यपालन यंत्री, महाप्रबंधक जल निगम, जिला संयोजक सहित उप संचालक कृषि, उद्यानिकी और पशु चिकित्सा सेवायें भी उपस्थित रहेंगे।

विश्वविद्यालय के बाहर छात्रों ने किया का हंगामा

छतरपुर । महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के बाहर बीएससी रिजल्ट में कथित अनियमितताओं के विरोध में गुरुवार की दोपहर सैकड़ों छात्रों ने सड़क पर लेटकर चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कॉपियों की जांच में लापरवाही का आरोप लगाते हुए रिजल्ट में सुधार की मांग की है। छात्र नेता सत्येंद्र शर्मा ने बताया कि गत मंगलवार को विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए बीएससी रिजल्ट में ज्यादातर छात्रों का प्रदर्शन खराब रहा। छात्रों ने आरोप लगाया है कि कॉपियों की जांच लापरवाही से की गई, जिसके कारण उनके अंक अपेक्षा से बहुत कम आए। इसी बात से नाराज छात्र आज विश्वविद्यालय के बाहर सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने सड़क पर लेटकर चक्का जाम किया और रिजल्ट में सुधार की मांग को लेकर नारेबाजी की। सत्येंद्र ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही ने छात्रों का भविष्य दांव पर लगा दिया है। हम तब तक प्रदर्शन जारी रखेंगे, जब तक रिजल्ट में सुधार नहीं होता।

रक्तदान कर जीवन बचाएं ब्रह्माकुमारी

पन्ना । प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा विशाल रक्तदान महा अभियान का हुआ शुभारंभ, यह अभियान संस्थान की पूर्व मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि के 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर विश्व बंधुत्व की ओर एक कदम बढ़ाए मानवता को बचाए उपलक्ष में पूरे भारतवर्ष के साथ-साथ नेपाल के भी अनेक ब्रह्माकुमारी के सेवा केंद्रो द्वारा 22 अगस्त से 25 अगस्त तक रहेगा ।

अंतिम चयन सूची प्रकाशित

पन्ना । महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय पन्ना शहरी द्वारा आंगनबाड़ी सहायिका के रिक्त तीन पद पर भर्ती के लिए गत 21 अगस्त को अंतिम चयन सूची प्रकाशित कर दी गई है। परियोजना अधिकारी किरण खरे ने बताया कि पूर्व में प्रकाशित अनंतिम चयन सूची के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी दावा-आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। जारी सूची अनुसार वार्ड क्रमांक 8 शिवाजी वार्ड में सहायिका के पद पर नैनसी नामदेव, वार्ड क्रमांक 11 राघवेन्द्र वार्ड में आरती प्रजापति तथा वार्ड क्रमांक 12 गांधी वार्ड में स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए चेतना अहिरवार का अंतिम रूप से चयन किया गया है। चयनित नहीं होने वाले आवेदकों द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं होने पर सूची प्रकाशन तिथि से 10 दिवस के भीतर कलेक्टर न्यायालय में प्रथम अपील तथा प्रथम अपील से संतुष्ट न होने की स्थिति में अपील के निराकरण उपरांत 10 दिवस के भीतर संभागायुक्त न्यायालय में द्वितीय अपील की जा सकती है।

यूरिया खाद के लिए किसान दर-दर भटक रहे, मंडी गोदाम में मनमानी वितरण से नाराजगी

पवई । खरीफ सीजन में धान की फसल के लिए अत्याधिक आवश्यक यूरिया खाद पवई क्षेत्र में किसानों को समय पर नहीं मिल पा रही है। हालात यह हैं कि किसानों को खाद के लिए दिनभर धूप और बारिश में लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है, फिर भी पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं हो रही। किसान बताते हैं कि कृषि उपज मंडी गोदाम पवई से खाद वितरण किया जा रहा है,

पर्यावरण शुद्धता का संदेश देने गुनौर में माटी गणेश-सिद्ध गणेश कार्यशाला का हुआ आयोजन

पन्ना । शासन के निर्देशानुसार जनअभियान परिषद द्वारा गुनौर विकासखण्ड में पर्यावरण शुद्धता का संदेश देने के लिए माटी गणेश-सिद्ध गणेश अभियान अंतर्गत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें संभाग समन्वयक दिनेश उमरैया सहित जिला समन्वयक अनीता जाटव, ब्लाक समन्वयक जगदीश सिंह भी उपस्थित रहे।

विशाल चट्टानों पर प्राचीन शैल चित्र मिले

पन्ना । दक्षिण वनमंडल के परिक्षेत्र अंतर्गत बौलिया सर्किल स्थित खिलसारी की पन्नी के समीप विशाल चट्टानों पर प्राचीन शैल चित्रों की खोज हुई है। इन अद्वितीय चित्रों को प्रकृति संरक्षण कार्यकर्ता अजय चौरसिया ने खोज कर साझा किया है।विशेषज्ञों के अनुसार ये चित्र अत्यंत प्राचीन काल के हैं और मानव सभ्यता के आरंभिक विकास, सांस्कृतिक गतिविधियों तथा उस दौर के सामाजिक जीवन का सजीव प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। लाल-गेरुए रंगों से बने ये चित्र आज भी स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो हमारी प्रागैतिहासिक धरोहर की महत्ता को दर्शाते हैं। खिलसारी की पन्नी अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ बहने वाली नदी का जल कई फीट ऊँचाई से गिरकर एक मनोरम झरना बनाता है, जो विशेषकर बरसात के दिनों में अत्यंत भव्य रूप ले लेता है। झरने के आसपास का वनक्षेत्र कुल्लू, अर्जुन, कठजामुन जैसे वृक्षों तथा विविध वन्य जीव-जंतुओं से समृद्ध है। पक्षियों का कलरव और तितलियों की उड़ान इस स्थल की खूबसूरती में चार चाँद लगाते हैं। इतना ही नहीं, शैल चित्रों के समीप स्थित बड़ादेव का स्थल आदिवासी समाज की आस्था का केंद्र है, जो इस स्थान को धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण बनाता है।

संरक्षण की आवश्यकता : इतिहासकारों और प्रकृति प्रेमियों का मानना है कि खिलसारी की पन्नी में मिले इन शैल चित्रों को पुरातात्विक धरोहर के रूप में संरक्षित करना अनिवार्य है। इनका संरक्षण न केवल हमारे अतीत को समझने में सहायक होगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी यह अमूल्य धरोहर बनी रहेगी।

संभागायुक्त ने अजयगढ़ तहसील कार्यालय का किया निरीक्षण

जागरण, पन्ना । कमिश्नर अनिल सुचारी ने आज अजयगढ़ तहसील कार्यालय पहुंचकर औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने राजस्व मामलों से संबंधित लंबित प्रकरणों की जानकारी लेकर समय-सीमा में निराकरण के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर संभागायुक्त अनिल सुचारी ने सायबर तहसील के बेहतर क्रियान्वयन तथा अधिकारी-कर्मचारियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित कर शासन के निर्देशों के तहत कार्रवाई के निर्देश भी दिए। साथ ही राजस्व रिकार्ड के ऑनलाइन संधारण तथा आपदा राहत राशि प्रकरणों की समीक्षा कर प्रभावितजनों को समय पर राहत राशि का वितरण सुनिश्चित करने के लिए कहा। इस दौरान राजस्व के दर्ज मामलों के निराकरण के संबंध में कार्यप्रणाली के बारे में भी पूछा और विभिन्न राजस्व अभिलेखों के संधारण का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक आपदा और आगजनी इत्यादि तथा आरबीसी 6-4 के प्रकरणों पर भी समय सीमा में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। राजस्व अधिकारी नियमित रूप से स्वयं कार्यों के प्रगति की समीक्षा करें और अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण कर प्रगति का जायजा भी लें।

थाना बीजाडांडी में शांति समिति की बैठक सम्पन्न

जागरण, मंडला । थाना बीजाडांडी परिसर में शुक्रवार को शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नवयुक्त थाना प्रभारी प्रदीप पांडे ने की। बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, धार्मिक व सामाजिक संगठन के पदाधिकारी तथा गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष डुमरीलाल कुम्हारे, पूर्व मंडल अध्यक्ष आदित्य मिश्रा, प्रदेश अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यालय मंत्री संदीप कुलस्ते, मंडल उपाध्यक्ष मो. सफ़र, जनपद सदस्य राजेंद्र पुट्टा, जनपद उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव, मस्जिद सुभानिया के सदर अकील मंसूरी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य पुष्पा सिंह उद्दे, सरपंच संघ के अध्यक्ष बलदेव परते सहित भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीणजन शामिल हुएपर्वों की शांति व्यवस्था पर हुई चर्चा बैठक में आगामी जश्ने ईद मिलादुन्नबी और गणेश भगवान के विसर्जन जैसे पर्वों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। थाना प्रभारी पांडे ने कहा कि ऱ्रत्योहार केवल उत्सव का अवसर नहीं बल्कि समाज में आपसी भाईचारे और प्रेम को मजबूत करने का माध्यम भी हैं। बीजाडांडी की पहचान गंगा-जमुनी तहज़ीब से है, इसे हर हाल में बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। जनप्रतिनिधियों ने रखे विचार भाजपा मंडल अध्यक्ष डुमरीलाल कुम्हारे ने कहा कि सभी धर्मों और समाजों का मिलजुलकर पर्व मनाना ही वास्तविक संस्कृति है। वहीं, मस्जिद सुभानिया के सदर अकील मंसूरी ने कहा कि ऱ्रईद मिलादुन्नबी का जुलूस शांति और भाईचारे का प्रतीक है। सभी समुदायों के सहयोग से यह पर्व सौहार्दपूर्ण ढंग से सम्पन्न होगा।

उर्मिल नदी के उद्गम पर वृहद पौधरोपण

छतरपुर। गंगोत्री हरित परियोजना अंतर्गत उर्मिल नदी उद् ?गम स्थल पर कलेक्टर पार्थ जैसवाल एवं सी.ई.ओ. जिला पंचायत तपस्या परिहार द्वारा जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों की उपस्थिति में वृहद पौधरोपण कार्यक्रम में पौधे लगाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आव्हान पर पर्यावरण संरक्षण एवं सामुदायिक भागीदारी के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत करने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान की प्रेरणा से उदभूत परिकल्पना के अनुक्रम में नदी के उदगम स्थल के पास गंगोत्री हरित परियोजना अंतर्गत उर्मिल नदी के उद् ?गम स्थल ग्राम पंचायत बूदौर में पौधरोपण का आयोजन किया गया। उर्मिल नदी का उद्गम बूदौर तालाब से छोटे से नाले के रूप में होता है जो 5 कि.मी. बाद नदी का आकार ले लेती है।

स्वयं का मकान बना सरकारी मकानों में जमे कर्मचारी

किराए के मकान में रहते हैं बाहर के कर्मचारी

स्थानांतरण व सेवानिवृत्ति के बाद भी शासकीय आवासों पर जमाए हैं कब्जा

जागरण, सीधी

जिला मुख्यालय में पदस्थ शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी शहर में अपना मकान बना लेने के बाद भी शासकीय आवास का मोह नहीं छोंड़ रहे हैं। अपना स्वयं का मकान किराये में देकर शासकीय आवासों पर कब्जा जमाये हुये हैं। यही नही जिन अधिकारी एवं कर्मचारियों का वर्षो पूर्व स्थानांतण हो गया है और जो सेवानिवृत्त हो गये है वह अपना शासकीय आवास खाली नही कर रहे हैं। बताते चलें कि जिला मुख्यालय में लोक निर्माण विभाग एवं अन्य मदो से निर्मित सरकारी भवनों में ऐसे अधिकारी कर्मचारी अपना डेरा जमाए हुए हैं, जबकि इनको शासकीय आवास की पात्रता ही नहीं हैं। यही नहीं कई ऐसे शासकीय आवास है जिसका आवंटन किसी और के नाम है और रहता कोई और हैं। यहां के शासकीय अधिकारी एवं कर्मचारी अपने नाम से शासकीय आवास का आवंटन करा कर उसको अपने नात-रिस्तेदारों को रहने के लिए दे दिए हैं। कलेक्ट्रेट परिसर में भवन आवंटन शाखा के जिम्मेदार लोगों द्वारा इन्हें खुली छूट दे दी गई है। जिसके चलते यह मकान नहीं खाली कर रहे हैं। जिले में 1 दर्जन से अधिक ऐसे शासकीय अधिकारी कर्मचारी हैं जो रहते तो सरकारी मकान में है लेकिन उनका खुद का मकान भी नगर पालिका क्षेत्र के अन्तर्गत बना हुआ हैं और जो अधिकारी एवं कर्मचारी अन्य जिलों से आ कर यहां अपनी सेवाएं दे रहे है उनको शासकीय आवास नही मिल रहा है। वह मजबूरन किराये के मकान में रहते हैं। यहां तक की कई ऐसे शासकीय भवन भी है जो कि वर्तमान समय पर काफी जर्जर हालत में पहुंच गए हैं। इसके बाद भी शासकीय कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डाल कर रह रहें हैं। कलेक्ट्रेट आवास शाखा से शासकीय मकान आवंटन की जो सूची तैयार की गई है उसमें जो अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि 15 वर्षों पूर्व सीधी छोड़ कर चले गये है उनके नाम अभी भी शासकीय आवास आवंटित हैं। इतना ही नहीं जो शासकीय कर्मचारी जिले से दूसरे जिले में चले गए हैं उनका नाम भी शासकीय आवास के आवंटन से नहीं हटाया गया है। वह आवास भी वर्तमान समय पर आवास साखा में भरे हुए हैं और उन आवास में अवैध रूप से अन्य लोग आराम से रह रहे हैं। यही नहीं जिले में ऐसे कई सरकारी मकान हैं जिनकी स्थिति काफी जर्जर हो चुकी है। बावजूद इसके यह कर्मचारी सरकारी मकान छोडने को तैयार नहीं है। जिले में लोक निर्माण विभाग के 40 सहित कुल 217 मकान है। वर्तमान में एक भी मकान रिक्त नहीं है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार जी टाइप के 16, आई टाइप के 73, एस टाइप के 56 एवं एफ टाइप के 72 मकान है जिसमें सभी मकान भरे हुए हैं जबकि इन मकानों की पड़ताल कराई जाए तो आधे से अधिक मकान अवैध कब्जाधारियों से मुक्त हो सकते हैं। कलेक्ट्रेट स्थित आवास शाखा के लिपिको के द्वारा ऐसे आवासों को जिनका स्थानांतरण हो चुका है या फिर दूसरा अन्य आवास आवंटित कर दिया है। ऐसे आवासों को स्वयं अपने स्तर से शासकीय कर्मचारी के नाम आवास का आवंटन कर देते है।

ज्यादा कर्मचारी वाले विभाग चर्चित

शासकीय आवास पर ज्यादा कर्मचारी वाले विभाग का अमला एक बार पहुंच जाने के बाद उसको छोंड़ने के लिए तैयार नहीं होता। स्थिति तो यह है कि इस मामले में आरईएस, महान नहर संभाग, खनिज, जनपद, तहसील, शिक्षा, पीएचई, स्वास्थ्य, राजस्व प्रमुख हैं। स्थिति तो यह है कि संबंधित कर्मचारियों का स्थानांतरण हो जाने के बाद भी वह मकान खाली करने की जरूरत नहीं समझते। कर्मचारी चले भी जाते हैं तो उनके परिजन सरकारी मकान में बराबर जमे रहते हैं। तत्संबंध जानकारों का कहना है कि विभागीय अधिकारियों के पास भी कई बार शिकायत पहुंचती है लेकिन उनके द्वारा भी इसको गंभीरता के साथ नहीं लिया जाता। अब तो स्थिति यह है कि पुलिस विभाग के शासकीय आवासों में भी स्थानांतरित कर्मचारी लंबे समय तक जमे रहते हैं। उनके द्वारा यह दलील दी जाती है कि वह जिले के विभिन्न थाना एवं चौकी में ही पदस्थ हैं। इस वजह से जिला स्तर पर उन्हें आवास चाहिए। जबकि उन्हें थाना स्तर पर भी शासकीय आवास उपलब्ध होता है। शासकीय आवासों के प्रति सरकारी कर्मचारियों की कब्जा करने की नीति का हाल यह है कि काफी कर्मचारी अपना स्वयं का मकान जिला मुख्यालय में बना चुके हैं। जिसको किराए पर दे दिया जाता है और वह सालों से शासकीय आवास में जमे हैं।

बाइक की टक्कर से वृद्ध की मौत, परिजनों ने लगाए आरोप

जागरण, सीधी। जिले के थाना बहरी क्षेत्रांतर्गत ग्राम शरदा में बाइक की टक्कर से वृद्ध की मौत पर परिजनों ने सुनियोजित तरीके से हत्या करने का आरोप लगाया है। मिली जानकारी के अनुसार शरदा निवासी 75 वर्षीय वृद्ध राजमणि जायसवाल अपने ही एक घर से दूसरे घर दिनांक 22 अगस्त को सुबह 9 बजे के करीबन जा रहे थे। उसी दौरान पास का ही एक युवक बाइक लेकर आया और टक्कर मार दी जिससे राजमणि जायसवाल गिर गए और जब लोगों ने देखा तो उनकी सांस रूक चुकी थी। लोगों ने आनन-फानन में पुलिस को सूचना दीए मौके स्थल पर पुलिस पहुंची और शव को बहरी मर्चुरी हाउस लेकर आई। परिजनों का आरोप है कि 3 घंटे तक इंतजार करने के बाद डॉक्टर लेट पहुंचे जिसकी वजह से रात भर पीएम की हुई बॉडी को घर में रखना पड़ेगा। दाह संस्कार सुबह कर पाएंगे। पुलिस के मुताबिक मामले की जांच चल रही है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार पूरा मामला क्या था।

आपसी रंजिश के कारण टक्कर मारने का आरोप

वहीं उक्त मामले पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुराना जमीनी विवाद था। इसी कारण से गोलू जायसवाल ने बाइक से टक्कर मार दिया। हालांकि मामला अभी जांच के घेरे में है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार सच्चाई क्या थी। देखना दिलचस्प होगा कि कब तक में मामले की जांच हो पाएगी।

शहर एवं ग्रामीण अंचल की खबरें

माटी गणेश, सिद्ध गणेश अभियान को लेकर हुई बैठक

जागरण, सीधी। मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद प्रदेश नेतृत्व के कुशल आह्वान पर आज जिला सीधी के खंड मझौली प्रज्ञा भवन में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मझौली के मुख्य अतिथि, विकास खंड समन्वयक रजनीश मिश्रा की अध्यक्षता एवं विशिष्ट अतिथि अयोध्या प्रसाद पटेल की उपस्थिति में समितियों की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया एवं सामाजिक न्याय विभाग के विकासखंड समय नारायण प्रसाद बैगा की उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। बैठक में पांचों नवांकुर समितियों के प्रतिनिधि, सभी सेक्टर के सक्रिय प्रस्फुटन समिति के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों की विशेष उपस्थिति में बैठक में निम्नलिखित विषयों पर प्रेरित किया गया। समग्र से आधार लिंक करने में सहयोग करना, एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम को लेकर वायुदूत में अपलोड करना, माटी गणेश, सिद्ध गणेश के तहत विभिन्न जगहों पर जन भागीदारी से प्रेरित करना जैसे विषयों को लेकर जन अभियान परिषद की खंड स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक के अन्त में उपस्थित समस्त सदस्यों को नशामुक्ति का शपथ दिलाया गया व ई सपथ हेतु सभी को प्रेरित किया गया। बैठक में परामर्शदाता रजनीश द्विवेदी द्वारा बनी प्रतिमा को मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रदान किया। वहीं अंबिकेश मिश्रा ने विकास खंड श्रोत समन्वयक को बनी प्रतिमा प्रदान कर आभार प्रगट किया गया।

शिक्षक वंशपति पटेल का निधन, शोक

जागरण, मोहनिया। ग्राम पंचायत मोहनिया के पूर्व सरपंच श्रीमती राजकली पटेल के पति वंशपति पटेल शिक्षक जो रामपुर के मूर्तला कोठार में पदस्थ थे। जिनकी मृत्यु दिनांक 19 अगस्त 2025 को सुबह 5 बजे अचानक ह्रदय गति रुक जाने से हो गई। श्री मास्टर साहब के दुखद निधन से उनके परिवार एवं पूरे गांव में शोक की लहर छाई हुई है। चुरहट विधायक अजय सिंह राहुल भैया ने गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है।

गौरक्षक दल ने गौवंशों के बांधे सुरक्षात्मक रेडियम

जागरण, मझौली। बेसहारा बेजुबान प्राणी जो सड़कों पर बैठ अपनी जान गवा रहे हैं, उनकी दुर्दशा को देखते हुए थाना प्रभारी मझौली विशाल शर्मा एवं खंड चिकित्सा अधिकारी मझौली राकेश तिवारी के आग्रह तथा सहयोग से विगत दिवस गौ सेवा, गौ रक्षक दल सीधी के प्रमुख केशव मिश्रा अपने साथियों के साथ मझौली पहुंच अभियान चलाकर थाना प्रभारी विशाल शर्मा तथा खंड चिकित्सा अधिकारी राकेश तिवारी के अगुवाई में अभियान चलाकर सड़क तथा कार्यालयों के प्रांगण पर ठहरे हजारों गौ वंशों के गले में लाल कलर का रेडियम बांधा गया। मीडिया से रूबरू होते हुए केशव मिश्रा द्वारा बताया गया कि जिले में मैं गौ सेवा को रक्षक दल बनाकर बेसहारा गौ वंशों की सुरक्षा करने का प्रयास कर रहा हूं, जिले में एक छोटा सा ट्रस्ट बनाकर दुर्घटना से ग्रसित गौवंशों को यहां रख उनकी सुरक्षा तथा दवाइयों का प्रबंध करता हूं, विगत कई दिनों से थाना प्रभारी द्वारा इस कार्य के लिए मुझे प्रेरित किया जा रहा था, जिनके आग्रह और प्रेरणा पर मैं दल बल-के साथ पहुंच थाना प्रभारी एवं खंड चिकित्सा अधिकारी के अगुवाई में दुर्घटना में कमी लाने गौ वंशों के गले में रेडियम पहनने के अभियान का शुभारंभ मझौली से किया गया हैं। आगे पूरे जिले में अभियान चलाकर गौ वंश रक्षा के लिए रेडियम बांधने का काम हमारे दल द्वारा निरंतर जारी रहेगा।

सरपंच, सचिव, वाल्व ऑपरेटर की सह कार्यशाला आयोजित

जागरण, मझौली। मध्य प्रदेश जल निगम पीआईयू सीधी के द्वारा मझौली ग्रामीण समूह जलप्रदाय योजना अंतर्गत आज 22 अगस्त को जनपद पंचायत मझौली के 18 ग्राम पंचायतों के 25 ग्रामों के लिए पंचायत दर्पण पोर्टल के माध्यम से जलकर भुगतान हेतु प्रशिक्षण, वाल्व ऑपरेटर के दायित्व एवं ग्राम जल एवं स्वछता तदर्थ समिति के पदेन सरपंच सचिव, जनपद पंचायत के सभाकक्ष में जनपद पंचायत मझौली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अधयक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में ग्राम पंचायत, ग्राम जल एवं स्वछता तदर्थ समिति के सरपंच, सचिव, वाल्वमैन को प्रशिक्षित किया गया। जनसहभागिता एसक्यूसी टीम द्वारा उपस्थित सचिवों को अपनी अपनी पंचायतों में जलकर राशि वसूली, पंचायत दर्पण पोर्टल द्वारा जल निगम को बल्क जल प्रभार राशि के रूप में जमा कराने सहित पेयजल सप्लाई को सुचारू रूप से संचालन-संधारण एवं प्रबंधन के संबंध में पीपीटी के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि सरपंच सचिव पेयजल का समुचित प्रयोग, पेय जल व्यर्थ न करने एवं जलकर राशि का भुगतान नियमित रूप से समय पर करने एवं ग्राम पेयजल स्वच्छता समिति की नियमित बैठक का आयोजन एवं योजना के संचालन में सहयोग प्रदान करें।

राकेश पटवारी संघ जिला अध्यक्ष एवं सदस्यता प्रभारी नियुक्त

जागरण, सीधी। प्रांतीय पटवारी संघ भोपाल के के प्रदेशाध्यक्ष अश्विन कुमार सैनी ने संघ के संविधान की कंडिका 15 में अध्यक्ष के अधिकार एवं प्रांतीय पटवारी संघ के गठन के पश्चात् प्रदेशध्जिले में संगठन के विस्तार व पटवारियों की समस्या को जिला स्तर पर निराकरण हेतु राकेश कुमार पाण्डेय को सीधी जिले का कार्यवाहक जिला अध्यक्ष एवं सदस्यता प्रभारी नियुक्त किया है। दिनांक 30 जून 2024 की प्रांतीय पटवारी संघ की आम सभा के निर्णय अनुसार मुख्य निर्वाचन अधिकारी रंधावा सिंह खत्री एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र लकवाल, शत्रुघ्न सोनी, जितेन्द्र चौहान से सम्पर्क कर जिले में निर्वावन की तिथि घोषित कर निर्वाचन प्रकिया सम्पन्न करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कृषि ग्रामीण मजदूर संघ के संभागीय अध्यक्ष बने वीरभानु सिंह

जागरण, सीधी। अखिल भारतीय कृषि एवं ग्रामीण मजदूर महासंघ के संपन्न हुए दो दिवसीय अधिवेशन में अल्ट्राटेक सीधी सीमेंट प्लांट में कार्यशील बीएएमएस यूनियन के अध्यक्ष वीरभानु सिंह को संभागीय अध्यक्ष बनाया गया है। बडखरा चुरहट सीधी निवासी वीरभानु सिंह पूर्व में संभागीय कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर चयनित थे। भारतीय मजदूर संघ के असंगठित क्षेत्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंती लाल के मुख्य आतिथ्य एवं महासंघ के अध्यक्ष के यन मोहनन की अध्यक्षता तथा राष्ट्रीय महामंत्री बृजेश सिंह के विशिष्ट आतिथ्य में बीते 18 अगस्त को संभागीय कार्य समिति का चयन भारतीय मजदूर संघ की रीति नीति के अनुसार किया गया। जारी विज्ञप्ति में सीमेंट मजदूर महासंघ मध्यप्रदेश के संयुक्त महासचिव उमा निवास मिश्रा पदेन ट्रेड यूनियन महामंत्री द्वारा बताया गया कि वीरभानु सिंह अल्ट्राटेक सीधी सीमेंट प्लांट में विगत 2017 से कार्यशील अल्ट्राटेक सीमेंट कर्मचारी एवं खदान श्रमिक संघ मझिगवां जिला सीधी मध्यप्रदेश सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष हैं। भारतीय मजदूर संघ के प्रादेशिक प्रतिनिधि के रूप में अपनी नैतिक कर्मठता का परिचय परिलक्षित करने वाले श्री सिंह को कृषि ग्रामीण मजदूर संघ का संभागीय अध्यक्ष बनाए जाने पर एक तरफ जहां सीमेंट प्लांट के समीपवर्ती गांवों के कृषि मजदूरों की समस्याओं का समयानुकूल अपेक्षित समाधान होगा, वहीं दूसरी तरफ सीमेंट प्लांट में कार्यान्वित श्रमिकों से संबंधित कार्यों को अपेक्षाकृत बल मिलेगा। प्रदेश कार्यसमिति सदस्य गजराज तिवारी, पूर्व विभाग प्रमुख सिंगरौली व बीएमएस के वर्तमान प्रादेशिक सदस्य डीपी दुबे, रमाशंकर तिवारी, रीवा मगनलाल वाल्मीकि विभाग प्रमुख सतना, कृषि एवं ग्रामीण मजदूर संघ मध्य प्रदेश के महामंत्री रणछोर सिंह, रीवा के मंत्री दीपनारायण द्विवेदी व विकास शुक्ला, दीपनारायण सिंह, अभिनव सिंह चंदेल, राकेश शुक्ला आदि जिला एवं संभाग के प्रमुख संघीय जन एवं सीमेंट फेडरेशन मध्यप्रदेश के अध्यक्ष संजय कुमार तिवारी के सहित यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष प्रशांत तिवारी, उपाध्यक्ष योगेन्द्र द्विवेदी, बृजेश तिवारी, ओंकार उर्मलिया, कोषाध्यक्ष सुनील सिंह, संगठन मंत्री संतोष माडेकर, कार्यालय मंत्री अजीत सिंह, मंत्री राधाकांत तिवारी, सुमेश मिश्रा पुष्पेन्द्र सिंह के सहित अमित सिंह, शिरीष पाण्डेय आदि वरिष्ठ जनों ने प्रसन्नता व्यक्त की है।

डॉ. वर्मा निलंबित, डॉ. श्रेया की कड़ी मेहनत से स्वास्थ्य सेवाओं में देखा गया सुधार

जागरण, सीधी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बबिता खरे ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरिया में पदस्थ डॉ. आरके वर्मा को राज्य स्तर से निलंबित किए जाने के बाद डॉ. श्रेया त्रिपाठी को खण्ड चिकित्सा अधिकारी का प्रभार सौंपा गया है। उन्होंने बताया कि अभी तक सेमरिया सीएचसी में हो रही अव्यवस्था में सुधार देखने को मिलने लगा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेमरिया में शुक्रवार को डॉ. त्रिपाठी द्वारा 250 मरीज देखे गए, 1 पोस्टमार्टम और 3 एमएलसी भी किए साथ में डॉ. विवेक तिवारी भी उपस्थित रहे। वर्तमान में सेमरिया सीएचसी में बॉण्डेड डॉ. सोनाली वर्मा, डॉ. अरुणेंद्र सिंह, डॉ. आकाश सिंह समय पर उपस्थित हो कर कार्य कर रहे हैं।

बाल न्याय प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में बैठक आयोजित

जागरण, सीधी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रयाग लाल दिनकर के मार्गदर्शन में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी मुकेश कुमार शिवहरे तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक द्वारा दिनांक 22 अगस्त 2025 को बच्चों से संबंधित मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं, अन्य हितधारकों एवं पैरालीगल वॉलेंटियरों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अधिवक्ताओं एवं प्रतिभागियों से बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, बाल न्याय प्रणाली के प्रभावी क्रियान्वयन तथा उनके कल्याण से संबंधित विषयों पर सुझाव प्राप्त किए गए। साथ ही उपस्थित सभी हितधारकों ने बाल संरक्षण हेतु सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर बल दिया। इसके अतिरिक्त सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी मुकेश कुमार शिवहरे तथा जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक द्वारा विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया जिसमें प्रतिभागियों को बच्चों से जुड़े मामलों में लागू विभिन्न कानूनों, निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं तथा उपलब्ध सेवाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। बैठक एवं शिविर का उद्देश्य बच्चों के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना तथा समाज में विधिक जागरूकता का प्रसार करना रहा। जिला विधिक सहायता अधिकरी मनीष कौशिक ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आमजन को न्याय दिलाने हेतु निरंतर कार्यरत है। उक्त शिविर में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी मुकेश कुमार शिवहरे एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी मनीष कौशिक, अधिवक्तागण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कर्मचारीगण रूपेन्द्र कुमार मिश्रा, राजेश प्रताप सिंह, उमाकांत शुक्ला, सुश्री अदिति पटेल तथा अन्य सभी हितधारक सहित जिला सीधी एवं तहसील रामपुर नैकिन एवं मझौली के पैरालीगल वॉलेंटियर्स उपस्थित रहे।

बाइकों की आमने-सामने टक्कर, तीन गंभीर

जागरण, सीधी। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 सीधी . सिंगरौली में उपनी गांव में तेज रफ्तार दो बाईकों के आमने-सामने टक्कर में तीन लोगों को गंभीर चोट लगी जिन्हें जिला अस्पताल में गंभीर अवस्था में भर्ती कराया गया है। जहां उपचार चल रहा है। दरअसल पूरा मामला जिला मुख्यालय के समीपी ग्राम उपनी का हैए जहां सीधी-सिंगरौली मार्ग पर तेज रफ्तार दो बाइक आपस में टकरा गएए जिसकी वजह से हादसे में तीन लोगों को गंभीर चोंट लगी जिन्हें जिला अस्पताल में 108 एंबुलेंस से भर्ती कराया गया। यूथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के द्वारा एंबुलेंस वाहन को हादसे की सूचना दी गई और सभी घायल व्यक्तियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरे मामले को लेकर अस्पताल चौकी पुलिस के द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध करते हुए विवेचना की जा रही है और आगे की कार्यवाही में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस द्वारा बताया गया कि तेज रफ्तार की वजह से यह हादसा हुआ है।

आवारा पशुओं से फसल बचाने किसान कर रहे रतजगा

सड़कों में आवारा गौवंशों के चलते हो रहे सड़क हादसे

पालतू गौवंशों को भी आवारा छोंड़ रहे पशु पालक

जागरण, सीधी

खरीफ सीजन में बोनी के बाद खेतों में खड़ी फसलों को आवारा गौवंशों से बचाने के लिए किसान गांव-गांव में रतजगा करने को मजबूर हो रहे हैं। हालात यह है कि जो आवारा गौवंश दिन में मुख्य सड़कों पर विचरण करते नजर आते हैं शाम ढ़लते ही वह अपनी खुराक की तलाश में गांवों की ओर रुख कर लेते हैं। ऐसा ही एक नजारा बुधवार की रात करगिल गांव में कैमरे में कैद हुआ। जहां आवारा पशुओं के झुंड को खेतों से दूर करने के लिए सड़क में एक महिला दौड़ती हुई नजर आई। इस तरह का नजारा गांवों में अब आम होने लगा है। करगिल क्षेत्र के किसानों ने बताया कि दिन होता है तो यहां के आवारा गौवंश तेंदुआ मुख्य मार्ग के आसपास चले जाते हैं और शाम ढ़लने के बाद गांव की ओर रुख कर लेते हैं। दरअसल कृषि सीजन शुरू होते ही आवारा गौवंशों के चलते किसानों की परेशानियां बढ़ जाती है। हालात यह है कि फसलों को बचाने के लिए किसानों को दिन एवं रात को खेतों की रखवाली करने की मजबूरी बन जाती है। वहीं आवारा गौवंशों का जमावड़ा दिन-रात सड़कों में होने के कारण सड़क हादसे भी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। जिले में आवारा छोड़े गए गौवंश सडकों को ही अपना ठिकाना बनाने के लिए मजबूर हैं। पालतू गौवंशों को मालिक ही सडकों पर आवारा छोड़ देते हैं। पशुओं के दुर्घटना या मृत होने पर मालिक सामने आ जाते हैं। खरीफ कृषि सीजन में आवारा पशुओं ने किसानों की भारी मुसीबतें बढ़ा दी है। दरअसल जिले में आधा सैकड़ा गौशालाओं का संचालन किया जा रहा है। लेकिन इनमें इतनी क्षमता नहीं है कि सभी आवारा पशुओं को रखा जा सके। अपने पशुओं को आवारा छोडने वाले मालिकों पर कार्यवाही के निर्देश भी हवा में उड़ रहे हैं। नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों को आवारा घूमने वाले पशुओं को गौशालाओं में भेजने के निर्देश तो हैं लेकिन जिम्मेदार इन पर कोई अमल करने की जरूरत नहीं समझते। जानकारों का कहना है कि नगरों और गांवों में कांजी हाउस का संचालन जबसे बंद हुए हैं यह समस्या और भी गंभीर रूप धारण कर चुकी है। कांजी हाउस की जमीनों, चरनोई की भूमियों का उपयोग पशुओं की जगह इंसानों के लिए करने की यह सुविधा बंद हुई और पशु ठिकाना तलाशने के लिए सडकों पर आने लगे हैं। पुराने समय की व्यवस्था को विकास की भेंट चढ़ाने से यह परिणाम सामने आ रहे हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि जब तक चरनोई की भूमि रही, कांजी हाउस की व्यवस्था संचालित रही तब तक बारिश में भी पशु सडकों पर नहीं आते थे। बारिश में पशुओं को जंगल या गांव के पास चरनोई भूमि पर रखकर चौमासा काटते थे। आवारा पशुओं को कांजी हाउस में बंद कराने की व्यवस्था थी जिससे उनके मालिक निश्चित राशि चुकाकर अपने घर ले जाते थे।

दुर्घटना से आवारा मवेशियों की हो रही मौतें

सड़कों में आवारा गौवंशों के जमावड़ा एवं बैठने के कारण सड़क हादसों की संख्या भी तेजी के साथ बढ़ रही है। सड़क हादसों में वाहन सवार जहां घायल हो रहे हैं वहीं दुर्घटनाओं में आवारा मवेशियों की मौतें भी हो रही हैं और गंभीर रूप से घायल भी हो रहे हैं। उक्त स्थिति से प्रशासन भलीभांति वाकिफ है फिर भी इस पर लगाम लगाने की जरूरत गंभीरता के साथ नहीं की जाती। जिले में लगभग डेढ़ सौ गांव हाइवे के किनारे बसे हैं। इन गांवों के पशु ही सडकों पर बैठते हैं। करना केवल इतना है कि पशुओं को गांव में ही रखने के लिए पंचायत के माध्यम से प्रबंध किए जा सकते हैं। खाली जमीनों को घेरकर बाड़े बनाकर वहां पशुओं को रखा जा सकता है। वहीं चारे के प्रबंध किए जा सकते हैं। इस व्यवस्था में सरकार के ऊपर ज्यादा व्यय का भार भी नहीं बढ़ेगा। फिर भी प्रशासन आवारा पशुओं से होने वाली समस्याओं को गंभीरता से दूर करने के प्रयास नहीं करता। खेती-किसानी के सीजन में किसान भी आवारा पशुओं से होने वाली नुकसानी को लेकर काफी हो-हल्ला करते हैं लेकिन इस कड़वी सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि जो आवारा पशु आज सडकों में जमे हुए हैं उसके जिम्मेदार भी किसान ही हैं। उनके द्वारा अपने पालतू पशुओं को बोझा मानकर आवारा छोड़ दिया गया है। यही आवारा पशु बनकर कृषि सीजन में किसानों के लिए बड़े सिर दर्द बने हुए हैं।

सीमेंट दिलाने के नाम पर नकदी, मोटर साइकिल, मोबाइल लेकर युवक फरार

जागरण, कटनी। उमरियापान थाना क्षेत्र के घुघरी गांव निवासी एक युवक को ढीमरखेड़ा में रहने वाले एक युवक ने सीमेंट दिलाने के नाम पर अपनी बातों में फंसाया और उसकी मोटर साइकिल, मोबाइल व नकदी लेकर चंपत हो गया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए युवक की तलाश की और उसे उमरिया जिले से पकड़कर न्यायालय में पेश किया है। उमरियापान थाना प्रभारी दिनेश तिवारी ने बताया कि घुघरी निवासी प्रमोद चौधरी पिता बनमाली चौधरी 32 साल दस दिन पूर्व ढीमरखेड़ा निवासी रामसजीवन बर्मन उर्फ शंकर बर्मन ने मोटर साइकिल में लिफ्ट ली थी। इसी दौरान रास्ते में उनका परिचय हुआ और प्रमोद ने रामसजीवन को उसके घर तक छोड़ा था। मंगलवार की सुबह प्रमोद को रामसजीवन रास्ते में मिला और उसने डीजल बिकवा देने की बात कही। प्रमोद ने इसको लेकर मना कर दिया। इस बीच प्रमोद ने सीमेंट लेने की बात की तो रामसजीवन ने नजदीक के एक पेट्रोल पंप में उसका ट्रक खड़े होने और सस्ते में सीमेंट दिलाने का झांसा दिया। जिसमें प्रमोद फंस गया। युवक ने बैंक से चार हजार रुपये निकाले और मोटर साइकिल से रामसजीवन को लेकर पेट्रोल पंप जाने को निकला। पुलिस ने आरोपित को उमरिया से पकड़ा लिए कोदवारी गांव के पास रोका। इस बीच उसने प्रमोद से चार हजार रुपये ले लिए और कंडक्टर से बात करने के लिए मोबाइल मांगा।

प्रमोद का मोबाइल लेकर उसने किसी से कोई बात की। साथ ही बात करने के बाद उसने प्रमोद से मोटर साइकिल की चाबी मांगते हुए कहा कि वह कंडक्टर से चर्चा करके दस मिनट में आता है। रामसजीवन उसकी मोटर साइकिल, मोबाइल व चार हजार रुपये लेकर चंपत हो गया। काफी देर तक जब वह नहीं लौटा तो प्रमोद ने घटना की जानकारी लोगों को दी और पेट्रोल पंप पहुंचे तो पता लगा कि वहां पर कोई सीमेंट का ट्रक हो नहीं खड़ा है। इसकी शिकायत उसने उमरियापान थाना में दर्ज कराई। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करते हुए रामसजीवन की खोजबीन शुरू की जिसमें उसके उमरिया जिले में होने की सूचना मिली। पुलिस ने दबिश देकर उमरिया से रामसजीवन को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से मोटर साइकिल, मोबाइल व नकदी जब्त करते हुए उसे बुधवार को न्यायालय में पेश किया है।

उमरा के लिए मुस्लिम श्रद्धालु साउदी अरब के लिए रवाना

जागरण, ब्यौहारी। ब्यौहारी विकास खंड से उमरा के मुस्लिम श्रद्धालुओं का जत्था ब्यौहारी से रवाना हुए यात्रा पर गए श्रद्धालुओ माला पहनाकर स्वागत किया गया उनके परिजन मुंबई तक छोड़ने गए हैं ब्यौहारी- नगर से छेत्र के वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय बशीर मोहम्मद की पत्नी , पत्रकार मों फाखिर चांद की मां जुबैदा मंसूरी सात दिनों की उमरा के लिए मक्का गई हैं उनको छोडने के लिए उनके पुत्र मोहम्मद सम्स मंसूरी,चंदा , राशिद मंसूरी, तौकीर मंसुरी,रोशन मुंबई गए हैं इसके अलावा सभी यात्रियों के परिजन भी छोड़ने मुंबई गए हैं उमरा के लिए गये यात्रियों को धूमधाम से बिदा किया गया मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष रमजान कादरी के नेतृत्व में सभी यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गए जबलपुर से मुंबई और मुंबई से जेद्दा के लिए फ्लाइट से सभी है हज यात्री मक्का पहुंचेंगे पूरी यात्रा 7 दिनों की होगी नगर जनों ने सभी यात्रियों के यात्रा के लिए मंगल कामना की है।

कटनी में माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन आज

कटनी। मुख्यमंत्री डा.मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में शनिवार 23 अगस्त को कटनी में भव्य माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन होने जा रहा है। इस कॉन्क्लेव में 2 हजार से अधिक प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। जिसमें प्रमुख निवेशक, उद्योगपति, नीति निर्माता, शोधकर्ता और शिक्षाविद शामिल होंगे। इस आयोजन का उद्देश्य राज्य के समृद्ध खनिज भंडारों का उपयोग करते हुए खनन क्षेत्र में नए निवेश और नवाचार को बढ़ावा देना है। मध्यप्रदेश तांबा, मैंगनीज, चूना पत्थर, बॉक्साइट, डोलोमाइट, मार्बल, बलुआ पत्थर और औद्योगिक खनिजों से भरपूर है। जो खनिज आधारित उद्योगों के लिए असीम संभावनायें प्रस्तुत करता है। अपनी रणनीतिक स्थिति और मजबूत औद्योगिक नेटवर्कों की वजह से मध्यप्रदेश जिम्मेदार और नवाचार आधारित खनन का एक तेजी से उभरता हुआ केन्द्र बन रहा है। कॉन्क्लेव में खनन अपशिष्ट को मूल्यवान संसाधनों में बदलने, खनिजों का उपयोग कर डाउनस्ट्रीम उद्योगों का विकास, पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए डिजिटल तकनीक का उपयोग, स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने पर चर्चा की जायेगी।

कॉन्क्लेव की मुख्य विशेषताएं : इस कॉन्क्लेव में खनन और प्रौद्योगिकी में शोध के लिए टेक्समाइन आईआईटी आईएसएम धनबाद और आईआईएसईआर भोपाल जैसे संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग बढ़ाने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के साथ भी एमओयू होगा। उद्योग विशेषज्ञ खनिज आधारित उद्योगों, बेनिफिशिएशन खनिज संवर्धन और उन्नत तकनीकों पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री निवेशकों के साथ वन टू वन बैठकें करेंगे, ताकि राज्य में निवेश के अवसरों को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा खनन क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप्स, खनिज संवर्धन संयंत्र और मशीनरी निर्माता कंपनियां भी इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दर्ज करा रही हैं। यह कॉन्क्लेव मध्य प्रदेश को देश में जिम्मेदार और टिकाऊ खनन के केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

चेक अनादृत होने की सूचना

राजेश कुमार पाण्डेय तनय श्री भगवानदास पाण्डेय ग्राम+पोस्ट वैसा तहसील हुजूर, रीवा (म.प्र.) का दिया हुआ चेक अगदृत हो गया जिसकी सूचना स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा गया जो आप नोटिस पत्र नहीं ले रहे हैं जिसकी यह सूचना है।

आवेदक
राजनिवास सिंह
(एडवोकेट)
जिला एवं सत्र न्यायालय
(नजदीक पत्थर का शेर)
जिला रीवा (म.प्र.)
मो.: 9827371275
RN-82754

मूलभूत सुविधाओं तक तुरंत पहुंच रहीं अध्यक्ष, वार्डो का पैदल निरीक्षण, कर्मचारियों को सख्त निर्देश

जागरण, कटनी। विजयराघवगढ़ नगर परिषद अध्यक्ष राजेश्वरी हरीश दुवे नगर की मूलभूत सुविधाएं दिलाने के लिए समस्या तक पैदल पहुंच रही और तुरंत निराकरण कर रही। नगर परिषद कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि नगर परिषद अध्यक्ष राजेश्वरी हरीश दुवे नगर की मूलभूत सुविधाओं पर विशेष सख्ती रख रही है। नगर की समस्या की जानकारी लगे तो वह खुद पैदल पहुंच जाती है सभी नगर वासियों के बीच जाकर समस्या की जानकारी लेती है। और नगर परिषद के कर्मचारियों की टीम को तुरंत निराकरण करने के निर्देश प्राप्त होते हैं। इसी तारतम्य में आज नगर परिषद अध्यक्ष राजेश्वरी हरीश दुवे वार्ड नंबर 13 की टंकी के पास चल रहे सुधार कार्यो की समीक्षा की तथा समय पर कार्य करने के निर्देश किया। साथ ही वार्ड न 9 में भी लोगों की शिकायतों पर वार्ड का निरीक्षण करने पहुंची श्रीमती दुवे इस दौरान वार्ड पार्षद व वार्ड रहवासियों ने नगर परिषद अध्यक्ष की जमकर तारीफ की ।कहा गया कि पहली बार कोई नगर अध्यक्ष घर-घर जाकर लोगों से समस्या पूछकर उनकी समस्याओं का निराकरण कर रही हैं, वार्ड पार्षद ने धन्यवाद देते हुए कहा कि न पार्टी वाद है न कोई भेदभाव नगर विकास के पथ पर राजेश्वरी हरीश दुवे पूरी इमानदारी के साथ कार्य कर रही है ऐसी ऊर्जावान अध्यक्ष मिलना सौभाग्य की बात है।

नाम सुधार सूचना

मैं सुरेश कुमार कोल पिता श्री सुखई कोल ग्राम पोस्ट ढेरा तहसील मउगंज जिला रीवा म.प्र. का निवासी हूँ व शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरा ड्राइविंग लायसेंस दिनांक 23.11.2011 को बना है, जिसमें मेरा नाम बबलू कोल पिता सुखई कोल निवासी ग्राम पोस्ट ढेरा तहसील मउगंज जिला रीवा दर्ज है, जबकि मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में मेरा नाम सुरेश कुमार कोल पिता श्री सुखई कोल निवासी ग्राम कूँड़ी पोस्ट ढेरा तहसील मउगंज दर्ज है। मेरे ड्राइविंग लायसेंस में मेरा नाम मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड के अनुसार सुरेश कुमार कोल पिता श्री सुखई कोल निवासी ग्राम कूड़ी पोस्ट ढेरा तहसील मउगंज जिला रीवा दर्ज / सुधार कर दिया जावे एवं पढ़ा, लिखा व जाना जावे।

RN-82753 सुरेश कुमार कोल

उत्तर मध्य रेलवे

निविदा सूचना संख्या एवं दिनांक : DY-CE-C-II-JHS-2025-05 dated 21.08.2025

ई-निविदा सूचना

उप मुख्य इंजीनियर/निर्माण-।।/झाँसी, भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा, निविदा बंद होने की दिनांक 15.09.2025 को 15:00 बजे तक आमंत्रित करते है।

निविदा संख्या : DY-CE-C-II-JHS-2025-05	**अनुमानित लागत** : Rs. 1,96,43,000.00
कार्य का नाम : "JHS-Bina तृतीय लाइन परियोजना के संबंध में JLN-DUA खंड और AGD यार्ड में सेस के साथ गिट्टी की आपूर्ति"।	
धरोहर राशि : Rs. 2,48,200.00	**वैधता की अवधि** : 60 दिन
कार्य पूर्ण होने की अवधि : 09 माह हार्वेस्ट एवं मानसून सहित।	
निविदा बंद होने का दिनांक व समय : 15.09.2025 को 15:00 बजे।	

नोट : पूर्ण विवरण एवं निविदा की प्रस्तुति करने के लिए भारतीय रेल की वेबसाइट **http://www.ireps.gov.in** का अवलोकन करें। **1510/25 (AS)**

North central railways www.ncr.indianrailways.gov.in @CPRONCR

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड सिंगरौली (म.प्र.)

नि.आ.सू.क्रं 91-93/व.ले.लि./का.यं./लो.स्वा.या./खण्ड/सिंगरौली/2025 दिनांक 12.08.2025

पता-विजय बंधु पेट्रोल पम्प के पास, ई-मेल eephedsin@rediffmail.com

प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना

निम्न कार्यो हेत निविदा का आन लाईन वेबसाइट http://www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की गई है। आन लाइन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 26.08.2025 सायं 17:30 बजे तथा निविदा खुलने की तिथि 27.08.2025 साय 17:30 बजे है। निविदा मे संशोधन की स्थिति मे वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उक्त वेबसाईट पर देखी जा सकती है।

Name of work:- Renovation of "Piped Water Supply Schemes Under Jal Jeevan Mission" of at Block Waidhan Distt Singrauli (M.P.)

S. N	NIT No.	Tender ID	Block	PAC (Rs. In Lakhs)	E-EMD in Rs.	Cost of Tender in Rs.	No. of Calls
1	91/2025-26	2025_PHED_443840_1	Waidhan	276.63	276630.00	15000.00	1st Call
2	92/2025-26	2025_PHED_443841_1	Waidhan	242.85	242850.00	15000.00	1st Call
3	93/2025-26	2025_PHED_443842_1	Waidhan	269.33	269330.00	15000.00	1st Call

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
सिंगरौली (म.प्र.)

G-17569/25

मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के परिवहनकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन

कटनी। मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना के तहत पीडीएस का परिवहन कार्य कर रहे समस्त परिवहनकर्ताओं ने कलेक्टर कार्यालय में एक पत्र के माध्यम से प्रशासन से अपील की है कि उनके लंबित बिलों का शीघ्र भुगतान किया जाए। परिवहनकर्ताओं का कहना है कि अप्रैल 2025 तक उनका बिल भुगतान समय पर हो जाता था लेकिन जून 2025 से अब तक तीन माह का बकाया भुगतान नहीं किया गया है जिससे उन्हें वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। नियमानुसार प्रत्येक माह के अंत तक बिल भुगतान होता था लेकिन अब आवंटन की प्रक्रिया में देरी हो रही है जिससे गाड़ियों के लिए आवश्यक बीमा, फिटनेस और अन्य खर्चों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। साथ ही उन्हें छोटे मार्गों के लिए अतिरिक्त गाड़ियाँ लगाने की आवश्यकता हो रही है जिसके कारण कार्य में और देरी हो रही है।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ ने काला दिवस मनाते हुए प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन

ब्यौहारी। शहडोल जिले के ब्योहारी विकास खंड में ब्लॉक अध्यक्ष शैली मिश्रा के नेतृत्व में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने तहसील कार्यालय पहुंचकर माननीय प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की समस्याओं के निराकरण के लिए मांग की गई जिसमें बड़ी संख्या कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने काले कपड़े पहने कर नारेबाजी करते हुए जल्द से जल्द समस्याओं को निराकरण के लिए बीस सूत्रीय मांगों पर विचार करने की मांग की गई इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष शैली मिश्रा ने बताया कि जल्द से जल्द समस्याओं का निराकरण किया जाय अन्यथा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी समस्त जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।

उत्तर मध्य रेलवे

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिये तथा उनकी ओर से **वरि. मंडल यॉंत्रिक इंजीनियर (डीजल), उत्तर मध्य रेल, झाँसी** द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिये ऑनलाईन (ई-टेन्डरिंग) के माध्यम से खुली निविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा सं.: झाँसी-एम-डीजल-डब्ल्यू.सी.-टी-03-25-26 आर.टी.

कार्य का विवरण: एच.एच.पी. लोकोमोटिवों के चालक कैब के लिए एअर कण्डीशनिंग उपकरण की मरम्मत।

निविदा मूल्य	बयाना राशि	निविदा प्रपत्र कीमत	निविदा बंद होने की तिथि
₹ 28,49,051.90/-	₹ 57,000/-	₹ 0.00/-	22.09.2025

समापन अवधिः 12 माह, निविदाकार निविदा दिनांक **22.09.2025** को **15.00** बजे तक ऑनलाईन जमा कर सकेंगे। पूर्ण विवरण एवं निविदा को प्रस्तुति करने के लिये भारतीय रेल के वेबसाईट http://www.ireps.gov.in पर देखें। **1508/25 FA**

North central railways @CPRONCR www.ncr.indianrailways.gov.in

COMPUTER PROFICIENCY CERTIFICATION TEST
Madhya Pradesh State Electronics Development Corporation Limited
Exam Registration Opens

म.प्र. शासन द्वारा सरकारी रोज़गार हेतु आवश्यक CPCT स्कोर कार्ड

राज्य शासन के विभिन्न विभागों एवं कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कम्प्यूटर दक्षता/कौशल प्रमाणीकरण हेतु **संविदा/नियमित नियुक्तियों** के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार (CPCT पोर्टल पर उपलब्ध) सूचना प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर क्षेत्र में कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा (CPCT) का स्कोर कार्ड प्राप्त करना अनिवार्य है।

परीक्षा तिथि : 26 - 27 एवं 28 सितम्बर 2025 **पंजीयन तिथि : 25 अगस्त 2025 से 08 सितम्बर 2025**

आवेदन पत्र में संशोधन करने की तिथि : 10 सितम्बर 2025 से 12 सितम्बर 2025

- CPCT परीक्षा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, सतना में आयोजित की जाएगी।
- CPCT नियम पुस्तिका में आवेदन फॉर्म में सुधार हेतु नियम उपलब्ध कराए गए हैं।
- CPCT नियम पुस्तिका में निःशक्तजनों से संबंधित नियम उपलब्ध कराये गए हैं तथा लेखक की सुविधा हेतु आवेदन का प्रारूप CPCT पोर्टल पर उपलब्ध है।
- CPCT परीक्षा सम्बन्धी समस्त जानकारी/विवरण एवं नियम पुस्तिका तथा आगामी परीक्षाओं का प्रस्तावित कैलेंडर CPCT पोर्टल (**www.cpct.mp.gov.in**) पर उपलब्ध है।
- मूल (Original) फोटोयुक्त पहचान पत्र लाने पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
- अभ्यर्थी को दोनों अनुभाग (कम्प्यूटर एवं टाइपिंग) में सम्मिलित होना अनिवार्य है।

परीक्षा एवं पंजीयन की सुविधा अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों भाषा में उपलब्ध होगी। आवेदकों को परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन ही भरने होंगे। आवेदक अपना पंजीयन MP-Online के Kiosks से भी कर सकते हैं।

मुख्य महाप्रबंधक
मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (MPSeDC)
म.प्र. माध्यम/121694/2025 **स्टेट आई टी सेंटर, 47-A, अरेरा हिल्स भोपाल-462011**

Note : MPSeDC द्वारा प्रदेश में किसी भी संस्था को CPCT प्रशिक्षण हेतु अधिकृत नहीं किया गया है।

कन्या महाविद्यालय में पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमा निर्माण करने कार्यशाला का आयोजन

कटनी। शासकीय कन्या महाविद्यालय में प्राचार्य डॉ.चित्रा प्रभात के मार्गदर्शन में इको क्लब के तत्वावधान में ग्रीन गणेश जागरूकता विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना और छात्राओं को पर्यावरण अनुकूल गणेश प्रतिमा निर्माण के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम के प्रथम चरण में इको क्लब पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को गणेश मूर्ति निर्माण की पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। विशेषज्ञ डॉ.दिलीप चक्रवर्ती ने प्राकृतिक और जैविक सामग्रियों के उपयोग पर जोर देते हुए पारंपरिक और पर्यावरण के लिए हानिकारक सामग्रियों के दुष्प्रभावों पर प्रकाश डाला। इस सत्र ने छात्राओं में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वेबिनार के पश्चात महाविद्यालय में एक कार्यशाला आयोजित की गई जिसमें छात्राओं ने प्राकृतिक सामग्रियों जैसे मिट्टी, हल्दी, पीपल के पत्ते और सुपारी का उपयोग करके इको फ्रेंडली गणेश प्रतिमाएँ बनाईं। प्राचार्य डॉ.चित्रा प्रभात ने छात्राओं का मार्गदर्शन करते हुए बताया कि ऐसी प्रतिमाएँ पर्यावरण के लिए अनुकूल होती हैं क्योंकि ये आसानी से विघटित हो जाती हैं और जल प्रदूषण को रोकती हैं। इस गतिविधि ने छात्राओं में रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति उत्साह को बढ़ाया।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्ड सिंगरौली (म.प्र.)

नि.आ.सू.क्रं94/व.ले.लि./का.यं./लो.स्वा.या./खण्ड/सिंगरौली/2025 दिनांक 14.08.2025

पता-विजय बंधु पेट्रोल पम्प के पास, ई-मेल eephedsin@rediffmail.com

प्रथम निविदा आमंत्रण सूचना

निम्न कार्यो हेत निविदा का आन लाईन वेबसाइट http://www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की गई है। आन लाइन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28.08.2025 सायं 17:30 बजे तथा निविदा खुलने की तिथि 29.08.2025 साय 17:30 बजे है। निविदा मे संशोधन की स्थिति मे वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उक्त वेबसाईट पर देखी जा सकती है।

Name of work:- Appointment of Third Party Inspection Agencies (TPIAs) for inspection of works to be implemented under Jal Jeevan Mission (JJM) in District Singrouli under Rewa Circle.

S. N	NIT No.	Tender ID	District	PAC (Rs. In Lakhs)	E-EMD in Rs.	Cost of Tender in Rs.	No. of Calls
1	94/2025-26	2025_PHED_444520_1	Singrauli	93.01	93010.00	10000.00	1st Call

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड
सिंगरौली (म.प्र.)

G-17568/25

सूचना

जागरण पब्लिकेशन प्रा. लि. किसी तृतीय पार्टी के उत्पादकों वस्तुओं या सेवाओं का समर्थन नहीं करती है और न ही किसी तृतीय पार्टी के विज्ञापनों में छपी किसी जानकारी की सच्चाई या विश्वसनीयता की पुष्टि करती है। जागरण पब्लिकेशन प्रा. लि. पाठकों को प्रेरित करती है कि वे ऐसे किसी भी विज्ञापनदाता के साथ कोई भी लेन-देन करने की कार्रवाई से पहले उचित व जरूरी समझे जाने वाली जांच पड़ताल कर लेवे।

जमीन बेचना है

पद्मधर कॉलोनी के पीछे नदी से लगा व 11,500 वर्गफिट फार्म हाउस मात्र 1200 रूपये वर्गफिट बेचना है। सम्पर्क करें। पंकज सिंह मो. 9753664665
आरएन-जीएमसर(23/8)

शीघ्र आवश्यकता

रीवा शहर में एक अनुभवी चालक (5 वर्ष का अनुभव) की आवश्यकता है रहने की सुविधा उपलब्ध वेतन 10000 से 13000/- रूपये एवं घरेलू कार्य हेतु एक नौकर की आवश्यकता है। मिलने का समय सुबह 10:00 से 5:00 बजे तक। मो. 9425735577, 8770082649
आरएन-84502 (24/8)

लोन

लोन फाईनेंस सर्विस रीवा संभाग में विशेष लोन व्यवस्था मुद्रा लोन, आधार कार्ड, मार्कशीट, पर्सनल, कृषि लोन और सभी प्रकार के लोन 2% ब्याज 50% छूट (एजेंट आमंत्रित) संपर्क - 8962086944

मैरिज गार्डन किराये से देना है

कोष्ठा रीवा में मैरिज गार्डन किराये से देना है। इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें:- मो. नं. 6260806864
आरएन. 84240 (29/8)

कार्यालय अध्यक्ष, काउंसलिंग समिति एवं आयुक्त तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

टैगोर छात्रावास क्रमांक-T2, प्रथम तल, श्यामला हिल्स, दूरदर्शन रोड, भोपाल-462002

ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2025-26 (C-17)

संस्थागत प्राथमिकता सीटों के अंतर्गत प्रवेश
(INSTITUTIONAL PREFERENCE SEATS)
सत्र 2025-26

संस्थागत प्राथमिकता सीटों (Institutional Preference Seats) के लिये काउंसलिंग उन संस्थानों में आयोजित होगी जिन्होंने इन सीटों के लिये सहमति पत्र के साथ आवेदन किया था। संस्थागत प्राथमिकता सीटों के अंतर्गत AICTE/COA द्वारा स्वीकृत प्रवेश क्षमता के 10 प्रतिशत स्थानों तक ही प्रवेश की कार्यवाही निम्न समय सारणी अनुसार की जावेगी।

पाठ्यक्रम	ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	काउंसलिंग अवधि
बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी (B.Tech.)	01.09.2025 से 15.09.2025 सायं 5:30 बजे तक	दिनांक 09.09.2025 एवं सीटें रिक्त रहने पर दिनांक 15.09.2025 रात्रि 11:45 तक
बैचलर ऑफ मैनेजमेंट (BBA)	01.09.2025 से 15.09.2025 सायं 5:30 बजे तक	दिनांक 09.09.2025 एवं सीटें रिक्त रहने पर दिनांक 15.09.2025 रात्रि 11:45 तक
बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर (B.Arch.)	25.08.2025 से 30.08.2025 सायं 5:30 बजे	दिनांक 28.08.2025 एवं सीटें रिक्त रहने पर दिनांक 30.08.2025 रात्रि 11:45 तक

- संस्थागत प्राथमिकता सीटों पर प्रवेश के लिये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात, उम्मीदवार को इच्छित संस्था में स्वयं उपस्थित होकर प्रवेश की कार्यवाही करनी होगी।
- संस्थागत प्राथमिकता सीटों के लिये उपलब्ध संस्थानों की सूची, प्रवेशित अभ्यर्थियों से लिये जाने वाले शिक्षण शुल्क की जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- प्रवेश नियम, समय-सारणी, अभ्यर्थियों के लिये महत्वपूर्ण निर्देश, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची वेबसाइट पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- **काउंसलिंग वेबसाइट dte.mponline.gov.in पर उपलब्ध है।**
- **संपर्क : 0755-6720205, 2660441**
- **ई-मेल : dte.helpcenter@mp.gov.in**

अतिरिक्त संचालक
म.प्र. माध्यम/121697/2025 **तकनीकी शिक्षा संचालनालय, मध्यप्रदेश**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय रीवा खंड रीवा (म.प्र.)

निविदा सूचना क्र.11/25-26/ब.ले.लि./का.यं./लो.स्वा.यॉ./25, रीवा, दिनांक 18.08.2025

ई-टेण्डरिंग निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से ऑन लाइन निविदायें एपेन्डिक्स 2.10 में प्रतिशत दर पर प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, भोपाल की नलकूपों के खनन एवं अन्य कार्य से संबंधित दिनांक 03.07.2018 से प्रभावशील एकीकृत दर सूची एवं निविदा सूचना जारी होने के दिनांक तक किए गए समस्त संशोधनों के आधार पर केन्द्रीयकृत नवीन पंजीयन के तहत लोक निर्माण विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से निविदा ऑन लाइन टेण्डर प्रक्रिया के तहत आमंत्रित की जाती है।

ऑन लाइन निविदा पब्लिशिंग का दिनांक 21.08.2025 डाक्यूमेन्ट डाउन लोड/टेण्डर फार्म कय प्रारम्भ तिथि 21.08.2025 टेण्डर फार्म कय की अंतिम तिथि 04.09.2025 बिड सबमिशन प्रारम्भ का दिनांक 21.08.2025 एवं बिड सबमिशन का अंतिम तिथि 04.09.2025 को सायं 5.30 बजे तक निर्धारित हैं। Manadatory 'A' & Financial bid Open का दिनांक 08.09.2025 को अपरान्ह 3.30 बजे निर्धारित हैं।

(2) उक्त निविदा आमंत्रण सूचना विभागीय वेवसाइट (http//www.mptenders.gov.in) पर प्रदर्शित है।

(3) निविदाएँ निर्धारित तिथि दिनांक 08.09.2025 को खोली जायेंगी।

(4) **कार्य का विवरणः-**
रीवा जिले के विकासखण्ड रीवा, रायपुर, सिरमौर एवं जवा के विभिन्न ग्रामों की योजनाओं में जल जीवन मिशन के तहत पुनरीक्षित डी.पी.आर अन्तर्गत उच्चस्तरीय टंकी निर्माण, सम्पवेल निर्माण, ट्यूबवेल पर आधारित रेट्रोफिटेड पाइप जलापूर्ति का निर्माण, निष्पादन, सबमर्सिवल मोटर पंप की स्थापना, कियाशील घरेलू नल कनेक्शन, 90 दिवस के ट्रायल रन एवं कमिशनिंग आदि समस्त कार्य सामग्री एवं लेबर सहित ।

ई-टेण्डर नं.	योजना का नाम	विकास खण्ड	कार्य की अनु. लागत (रु. लाख में)	प्रतिभूति राशि रु. में	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
2025_PHED_445078_1	खजुहा, मड़वा, बैजनाथ, सोनरा, कोठी, खौर, रीठी, बहुरीबाँध, बांसा, बिड़वा, लक्ष्मणपुर	रीवा	442.34	442340.00	15000.00	9 माह (वर्षा ऋतु सहित)
2025_PHED_445079_1	विकासखण्ड-जवा, कसियारी, चौखण्डी, जवा, पटेहरा, रघुनाथपुर (दोंदर), सितलहा, रघुनाथपुर (केचुहा) विकासखण्ड-सिरमौर, रिमारी, हिनौता, कपसा, बेला, लैनबधरी, मौहरा, तिघरा, डढ़िया	जवा/ सिरमौर	422.74	422740.00	15000.00	9 माह (वर्षा ऋतु सहित)
2025_PHED_445080_1	इटार, बड़ागाँव सिलचट टोला, लोही, हरदुआ, नर्रहा, सेमरी कला, धवैया-291, पलिया-350, महुली, महगना, पलिया -349, कोलईया, कसई, जलदर, बंधवा, रमपुरवा, बरयाटोला, दुअरा-274, दुअरा-275, महिलया, हटावा, मानपुर	रायपुर	315.89	315890.00	15000.00	9 माह (वर्षा ऋतु सहित)

निविदा सूचना से संबंधित अन्य विस्तृत जानकारी विभागीय वेवसाइट (http//www.mptenders.gov.in) पर प्रदर्शित है।

कार्यपालन यंत्री
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड,
रीवा (म.प्र.)

G-17575/25

निर्धारित किए गए लक्ष्य के अनुसार वार्ड प्रभारी राजस्व वसूली किया जाना सुनिश्चित करें : आयुक्त

नगर निगम आयुक्त ने की राजस्व वसूली के प्रगति की समीक्षा

जागरण, बैढ़न। नगर निगम आयुक्त श्रीमती सविता प्रधान के द्वारा आज निगम सभागार में बैठक आयोजित कर राजस्व वसूली के प्रगति की समीक्षा की गई। निगमायुक्त श्रीमती प्रधान के द्वारा निर्देश दिया कि सभी राजस्व अधिकारी शासन के मंशानुसार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार राजस्व वशूली किया जाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा मेरे द्वारा एक दिन छोड़कर व्हीसी के माध्यम से राजस्व वशूली कार्य की प्रति करे। ताकि निर्धारित समयानुसार शत प्रतिशत राजस्व वसूली का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। उन्होंने राजस्व प्रभारियों को निर्देश दिये कि अपने अपने अपने वार्डो में जाकार प्रति दिन वसूली करना सुनिश्चित करें एवं वसूली की प्रगति की जानकारी से राजस्व अधिकारी को अवगत कराये। उन्होंने कहा कि बड़े बकायादारों को राजस्व कर जमा करने के लिए नोटिस जारी करे इसके बावजूद भी जिनके द्वारा अपना कर निगम कोष में जमा नहीं किया जाता तो उनके विरूद्ध कुर्की की कार्यवाही करें। उन्होंने निर्देश दिया कि निगम से बिना भवन अनुज्ञा नये बन रहे मकानों को चिन्हित कर संबंधित भवन स्वामी के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि सम्पत्ति कर दुकान किराया ए जल करए भू भाटक सहित निगम के अन्य करो निर्धारित समय सीमा में शत प्रतिशत वसूली किया जाना सुनिश्चित करें ताकि निगम के आय में वृद्धि हो सके। साथ ही निर्देश दिया गया कि आगामी 13 सितम्बर को आयोजित होने वाले लोक अदालत के पहले बकायादारों को नोटिस जारी कर तथा उन्हें लोक अदालत में मिलने वाली छूट के संबंध में अवगत करायें। निगमायुक्त श्रीमती प्रधान ने प्रधानमंत्री आवास निर्माण की समीक्षा कर वार्ड प्रभारियो को निर्देश दिए कि लिंटर लेवल तथा छत लेवल के अपूर्ण आवासों को पूर्ण करने हेतु संबंधित हितग्राहियो से मिलकर उन्हें आवास निर्माण का कार्य पूर्ण करने के लिए समझाईस दें साथ यह भी अवगत कराये कि आवास निर्माण में देरी करने पर राशि वशूल करने के लिए नोटिस जारी की जायेगी। उन्होंने आधार से समंग्र ई केवायसी करने की समीक्षा करते हुयें असंतोष जाहिर करते हुये निर्देशित किया कि नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक का शत प्रतिशत ई केवायसी पूर्ण कराये इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दास्त नही की जायेगी। उन्होने कहा कि इस कार्य समीक्षा भी मेरे द्वारा व्हीसी के माध्यम से की जायेगी। निगमायुक्त ने कहा कि हमारा कार्य नगरीय क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक नागरिको को मूलभूत सुविधाए उपलंब्ध कराने के साथ ही शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करना है। उन्होंने कहा कि निगम कार्यालय में आने वाले हितग्राहियो से उनकी समस्याओं को जाने उन्हें बैठने के लिए कहें तथा यह भी बतायें कि उनके द्वारा कराये जाने वाले कार्य में कितना समय लगेगा। बैठक के दौरान निगम के कार्यपालन यंत्री प्रदीप चड़ार उपायुक्त आरपी बैस सहित समस्त वार्ड प्रभारी कम्प्युटर ऑपरेटर उपस्थित रहे।

नालियों की सफाई कराने के साथ ही उनमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करायें : रूपाली द्विवेदी

सहायक आयुक्त ने देखी मटवई बस्ती की सफाई व्यवस्था

जागरण, बैढ़न। नगर पालिक निगम सिंगरौली की सहायक आयुक्त व नोडल अधिकारी स्वच्छता श्रीमती रूपाली द्विवेदी ने आज अपने प्रातः भ्रमण में वार्ड क्र.36 मटवई बस्ती में की जा रही साफ सफाई व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई कार्य हेतु निर्देश दिए कि वार्ड की सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रखें नालियां जाम न हों इसके लिए नालियों की सफाई कराने के साथ ही उनमें कीटनशक दवाओं का छिड़काव कराये। सहायक आयुक्त ने कहा कि वार्डवासियों को भी प्रेरित करें वे अपने घर का कचरा, कचरा वाहन में ही डालें उन्होंने नवजीवन विहार का जोन की भी साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर अवाश्य निर्देश दिए। इस दौरान पार्षद प्रेम सागर मिश्रा सफाई निरीक्षण पवन बरोडे सहित सफाई कर्मी उपस्थित रहे।

ट्रेड लायसेंस लेकर सुगमता के साथ करें अपना व्यापार : उपायुक्त ननि

बैढ़न। सिंगरौली नगर पालिक निगम सिंगरौली के उपायुक्त आरपी बैस ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में व्यापार करने वाले सभी व्यावसाईयो को ट्रेड लायसेंस लेना अनिवार्य है। उन्होने बताया कि ट्रेड लायसेंस लेकर व्यापारी सुगमता से अपना व्यापार कर सकते हैं। तथा इससे उनके व्यापार को वैधता भी मिलती है। उपायुक्त श्री बैस ने कहा कि व्यापारी ट्रेड लायसेंस के लिए नगर निगम में आवश्यक दस्तावेज जिनमें स्वा प्रमाणित घोषणा पत्र शपथ पत्र स्थापना पंजीयन का प्रमाण पत्र किरायानामा सम्पत्तिकर की रसीद फर्म पंजीकरण प्रमाण पत्र आधार कार्ड की छाया प्रति तथा आवेदक तथा दुकान का फोटो निगम कार्यालय में प्रस्तुत कर सुगमता से ट्रेड लायसेंस प्राप्त कर सकते। उन्होनें नगरीय क्षेत्र में व्यावसाय कर रहे सभी व्यापारियों से आग्रह किया है कि निगम कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत कर ट्रेड लायसेंस लेकर ही अपना व्यवसाय करे इससे उनके व्यापार को वैधता भी मिलती है।

उत्तर मध्य रेलवे

सं. पी/आरएसके/सिथौली/पुनः नियुक्ति/यांत्रिक/उमरे दिनांकः 07.08.2025

अधिसूचना

विषयः सेवा की अनिवार्यताओं में संविदाकर्मी के रूप में सेवानिवृत रेलवे कर्मचारियों की पुनः नियोजन के सम्बन्ध में।

संदर्भः रेलवे बोर्ड का पत्र संख्या 2024/ई (जीआर) आई/38/1 दिनांक 29.08.2024 एवं 08.11.2024 और NCRPS No. 6377/2025 दिनांक 24.01.2025

रेलवे बोर्ड के संदर्भाधीन पत्र के अनुसार तथा सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली, ग्वालियर, भारतीय रेलवे (स्तर-2 से स्तर-8) से इच्छुक सेवानिवृत ग्रुप 'सी' अराजपत्रित कर्मचारियों से सेवाओं की आवश्यकताओं के मद्देनजर पुनः नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली, ग्वालियर/उमरे में सेवाओं की अनिवार्यता हेतु पुनः नियोजन के लिए इच्छुक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों से निम्नलिखित नियमों और शर्तों के साथ आवेदन मांगे जाते हैः-

(1) वेतन स्तर-02 से वेतन स्तर-08 में सेवानिवृत्त हुए गैर-राजपत्रित रेलवे कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय उनके द्वारा धारित मूल वेतन स्तर में उपलब्ध रिक्ति के समान पद के विरुद्ध पुनः नियोजित के लिए विचार किया जायेगा । (2) रेलवे बोर्ड के द्वारा जारी नियमानुसार आवेदक को आवेदित पद की चिकित्सा श्रेणी Cee Two and below में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। (3) पुनः नियोजित किए जा रहे सेवानिवृत्त कर्मचारी सुरक्षा संबंधी सेवानिवृत्ति योजना/सुरक्षा कर्मचारियों के लिए गारंटीकृत रोजगार हेतु उदारीकृत सक्रिय सेवानिवृति योजना (एलएआरएसजीईएसएस) / हटाए गए / बर्खास्त किए गए/अनिवार्य सेवानिवृत्त के अंतर्गत कवर नहीं किए गए होने चाहिए। (4) कर्मचारियों की उपयुक्तता/योग्यता का निर्धारण नामित समिति द्वारा किया जाएगा। (5) पुनः नियोजन हेतु कर्मचारी डीएआर/ सतर्कता मामलों से मुक्त होना चाहिए। (6) पुनः नियोजन अधिकतम 65 वर्ष तक होगी। (7) पुनः नियोजन सेवानिवृत्त कर्मचारियों का पारिश्रमिक, भते और अवकाश रेलवे बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के **दिनांक** 09.12.2020 के कार्यालय ज्ञापन संख्या **एफ. सं. 3-25/2020-ई.IIIA** के अनुसार होंगे, जो निम्नानुसार हैं:-

(अ) सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त वेतन से मूल पेंशन की कटौती करके अनुबंध अवधि के दौरान एक निश्चित मासिक राशि पारिश्रमिक के रूप में स्वीकार्य होगी। इस प्रकार निर्धारित पारिश्रमिक की राशि अनुबंध की अवधि के लिए अपरिवर्तित रहेगी। (ब) अनुबंध की अवधि के दौरान कोई वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और एचआरए की अनुमति नहीं दी जाएगी। (स) निवास और कार्य के स्थान के बीच आवागमन के उद्देश्य से परिवहन भत्ते के रूप में एक उचित और निश्चित राशि की अनुमति दी जाएगी हालांकि, सेवानिवृत्ति के समय उनकी पात्रता के अनुसार उन्हें आधिकारिक दौरे पर टीए/डीए, यदि कोई हो की अनुमति दी जा सकती है। (घ) सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए 1.5 दिनों की दर से सवेतन अनुपस्थिति अवकाश की अनुमति दी जा सकती है। एक कैलेंडर वर्ष से अधिक अवकाश संचय की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(8) पुनः नियुक्ति अवधि 01 वर्ष की अवधिं या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए होगी। हालांकि, पुनः नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारी के संतोषजनक प्रदर्शन के आधार पर, उसकी नियुक्ति की अवधि को एक वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाया जा सकता है। (9) आरआरबी से चयनित उम्मीदवारों और उस वक्त की रिक्तियों को देखते हुए शामिलहोने पर पुनः नियोजित कर्मचारियों को तुरंत हटा दिया जाएगा। (10) पुनः नियोजन कर्मचारियों को इकाई का प्रभारी नहीं बनाया जाएगा। पुनः नियोजन कर्मचारियों को वित्तीय और डी एंड एआर शक्तियाँ नहीं दी जाएंगी और उन्हें कोई सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए अधिकृत नहीं किया जाएगा। पुनः नियोजित कर्मचारी वित्तीय एवं अन्य मामलों पर अपने सुझाव नियमित या सेवारत कर्मचारियों/अधिकारियों कोदे सकते हैं। (11) केवल वे सेवानिवृत्त कर्मचारी जो अधिवर्षिता के कारण सेवानिवृत्त हुए हैं वो सेवानिवृत्त के समय धारित वेतन लेवल एवं सेवानिवृत्तिविभाग में ही आवेदन करने के पात्र हैं। (12) चयनित आवेदक को रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली में किसी भी शाखा परतैनात किया जा सकता है। (13) पुनः नियोजित कर्मचारियों को पुनः नियोजित होने की सभी शर्तों का पालन करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। (14) पुनः नियोजन का कार्य /आचरण असंतोषजनक पाया जाता है तो प्रशासन पुनः नियोजित कर्मचारियों की सेवा अवधि पूरी होने से पहले ही 7 दिन का नोटिस देकर समाप्त करने के लिए स्वतंत्र है। पुनः नियोजित सेवानिवृत्त कर्मचारी को अपनीसेवाएं समाप्त करने से पहले 7 दिन का नोटिस देना होगा। (15) अनुलग्नक 'अ' में दर्शाये पदों को सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों द्वारा भरे जाने का प्रस्ताव है। (16) पुनः नियुक्ति के उद्देश्य से, पुनः नियुक्ति चाहने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पिछले 5 एपीएआर को ध्यान में रखा जाना चाहिए और केवल उन पर विचार किया जाना चाहिए जिनकी सभी 5 वर्षों में 'अच्छी' ग्रेडिंग रही हो। (17) यह योजना निर्देश जारी होने की तिथि से 2 वर्ष की प्रारंभिक अवधि या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी। किसी सेवानिवृत्त कर्मचारी की नियुक्ति अवधि एक वर्ष या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रहेगी। हालाँकि, पुनः नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी के संतोषजनक कार्य-निष्पादन के आधार पर, उसकी नियुक्ति अवधि को एक वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाया जा सकता है। (18) कर्मचारियों की उपयुक्तता योग्यता का मूल्यांकन, पुनर्नियुक्ति से पहले,सुरक्षा और अन्य परिचालन आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, एक उपयुक्त स्तर की समिति द्वारा किया जाना चाहिए। उक्त समिति का स्तर महाप्रबंधक द्वारा तय किया जाएगा। पुनर्नियुक्ति वाले कर्मचारी डीएआर/सतर्कता मामलों से भी मुक्त होने चाहिए।

आवेदन कैसे करें:- योग्य एवं इच्छुक सेवानिवृत्त रेलवे अराजपत्रित कर्मचारी (वेतन स्तर-02 से स्तर- 08 तक) निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक 'बी' संलग्नक) में आवेदन को तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ जमा करें जैसे स्व-सत्यापित (i) पी.पी.ओ.की फोटोकॉपी (ii) सेवा प्रमाण पत्र (iii) पेंशन पहचान पत्र तथा (iv) हाल ही की पासपोर्ट साइज फोटो की 02 प्रतियां । आवेदन को कार्मिक शाखा, मुख्य कारखाना प्रबंधक, रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली, उत्तर मध्य रेलवे, ग्वालियर में जमा करने की अंतिम तिथि अधिसूचना प्रसारित होने की तिथि से 01 माह के अंदर तक भेजना आवश्यक है। यह अधिसूचना एनसीआर की वेबसाइट http://ncr.Indianrailways.gov.in पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक 'अ'

रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली, ग्वालियर/एनसीआर में पुनर्नियुक्ति हेतु पद प्रस्तावित :-

क्र. सं.	पद का नाम	श्रेणी	स्तर	आवश्यक स्टाफ/ पर्यवेक्षक की संख्या	योग्यता / अनुभव
1	सीनियर सेक्शन इंजीनियर	पर्यवेक्षक	7/8	2	मैकेनिकल/इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा, न्यूनतम 5 वर्ष का कॉइलिंग लाइन का अनुभव
2	जूनियर इंजीनियर	पर्यवेक्षक	6	2	
3	वरिष्ठ तकनीशियन	कॉइलिंग ऑपरेटर	6	21	मैकेनिकल / इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा, मशीन व इलेक्ट्रिकल विभाग में 5 वर्ष का अनुभव या किसी भी ट्रेड में आई.टी.आई. और मशीन व इलेक्ट्रिकल विभाग में 5 वर्ष का अनुभव
4	तकनीशियन-I	कॉइलिंग ऑपरेटर	5	20	
5	तकनीशियन-II	एंड ग्राइंडिंग ऑपरेटर	4	3	
6	कनिष्ठ लिपिक (जूनियर क्लर्क)	स्थापना	2	2	
	कुल			50	

अनुलग्नक 'ब'

मै, पदनाम.................. हेतु अक्त अधिसूचना में उल्लेखित नियमो और शर्तो पर मासिक पारिश्रमिक के आधार पर रेल स्प्रिंग कारखाना, सिथौली ग्वालियर के विभाग..................................(यांत्रिक/विद्युत) में पुनः नियुक्ति के लिए आवेदन करता/करती हूँ। मेरी सेवा का विवरण निम्नप्रकार है :-

1.	नाम (स्पष्ट अक्षरों में)	
2.	पिता का नाम	
3.	जन्म तिथि DD-MM-YYYY	
4.	सेवा निर्वृति की तिथि DD-MM-YYYY	
5.	65 वर्ष की आयु पूर्ण होने की तिथि	
6.	सेवानिवृति के समय पदनाम	
7.	ग्रेड पे/लेवल (नियमित पदोन्नति के अनुसार)	
8.	ग्रेड पे/लेवल (MACP के अनुसार) यदि हो तो	
9.	अंतिम अहरित वेतन (वेतनमान)	
10.	स्थान जहाँ से सेवानिवृत हुए है	1.मंडल का नाम............... 2. यूनिट...................... 3. विभाग......................
11.	सेवानिवृति होने की तरीका (कृपया उपयुक्त बॉक्स में टिक मार्क करे)	1.अधिवर्षिता 2.वीआरएस 3.लार्जेस 4. किसी अन्य तरीके से (निर्दिष्ट करें)
12.	पीपीओ संख्या और तिथि	
13.	संलग्नक (सत्यापित छायाप्रति संलग्न): (कृपया उपयुक्त बॉक्स में टिक मार्क करें)	हाँ नहीं
अ.	सेवा प्रमाण पत्र	
ब.	पेंशन पहचान पत्र	
स.	पेंशन भुगतान आदेश	
14.	मोबाइल नंबर	
15.	आधार कार्ड नंबर	
16.	पत्रचार के लिए पूरा पता (पिन कोड के साथ)	

मै घोषणा करता करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सत्य है और यदि यह गलत / झूठी पाई जाती है तो मै दंडात्मक कार्यवाई के लिए उत्तरदायी हूँ । मैं यह भी घोषणा करता करती हूँ कि मैंने अधिसूचना में निर्धारित नियमो और शर्तो को पढ़ लिया है और मैं उनका पालन करूँगा/करूँगी

हाल ही का पासपोर्ट आकर का रंगीन फोटो चिपकाएं एवं फोटो पर हस्ताक्षर करे

1507/25 (D)

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम..............................
स्थान.............................
दिनांक............................

North central railways @CPRONCR www.ncr.indianrailways.gov.in

सुहासिनी शिशु मंदिर गाहिलगढ़ में विद्यार्थीयों को स्कूल ड्रेस बैग पानी बॉटल्स का वितरण

एनटीपीसी एम्पलाइज द्वारा संचालित एनजीओ प्रगति संस्था की पहल

जागरण, विंध्यनगर। आज एनटीपीसी एम्पलाइज द्वारा संचालित एनजीओ प्रगति संस्था के द्वारा संचालित सुहासिनी शिशु मंदिर ग़ाहिलगढ़ में विद्यार्थीयों को स्कूल ड्रेस बैग पानी बॉटल्स का वितरण किया गया। इस अवसर पर एसके सिन्हा जीएम आपरेशन एवं एफ़एम ने बच्चों से बात करते हुए कहा कि जीवन में उद्देशों का तय होना जरूरी है और फिर उन्हीं तय उद्देश्यों के लिए पढ़ना और आगे बढ़ना जरूरी है। वहीं प्रगति संस्था के महासचिव तनुज कुमार ने बच्चों को मेहनत से पढ़ने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने को कहा। तनुज कुमार ने विद्यार्थियों के पठन.पाठन के लिए ऐसे आगे भी योगदान बनाए रखने की बात कही।बच्चों के बीच उन्हें मिले बैग बॉटल्स और स्कूल ड्रेस की खुशी देखने लायक थी। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष मनीष कुमार श्रीमती मालविका अवस्थी कृष्ण कुमार निशांत सिंह बी एल शर्मा उपस्थित रहे । एचआर विभाग से डीजीएम महताब आलम विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दी और बच्चों का उत्साह वर्धन किया। सुहासिनी शिशु मंदिर ग़ाहिलगढ़ स्कूल प्रगति संस्था द्वारा संचालित विद्यालय है।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मै बसन्ती पति राजेन्द्र सिंह उम्र 42 वर्ष ग्राम मुहेर पो. गोरबी तहसील व जिला सिंगरौली म.प्र. की निवासी हूं। मैं शपथ पूर्वक कथन करती हूं कि मुझ शपथकर्ती के माता सितलिया पति सुखराम सिंह की मृत्यु हो चूकी है जिनके मृत्यु के बाद विधिक वारिस पुत्री गण बसन्ती व बबनी मौजुद है। तथा हमारे बहन किसमतिया की मृत्यु अविवाहित अवस्था में हो चूकी है ऐसी स्थित में हमारे माता के विधिक वारिस पुत्री गण बसन्ती व बबनी के अन्य कोई वारिस पुत्र पुत्री मौजुद नहीं है। मै शपथ पूर्वक कथन करती हूं कि हमारे माता के जीवित विधिक वारिस प्रमाणित करने बाबत मैंने शपथ पत्र निष्पादित कराया है जो सही एवं सत्य है।

रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ,पश्चिम मध्य रेल

Railway Recruitment Cell,West Central Railway
आर.बी.-IV, 290, स्टेशन रोड, साउथ सिविल लाइंस, जबलपुर, 482001
RB-IV, 290, Station Road, South Civil lines, Jabalpur-482001
website:-www.wcr.indianrailways.gov.in

सांकेतिक विज्ञापन

अधिसूचना संख्या-01/2025 (एक्ट अप्रेंटिस)

पश्चिम मध्य रेल (सभी यूनिटों के लिए) पर वर्ष 2025-26 में अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए चयन हेतु 2865 स्लॉट के लिए अधिसूचना पश्चिम मध्य रेल की वेबसाइट पर दिनांक 20/08/2025 को जारी की गई है।विवरण निम्नानुसार है-

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि	30/08/2025
ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि एवं समय	29/09/2025 को 23:59 बजे तक

विस्तृत अधिसूचना एवं ऑनलाईन आवेदन करने की लिंक पश्चिम मध्य रेल की वेबसाईट www.wcr.indianrailways.gov.in www.wcr.indianrailways.gov.in {Path as follows- About us > Recruitment >Railway Recruitment Cell > Engagement of Act Apprentices > Engagement of Act Apprentices for 2025-26 > Notification No. 01/2025 (Act Apprentice)} पर उपलब्ध है।

दिनांक-20/08/2025 (हस्ता.)
स्थान-जबलपुर अध्यक्ष-रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर

स्वच्छ भारत अभियान, एक कदम स्वच्छता की ओर

समूह संचालक ने की किचन शेड बनवाने की मांग

मामला नगर परिषद क्षेत्र सरई का

जागरण, सरई। संकुल केंद्र सरई अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला खाड़ीटोला में मध्यान भोजन पकाने के लिए किचन सेट नहीं है। यह विडंबना है कि 27 वर्षों पुरानी विद्यालय में आज तक किचन शेड नहीं बन पाया है। मध्यान्ह भोजन पकाने वाली महिलाएं खुले में भोजन तैयार करने के लिए मजबूर हैं। बीते दिवस अनमोल स्व सहायता समूह के अध्यक्ष श्रीमती ममता पनिका ने अपनी समस्या मीडिया के सामने बयान की है। विद्यालय में बच्चों के लिए मध्यान्ह भोजन तैयार करने में काफी परेशानी हो रही है। बारिश का सीजन होने से इस समय खुले में भोजन तैयार करने में रोना आ जाता है। मध्यान भोजन बनाने वाली रसोइयों व समूह अध्यक्ष ने खाड़ी टोला विद्यालय में किचन शेड बनवाने की गुहार कलेक्टर से लगाई हैं।

आगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की नियुक्ति में मनमानी

देवसर। देवसर महिला एवं बाल विकास परियोंजना में आगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की ऑन लाईन नियुक्ति भर्ती के चयन सम्बन्धित ऑनलाईन आवेदन करने की तिथि 20 जून से 7 जुलाई तक ऑनलाईन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि के पश्चात पन्द्रह दिवस के अन्दर अन्तिम सूची जारी किया जाना था किन्तु आज दिनांक तक सूची जारी नही किया गया जिला अधिकारी एवं बाबू के लापरवाही के कारण लोग परेशान हैं क्या कारण है यह तो भगवान जाने लोगों ने आरोप लगाते हुये कहते है कि जबसे महिला एवं बाल विकास परियोजना देवसर में सिंगरौली जिले के ग्रामीण 2 परियोजना बाबू का प्रभार लिये हुये हैं तबसे लापरवाही चल रही है यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि आगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका की ऑनलाईन नियुक्ति भर्ती में चयनित व्यक्तियों के संबंध में जिला कलेक्टर सिंगरौली से मांग है कि कार्यवाही प्रक्रिया आगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का आवेदन जांच कर सूची जारी की जाय।

खड़े ट्रक से टकराई कार, मां-बेटे की दर्दनाक मौत

छतरपुर। दोपहर करीब 12 बजे ओरछा रोड थाना क्षेत्र अंतर्गत फोरलेन पर कैंड़ी गांव के समीप हुए भीषण सड़क हादसे में मां-बेटे की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि भाई-बहन सहित तीन घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल से ग्वालियर रेफर किया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची ओरछा रोड थाना पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को कब्जे में लेकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, साथ ही मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाए।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक नौगांव थाना क्षेत्र के ग्राम चौबारा के रहने वाले विश्राम राजावत की 45 वर्षीय पत्नी संतोषी राजावत, 27 वर्षीय पुत्र आशीष राजावत, 24 वर्षीय पुत्री आकांक्षा रावत, 19 वर्षीय पुत्र आयुष राजावत सहित एक अन्य महिला नौगांव से पन्ना की ओर जा रहे थे। इसी दौरान छतरपुर के ओरछा रोड थाना क्षेत्र में कैंड़ी के पास फोरलेन पर कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराई। कार की रफ्तार तेज होने के कारण संतोषी राजावत और उसके पुत्र आशीष राजावत की मौके पर मौत हो गई, जबकि आकांक्षा, आयुष सहित एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। दुर्घटना की खबर मिलते ही सीएसपी अरुण कुमार सोनी, ओरछा रोड थाना प्रभारी दीपक यादव सहित पुलिस बल मौके पर पहुंचा। दुर्घटनाग्रस्त वाहन से मृतकों और घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। चूंकि घायलों की हालत गंभीर थी, इसलिए प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को ग्वालियर रेफर किया गया है।

दवाइयों के साथ सही मार्गदर्शन सम्पूर्ण देखभाल एक ही जगह पर
डॉ. अभय मिश्रा एम.डी.,पी.एच.डी.(होम्यो)
के नेतृत्व में होमियोपैथिक इलाज, काउंसलिंग, डाइट व लाइफस्टाइल मैनेजमेंट
क्रॉनिक बीमारियों की देखभाल: माइग्रेन, एलर्जी, आर्थ्राइटिस/जॉइंट पेन, थायरॉइड, साइनुसाइटिस, सोरायसिस त्वचा समस्याएँ, गैस्ट्रिक/एसीडिटी, पीसीओएस, बाल/बालों का झड़ना आदि
मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार: एंग्जायटी, ओसीडी, स्ट्रेस, नींद की समस्या-काउंसलिंग + होमियोपैथिक सपोर्ट
हमारी विशेषताएँ: महिला एवं शिशु स्वास्थ्य: पीरियड/हार्मोन असंतुलन, गर्भावस्था-पूर्व/पश्चात देखभाल, बच्चों की बार-बार होने वाली सर्दी-खांसी
• Folli Plus Therapy
• Skin Care Unit
• Pain Management Therapy
• Detox Therapy (Liver & Skin)
• Weight Management (Obesity/Fat Loss)
क्लिनिक सुविधाएँ-
• स्वच्छ, शांत और प्राइवेसी-फ्रेंडली वातावरण
• डिजिटल रजिस्ट्रेशन व फॉलो-अप (व्हाट्सऐप/फोन पर)
• इन-हाउस होमियोपैथिक फार्मेसी (क्वालिटी मेडिसिन)
• काउंसलिंग रूम एवं डाइट/लाइफस्टाइल सलाह
• होम विज़िट (पूर्व-नियोजन पर)
DAY CARE UNIT विंध्य प्रदेश का पहला होमियोपैथिक सर्व सुविधायुक्त अस्पताल
क्यों चुनें हमें?
• 15+वर्ष का क्लिनिकल अनुभव / रिसर्च-ओरिएंटेड अप्रोच
• मरीज-केंद्रित, सुरक्षित और जेंटल थेरेपी
• केवल लक्षण नहीं- रूट कॉज पर फोकस
किरण होमियोपैथिक हेल्थ, वेलनेस & हीलिंग सेंटर - रीवा
पता:MIG 3/3/47, ऑक्सफोर्ड स्कूल के सामने, नेहरू नगर (नया बस स्टैंड), रीवा
समयः सोम-शनिः 10:30AM— 8:30 PM पूर्व-नियोजन फोन/व्हाट्सऐपः 91+ 07662454132- 9406752495

कार्यालय, नगर परिषद बरगवाँ, जिला-सिंगरौली (म.प्र.)

Office of Nagar Parishad Bargawan Distt-Singrauli (M.P.)
e-mail- cmobargawansingrauli@mpurban.gov.in

क्रमांक/944/न.प./2025 बरगवॉ, दिनांक: 18/08/2025

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित सप्लाई कार्य हेतु केंद्रीकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाइन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट www.mptenders.gov.in पर देखी जा सकती है।

क्र.	टेंडर क्रमांक जारी दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1	2025_UAD_444277_1 दिनांक– 18/08/2025	135 नग 48 वाट एल.ई.डी. स्ट्रिट लाईट सप्लाई कार्य (दिये गये स्पेशिफिकेशन अनुसार)	1. 01 माह 2. 4.38 लाख	1. 2000 2. 5000	03.09.2025
2	2025_UAD_444277_2 दिनांक– 18/08/2025	50 नग 100 लीटर जुडवा कुडादान सप्लाई कार्य (दिये गये स्पेशिफिकेशन अनुसार)	1. 01 माह 2. 4.25 लाख	1. 2000 2. 5000	03.09.2025

नोट:– निविदा में किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन www.mptenders.gov.in की बेवसाइट पर ही प्रकाशित किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नही किया जावेगा।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर परिषद् बरगवॉ
जिला– सिंगरौली (म.प्र.)

संस्थापक ▸ गुरुदेव गुप्त

संपादकीय

ऑनलाइन गेमिंग से पैदा हो रहीं गंभीर मुश्किलें

ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के कारण धोखाधड़ी और शोषण की घटनाएं भी सामने आई हैं। ऐसे में बाजार के इस हिस्से का विनियमन करने के बजाय यह जनहित में है कि इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए।

ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025 बुधवार को लोक सभा में पारित हो गया। यह विधेयक देश में ऑनलाइन गेमिंग में पैसों के लेनदेन को प्रतिबंधित करने से संबंधित है। अनुमान के मुताबिक ही सरकार के इस कदम ने ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में हलचल पैदा कर दी है। खबरें बताती हैं कि इसके चलते हजारों उच्च कौशल वाले रोजगारों पर संकट की तलवार लटकने लगी है। विधेयक में जिन उद्देश्यों और कारणों का उल्लेख किया गया है उनके मुताबिक ऑनलाइन गेमिंग में पैसों का इस्तेमाल होने से देश भर में गंभीर सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक मुश्किलें पैदा हो गई हैं क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से ये गेम बहुत व्यापक रूप से प्रसारित हो चुके हैं। ये प्लेटफॉर्म ऐसे लत वाले व्यवहार को बढ़ावा देते हैं जिनका परिणाम मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और वित्तीय नुकसान के रूप में सामने आता है। ऐसे प्लेटफॉर्म के कारण धोखाधड़ी और शोषण की घटनाएं भी सामने आई हैं। ऐसे में बाजार के इस हिस्से का विनियमन करने के बजाय यह जनहित में है कि इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया जाए।

अगर यह विधेयक अपने मौजूदा स्वरूप में पारित होता है तो देश में औपचारिक ऑनलाइन गेमिंग कारोबार का हमेशा के लिए पटाक्षेप हो जाएगा। साफ कहें तो इस बात से असहमति नहीं जताई जा सकती है कि ऑनलाइन गेमिंग एक लत की तरह है जो मानसिक और वित्तीय दोनों स्तरों पर प्रभावित करती है। बहरहाल, इस बात पर बहस हो सकती है कि क्या पूरी तरह प्रतिबंधित करना ही उपरोक्त समस्याओं का सही हल है। भारत में प्रतिभाशाली डेवलपर की एक पूरी फौज है जो तरह-तरह के गेम तैयार करती है और यह उद्योग बहुत तेज गति से बढ़ रहा है। भारत में ऑनलाइन गेम्स विकसित करने का वैश्विक केंद्र बनने की संभावना है। उद्योग जगत के संगठनों के मुताबिक स्किल गेमिंग कंपनियों का कारोबारी मूल्य 2 लाख करोड़ रुपये है और अब तक यह 25,000 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटा चुका है। सरकार के लिए बेहतर होता कि वह इस क्षेत्र के अंशधारकों और विशेषज्ञों से चर्चा करने के बाद ही विधेयक को पेश करती। सीधे प्रतिबंध लगाने के बाद एक संभावना यह है कि ऐसी गतिविधियों को गैर कानूनी तरीके से अंजाम दिया जाने लगे। यदि ऐसा हुआ तो ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े लोगों के शोषण और उनके साथ धोखाधड़ी की आशंकाएं बढ़ जाएंगी। इंटरनेट की पहुंच को देखते हुए सरकार के लिए यह बहुत कठिन होगा कि भूमिगत रूप से इसे संचालित करने वालों तक पहुंच सके। इसके अलावा सरकार कर राजस्व भी गंवा बैठेगी। इन सभी पहलुओं पर अब संसद में बहस होनी चाहिए।

कुल मिलाकर ऑनलाइन गेमिंग के लिए कानूनी ढांचा मुहैया कराने की बात के साथ यह विधेयक दूरदर्शी प्रतीत होता है। इससे वृद्धि और विकास में मदद मिलेगी हालांकि, ऑनलाइन धन आधारित गेम पर प्रतिबंध उसी भावना के अनुरूप नहीं है

नयी प्रतिभाओं के हाथ होनी चाहिए वित्तीय नियामकों की कमान

नियामक संस्थाएं

के पी कृष्णन

एक पुराना अवलोकन एक बार फिर उभर आया है। देश के प्रमुख वित्तीय नियामकों मसलन भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) और भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) आदि सभी के मौजूदा नियामक भारतीय प्रशासनिक सेवा के पूर्व अफसरशाह हैं। अक्सर इस तथ्य के साथ एक कथानक यह जोड़ दिया जाता है कि उनमें निरंतरता होती है और उन्हें सार्वजनिक व्यवस्था की गहरी समझ होती है और यह बात उन्हें इस काम के लिए सर्वथा उपयुक्त बनाती है। तर्क यह दिया जाता है कि यह कोई संयोग नहीं बल्कि उनके कौशल को मान्यता देना है जो सीमित क्षेत्रीय विशेषज्ञता से परे सामरिक सोच, आपदा प्रबंधन तक जाती है और उन्हें सरकारी मशीनरी के कामकाज की पूरी समझ होती है। हम पीछे मुड़कर इन संस्थानों के इतिहास को देख सकते हैं और इस नज़रिये की पुष्टि के लिए प्रमाण तलाश कर सकते हैं। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नरों की लंबी सूची में एस वेंकटरमणन, सी रंगराजन, विमल जालान, वाईवी रेड्डी और डी सुब्बाराव तक सभी अफसरशाही से आए थे और उनका लोक सेवा में लंबा करियर था। इसी प्रकार सेबी में 1992 से बने चेयरमैन मसलन जीवी रामकृष्ण, डीआर मेहता, जीएन वाजपेयी, एम दामोदरन, सीबी भावे और यूके सिन्हा भी वहीं से आए थे। आईआरडीएआई पर भी यही बात लागू होती है। उसके शुरुआती प्रमुखों में एन रंगाचारी, सीएस राव, जे हरि नारायण और टीएस विजयन अफसरशाही से आए थे। इस तरह से देखते हुए यह नतीजा निकालना आसान है कि भारत ने सफलतापूर्वक अफसरशाहों का ऐसा कैडर तैयार किया जो नियामकीय संस्थाओं के नेतृत्व के लिए अनुकूल थे। परंतु यह धारणा खतरनाक रूप से भ्रामक है। यह हकीकत को वांछित परिणामों के साथ भ्रमित करती है। हम जो देख रहे हैं वह व्यवस्था की कामयाबी नहीं बल्कि उसकी अपरिपक्वता की निशानियां हैं। अफसरशाहों को निरंतर प्राथमिकता देने का अर्थ यह नहीं है कि हम ढेर सारे योग्य उम्मीदवारों के बीच से चयन कर रहे हैं बल्कि यह संस्थागत कमजोरी का नतीजा है जिसके चलते किसी और के कामयाब होने की संभावना कम है। नियामकीय नेतृत्व के दुनिया भर में प्रचलित समझदारी भरे मॉडल्स की बात करें तो वे किसी एक तरह के पेशेवरों के बजाय विविधतापूर्ण नेतृत्व पैकेज पर काम करते हैं। किसी नियामक के लिए एक अच्छा नेतृत्व वह होता है जिसने संबंधित उद्योग में काम किया हो, व्यावहारिक कठिनाइयों, उसके प्रोत्साहनों और मुश्किलों से परिचित हो। इस व्यक्ति के पास गहन बौद्धिक क्षमता भी होनी चाहिए। अगर वह शोध या अकादमिक जगत से हो तो और भी अच्छा। इससे उसे बिना तात्कालिक हालात से प्रभावित हुए ठोस तरीके से सोच-विचार करने में सुविधा होगी। आखिर में, उसमें लोक प्रशासन, कानून और राजनीति की गहरी समझ होनी चाहिए। एक लोकतांत्रिक ढांचे मे अर्ध विधायी और अर्ध न्यायिक संस्था को चलाने के लिए यह आवश्यक है। भारत में हमें इस आदर्श को हकीकत में उतारने में मुश्किल होती है। अफसरशाहों के बीच जो सद्भाव नजर आता है वह दरअसल एक ऐसी व्यवस्था का परिणाम है जो किसी और चीज को संभालने में सक्षम नहीं होती। हमने ठोस संस्थागत बुनियाद नहीं रखीं। अगर हम ऐसा करते तो शायद गैर अफसरशाह नियामकों को पनपने का मौका मिलता। जब बाहरी व्यक्ति को भीतर लाया जाता है तो अक्सर उन्हें काफी कठिनाई होती है क्योंकि नियामक संस्थाएं पारदर्शी औपचारिक प्रक्रियाओं और कानून के शासन द्वारा संचालित नहीं होतीं। वे अक्सर अनौपचारिक नेटवर्क, अलिखित परंपराओं और सरकार के कामकाज की उस गहरी समझ पर निर्भर होती हैं जो केवल आजीवन अफसरशाह रहे व्यक्ति के पास होती है। यह एक बड़ी कमी है। उद्योग जगत के पेशेवर बाजार व्यवहार, नवाचार और जोखिम की जबरदस्त समझ रखते हैं। शोधकर्ताओं के पास अहम प्रमाण आधारित मानसिकता होती है और उनमें यह बौद्धिक क्षमता होती है कि वे उभरती चुनौतियों का सामना कर सकें। इसमें जटिल वित्तीय उपायों से लेकर नई तकनीक के नियमन तक शामिल होते हैं। इस समस्या का निदान मौजूदा हालात को लेकर रूमानी होना या यथास्थिति को अपनाना नहीं है बल्कि इसका हल बेहतर और अधिक मजबूत संस्थान बनाना है। हमें ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहां मनमोहन सिंह, सी रंगराजन, विमल जालान, विजय केलकर और एम एस आहलूवालिया जैसे असाधारण लोग मझोले-वरिष्ठ स्तर पर सरकार में शामिल हों और आगे बढ़ें। इस दौरान वे अपनी पेशेवर काबिलियत और अकादमिक नेटवर्क को बरकरार रखते हुए ऐसा कर सकें। ये सारे लोग किसी एक व्यवस्था की उपज नहीं हैं। वे विशेषज्ञों के एक समुदाय का हिस्सा थे जो सरकार, अकादमिक जगत, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और बाजार जैसे विविध क्षेत्रों में आवाजाही करते रहे। हालांकि इनमें से अधिकांश लोग विदेशी संस्थानों से आए लेकिन वे किसी संस्था में सीधे शीर्ष स्तर पर नहीं शामिल हुए। इसके बजाय वे देश की सार्वजनिक व्यवस्था में पनपे और उन्होंने आगे बढ़ते हुए व्यवस्थागत जटिलताओं को भी समझा। संस्थागत सुधारों को यही बात जटिल बनाती है। आगे की राह इस बात पर निर्भर करती है कि हम नियामकीय संस्थानों को कितना मजबूत बनाते हैं और उनके कामकाज को विधि के शासन के अनुरूप कितना ढालते हैं। वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग यानी एफएसएलआरसी का काम इस बदलाव को बखूबी दर्शाता है। भारतीय विधि संहिता का मसौदा जहां वित्तीय नियमन का खाका है वहीं इसमें कानून की 140 धाराएं हैं जो किसी भी नियामक पर लागू की जा सकती हैं, न कि केवल वित्तीय क्षेत्र के नियामकों पर। इनका लक्ष्य असंगठित क्षेत्र के नेटवर्क की जगह एक औपचारिक नियम आधारित प्रक्रिया को अपनाना है। यह संस्थागत सुधार केवल इस पर निर्भर नहीं है कि हमारे नियामकों का नेतृत्व कौन करेगा बल्कि यह देश की विकास यात्रा का भी अहम हिस्सा है। एक आधुनिक अर्थव्यवस्था अस्पष्ट और व्यक्तित्व आधारित प्रशासनिक राज्य पर नहीं बन सकती। इसके लिए एक ऐसी व्यवस्था की आवश्यकता है जहां निर्णय अनुमान लगाने योग्य न हों और जवाबदेही साफ हो। एफएसएलआरसी द्वारा सुझाए गए सुधारों का अनुकरण करके हम ऐसे नियामकीय संस्थान बना सकते हैं जो इतने मजबूत हों कि उद्योग, शोध और सार्वजनिक प्रशासन जैसे क्षेत्रों से नेतृत्व का स्वागत कर सकें। इससे हमें यह क्षमता मिलेगी कि हम उन चुनिंदा पेशेवरों द्वारा प्रदान की गई स्थिरता के भ्रम से आगे बढ़ने में सक्षम हो पाएंगे और यह एक वास्तव में परिष्कृत और प्रभावशाली नियामक नेतृत्व का निर्माण करने में मदद करेगा, जिसकी भारत को वैश्वीकृत दुनिया में समृद्ध होने के लिए आवश्यकता है।

यह नतीजा निकालना आसान है कि भारत ने सफलतापूर्वक अफसरशाहों का ऐसा कैडर तैयार किया जो नियामकीय संस्थाओं के नेतृत्व के लिए अनुकूल थे। परंतु यह धारणा खतरनाक रूप से भ्रामक है। यह हकीकत को वांछित परिणामों के साथ भ्रमित करती है। हम जो देख रहे हैं वह व्यवस्था की कामयाबी नहीं बल्कि उसकी अपरिपक्वता की निशानियां हैं। यह संस्थागत कमजोरी का नतीजा है जिसके चलते किसी और के कामयाब होने की संभावना कम है। ऐसे में आवश्यकता इस बात की है कि नियामकीय एजेंसियों के दरवाजे अधिक विविधता वाली प्रतिभाओं के लिए खोल दिए जाएं।

लचर पड़ती तकनीकी शिक्षा में सुधार का जिम्मा मेरिट योजना पर

राष्ट्रीय शिक्षा नीति

शशांक द्विवेदी

केंद्र सरकार ने हाल ही में बहु-विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार 'मेरिट' योजना को मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी योजना पर अगले पांच वर्षों में 4,200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और इससे देश के लगभग साढ़े सात लाख विद्यार्थी प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। यह योजना देश के 275 तकनीकी शिक्षण संस्थानों में लागू होगी, जिनमें 175 इंजीनियरिंग कॉलेज और 100 पॉलिटेक्निक संस्थान शामिल हैं। इस योजना का उद्देश्य न केवल तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारना है, बल्कि छात्रों को बहु-विषयक, व्यावहारिक और उद्योग से जुड़ा प्रशिक्षण प्रदान करना भी है। यह केंद्र सरकार की योजना है, जिसे इसी वित्तीय वर्ष से शुरू किया गया है। 2029-30 तक कुल 4,200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसकी आधी राशि 2,100 करोड़ रुपये का प्रबंध विश्व बैंक से ऋण लेकर किया जाएगा।

देश में तकनीकी शिक्षा की स्थिति : भारत में तकनीकी शिक्षा का ढांचा काफी व्यापक है। देश में आईआईटी, एनआईटी, सरकारी और निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ-साथ पॉलिटेक्निक और आईटीआई संस्थानों का बड़ा नेटवर्क है। हर साल लाखों छात्र तकनीकी कोर्सों में दाखिला लेते हैं। भारत में इंजीनियरिंग शिक्षा लंबे समय तक युवाओं की पहली पसंद रही है। डॉक्टर या इंजीनियर बनना दशकों तक माता-पिता और छात्रों का सपना रहा है। इसी मांग को देखते हुए 2000 के बाद देश में निजी इंजीनियरिंग कॉलेजों की संख्या तेज़ी से बढ़ी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में स्थिति पलट गई है, अब हर साल लाखों सीटें खाली रह जाती हैं। यह समस्या सिर्फ छोटे शहरों के कॉलेजों में ही नहीं, बल्कि कई पुराने और स्थापित संस्थानों में भी देखने को मिल रही है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के आंकड़ों के अनुसार, देश के कई राज्यों में इंजीनियरिंग सीटों का 30 से 50 फीसदी तक हिस्सा खाली रह जाता है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक से लेकर उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में यह प्रवृत्ति स्पष्ट है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजों में खाली सीटों का संकट केवल एक शैक्षिक समस्या नहीं, बल्कि यह देश के तकनीकी मानव संसाधन विकास पर भी असर डाल रहा है। यदि समय रहते शिक्षा की गुणवत्ता, उद्योग से तालमेल और छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखकर सुधार नहीं किए गए, तो यह संकट और गहराएगा। शिक्षा संस्थानों, सरकार और उद्योग–तीनों को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि इंजीनियरिंग शिक्षा फिर से रोजगारपरक, गुणवत्तापूर्ण और छात्रों के लिए आकर्षक बन सके।

गंभीर चुनौतियां

रोजगार की कमी- तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद बड़ी संख्या में स्नातक छात्रों को गुणवत्तापूर्ण रोजगार नहीं मिल पाता।

पाठ्यक्रम का पुराना ढांचा- कई संस्थानों में पाठ्यक्रम अभी भी पुराना है और उद्योग की बदलती जरूरतों के अनुरूप अपडेट नहीं है।

व्यावहारिक प्रशिक्षण की कमी- प्रयोगशालाओं, वर्कशॉप और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता।

अनुसंधान व नवाचार में पिछड़ापन- अनुसंधान कार्य और पेटेंट के मामले में भारत के तकनीकी संस्थान अब भी अंतरराष्ट्रीय मानकों से पीछे हैं।

शहरी-ग्रामीण असमानता- ग्रामीण क्षेत्रों के तकनीकी संस्थानों में संसाधनों, फैकल्टी और तकनीकी उपकरणों की भारी कमी है।

मेरिट योजना के उद्देश्य और विशेषताएं : बहु-विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार मेरिट योजना का उद्देश्य छात्रों को केवल तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि प्रबंधन जैसे विषयों से भी जोड़न है । छात्रों और फैकल्टी को उच्चस्तरीय रिसर्च प्रोजेक्ट्स में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता। प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिक वर्कशॉप की स्थापना। उद्योग के साथ मिलकर पाठ्यक्रम तैयार करना और छात्रों के लिए इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट और रोजगार के अवसर पैदा करना। कमजोर क्षेत्रों के तकनीकी संस्थानों को अतिरिक्त फंड और विशेषज्ञ सहयोग देना है।

तकनीकी शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के उपाय : पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण, हर तीन वर्ष में पाठ्यक्रम की समीक्षा और उद्योग की जरूरतों के अनुरूप अपडेट करना, ग्रीन एनर्जी को पढ़ाई में शामिल करना है। कॉलेजों में रिसर्च लैब और इनोवेशन सेंटर स्थापित करना है। छात्रों और शिक्षकों को पेटेंट फाइल करने के लिए प्रोत्साहन देना है। कंपनियों के साथ जॉब-रेडी स्किल आधारित प्रशिक्षण। ग्रामीण और छोटे शहरों के संस्थानों पर ध्यान वहां आधुनिक लैब और इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करना। छात्रों को ऑनलाइन लर्निंग और वर्चुअल लैब की सुविधा देना है।

छात्र-केंद्रित शिक्षा : कुशल और उद्योग-तैयार मानव संसाधन मेरिट योजना से निकलने वाले छात्र केवल डिग्रीधारी नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल स्किल वाले होंगे। इंडस्ट्री से जुड़ी शिक्षा मिलने पर छात्रों की रोजगार-योग्यता बढ़ेगी। पिछड़े इलाकों में भी आधुनिक तकनीकी शिक्षा की पहुँच बढ़ेगी। तकनीकी शिक्षा किसी भी देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास की रीढ़ होती है। यदि इस योजना को सही तरीके से लागू किया गया, तो आने वाले वर्षों में भारत न केवल तकनीकी शिक्षा में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि नवाचार और अनुसंधान में भी दुनिया में अग्रणी स्थान हासिल करेगा।

इंजीनियरिंग कॉलेजों में हर साल लाखों सीटें खाली रह जाती हैं। यह समस्या सिर्फ छोटे शहरों के कॉलेजों में ही नहीं, बल्कि कई पुराने और स्थापित संस्थानों में भी देखने को मिल रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप, केंद्र सरकार ने तकनीकी शिक्षा में सुधार के लिए बहु-विषयक शिक्षा एवं अनुसंधान सुधार मेरिट योजना को मंजूरी दी है।

प्रसंगवश

मुख्यमंत्री पर हमला, पुलिस इंटेलिजेंस पर गंभीर सवाल

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान हमला गंभीर और चिंताजनक घटना है। इससे न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा, बल्कि राष्ट्रीय राजधानी में समूची सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर मुख्यमंत्री के कड़े सुरक्षा घेरे की परवाह किए बगैर कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत कर सकता है, तो आम आदमी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। हालांकि, कहा जा रहा है कि मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने आरोपी को तत्काल हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। मगर, सवाल यह है कि वह मुख्यमंत्री के इतने करीब कैसे पहुंच गया? सुरक्षाकर्मी उसके नापाक इरादों को पहले क्यों नहीं भांप पाए? यह कोई साजिश थी या फिर कुछ और, इसका पता तो जांच-पड़ताल के बाद ही चल पाएगा, लेकिन इस घटना को सुरक्षा में चूक की नजर से देखा जा रहा है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच आरोपी सीएम के पास पहुंच गया था। मुख्यमंत्री पर हमला बुधवार सुबह उस समय हुआ, जब वे सिविल लाइंस स्थित अपने कार्यालय में लोगों की शिकायतें सुन रही थीं। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने मुख्यमंत्री को पहले कुछ कागजात दिए और फिर अचानक उन पर हमला कर दिया। इस हमले में उन्हें हाथ, कंधे और सिर में चोटें आई हैं। गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 'जेड' श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है। सुरक्षा के इतने मजबूत घेरे के बावजूद आरोपी मुख्यमंत्री के इतने करीब पहुंच गया कि हमला कर सके। आरोपी गुजरात के राजकोट का निवासी है और पुलिस का दावा है कि उस पर पहले से पांच आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें चाकू से हमले के दो और आबकारी अधिनियम के तहत तीन मामले शामिल हैं। यही नहीं, प्रारंभिक जांच में पता चला है कि आरोपी दो दिन पहले दिल्ली आया था और उत्तरी दिल्ली के सिविल लाइंस में रुका था। उसने हमले से पहले मुख्यमंत्री कार्यालय परिसर की रेकी भी थी। सीसीटीवी फुटेज में इसके प्रमाण मिले हैं। यानी पुलिस का खुफिया तंत्र भी आरोपी की इन गतिविधियों का समय रहते पता लगाने में विफल रहा। इसे सुरक्षा में लापरवाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा।

इस घटना को दिल्ली-एनसीआर से आवारा कुत्तों को आश्रय स्थलों में ले जाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से भी जोड़ा जा रहा है। आरोपी की मां का दावा है कि उनका बेटा पशु प्रेमी है और वह कुत्तों से बहुत प्यार करता है। कुत्तों को आश्रय स्थलों में भेजने की प्रक्रिया से वह आहत था और अपना विरोध जताने के लिए दिल्ली आया था।

अब सवाल यह है कि कानूनी दायरे में रह कर विरोध जताने के कई तरीके हैं, फिर उसने मुख्यमंत्री पर हमले की वारदात को अंजाम क्यों दिया? क्या इसके पीछे कोई सोची-समझी साजिश थी, पुलिस इस पहलू से भी छानबीन कर रही है। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि जिस तरह हमला किया गया, वह जानलेवा भी हो सकता था। इससे इस घटना की गंभीरता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। ऐसे में यह सवाल भी महत्त्वपूर्ण है कि आखिर राजधानी में सुरक्षा इंतजामों में इतनी लापरवाही क्यों हो रही है। अपराधियों में कानून का खौफ क्यों नहीं रहा। उनके हौसले क्यों बुलंद हो रहे हैं? जब तक इसकी जड़ में नहीं जाएंगे, तब तक कानून व्यवस्था में सुधार की उम्मीद धुंधली ही रहेगी।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले से राष्ट्रीय राजधानी में समूची सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। अगर मुख्यमंत्री के कड़े सुरक्षा घेरे की परवाह किए बगैर कोई व्यक्ति इस तरह की हरकत कर सकता है, तो आम आदमी खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा।

॥गीता॥

श्लोक

रुद्राणां शङ्करश्चास्मि
वित्तेशो यक्षरक्षसाम।
वसूनां पावकश्चास्मि
मेरुः शिखरिणामहम॥

भावार्थ

मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ। मैं आठ वसुओं में अग्नि हूँ और शिखरवाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत हूँ।

जीवन दर्शन

आपके अस्तित्व का एक महत्वपूर्ण भाग है ईश्वर

ऐसा माना जाता था कि जब हम स्वयं को ईश्वर कहते हैं तो कहीं न कहीं हम ईश-निंदा जैसा बड़ा अपराध कर रहे होते हैं। जबकि मैं कहता हूँ कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, ये कहना ईश्वर का असम्मान करने जैसा है। ऐसा कहकर आप इस बात को नकार रहे हैं कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है।

आप प्रेम से बने हैं, अगर आप ये कहते हैं कि आप ईश्वर नहीं हैं तो इसका अर्थ है कि आप ईश्वर और प्रेम में भिन्नता कर रहे हैं। ईश्वर को प्रेम न मानना एक तरह से ईश-निंदा करना है। मैं यहाँ आपकी चेतना है, जब आप ये कहते हैं कि- मैं ईश्वर नहीं हूँ तो इसका अर्थ ये है कि आप इस बात से इनकार कर रहे हैं कि ईश्वर जागरुक है, ईश्वर सचेत और सावधान है। आपका अस्तित्व है, लेकिन आप ईश्वर को अपने अस्तित्व का भाग मानने से इनकार कर देते हैं और निश्चित तौर पर इसे ईश्वर की निंदा से जोड़कर देखा जाना चाहिए। ऐसा कहते हुए आप उन दस्तावेजों को नकार रहे हैं, उन दस्तावेजों में लिखे सिद्धांतों को आप नकार रहे हैं जो ये कहते हैं कि ईश्वर ने इंसान को अपनी छवि के तौर पर बनाया है। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व ही नहीं है, एक दूसरे से अलग चीजें भी एक दूसरे के साथ पूरी तरह जुड़ी हैं। सापेक्षिक अस्तित्व रखने वाली कोई भी चीज कभी पूर्ण नहीं होती। अच्छा-बुरा, सही-गलत, सब कुछ सापेक्षिक है। उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हैं, दूध पीना अच्छा है लेकिन ज्यादा दूध पीना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। सत्य आपको द्विविधता तक पहुंचाता है, और ईश्वर संपूर्ण सत्य है। किसी फिल्म में जब रोशनी का उपयोग किया जाता है, तब उस रोशनी को इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि फिल्म कैसी है। कॉमेडी है या ट्रैजेडी, उसमें हीरो कौन है-विलेन कौन है..... रोशनी हमेशा वहाँ रहेगी। इसी तरह, आपके मस्तिष्क में भले ही कुछ क्यों न चल रहा हो, आप ईश्वर हैं और आपको इस बात को नकारना नहीं चाहिए।

श्री श्री रवि शंकर

संक्षिप्त खबरें

ईएनसी राणा ने बदले आठ इंजीनियरों के प्रभार

एजुकेशन रिपोर्टर, भोपाल। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता कृष्णपाल सिंह राणा ने आठ इंजीनियर प्रभार में परिवर्तन किया है। इसमें रामदास चौधरी, कार्यपालन यंत्री को प्रभारी अधीक्षण (योजना / बजट) यंत्री से प्रभारी अधीक्षण यंत्री (योजना / बजट) एवं प्रभारी अधीक्षण यंत्री (प्रशिक्षण), सुभाष पाटिल सहायक यंत्री को सहायक यंत्री (2010), कार्यालय प्रमुख अभियंता से प्रभारी अधीक्षण यंत्री (प्रशासन) और प्रभारी अधीक्षण यंत्री (विजिलेंस), मयंक शुक्ला सहायक यंत्री को प्रभारी अधीक्षण यंत्री से प्रभारी अधीक्षण यंत्री (क्वाालिटी कंट्रोल) और प्रभारी अधिकारी, केंद्रीय प्रयोगशाला, कुलदीप सिंह सहायक यंत्री को प्रभारी अधीक्षण यंत्री (विजिलेंस) से प्रभारी अधीक्षण यंत्री (संचार), अविनाश शिवरिया सहायक यंत्री को प्रभारी अधीक्षण यंत्री (आईटी सेल) से प्रभारी अधीक्षण यंत्री (न्यायालय प्रकोष्ट)। आसिफ मंडल सहायक यंत्री को प्रभारी कार्यपालन यंत्री (संचार शाखा/ एसएफसी/ ईएफसी) से प्रभारी अधीक्षण यंत्री (आईटी सेल), सविता मालवीय सहायक यंत्री को प्रभारी कार्यपालन यंत्री (विजिलेंस) और प्रभारी कार्यपालन यंत्री केन्द्रीय प्रयोगशाला से प्रभारी कार्यपालन यंत्री (विजिलेंस) (कार्यपालन यंत्री केन्द्रीय प्रयोगशाला के दायित्वों से मुक्त करते हुये) और नीतेश सूर्यवंशी सहायक यंत्री कुमार को प्रभारी कार्यपालन यंत्री (प्रशासन) से प्रभारी कार्यपालन यंत्री (प्रशासन) एक प्रभारी कार्यपालन यंत्री (आईटी सेलं) में पदस्थ किया गया है।

जीएसटी की नई दरों से किसानों को होगा लाभ

भोपाल। उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा गुरुवार को नई दिल्ली में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक में शामिल हुये। उन्होंने प्रदेश का पक्ष रखते हुए कहा कि 31 अक्टूबर 2025 को सेस समाप्त करने पर मप्र सहमत है। सेस समाप्त होने के बाद इसे जीएसटी में मर्ज करना है। देवड़ा ने कहा कि 40 प्रतिशत स्लैब की सीलिंग के संबंध में जीएसटी एक्ट में धारा 9 (1) में संशोधन पर विचार किया जा सकता है। देवड़ा ने कहा कि सरलीकृत प्रणाली से आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और छोटे व्यवसायों को लाभ होगा। जीएसटी को और अधिक पारदर्शी और विकास केंद्रित भी बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट देने पर विचार किया जा सकता है।

34 सरकारी विभाग नहीं दे रहे अधूरी परियोजनाओं की जानकारी

सीएजी और वित्त विभाग ने कई बार लिखे पत्र, सीएस को भी दी जानकारी, विभाग को अपनी वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने में आ रही दिक्कत

विशेष संवाददाता, भोपाल। प्रदेश के गृह, लोकनिर्माण, स्कूल शिक्षा सहित ऐसे 34 विभागों द्वारा अपनी अधूरी परियोजनाओं के बारे में जानकारी नहीं दी जा रही है, जबकि इसके लिए ऑडिटर जनरल (सीएजी) और वित्त विभाग द्वारा पिछले 5 माह से लगातार पत्र लिखकर जानकारी मांगी जा रही है। विभाग यह भी नहीं बता पा रहे हैं कि उनके विभाग के बजट की कितनी राशि बैंकों में जमा है। सबसे अहम बात यह है कि इन विभागों में वित्त विभाग भी शामिल है। गौरतलब है कि सीएजी को वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदेश के विभागों को जारी बजट के आंकलन के दौरान पता चला कि 34 ऐसे विभाग हैं, जिनके बजट नियंत्रण अधिकारियों द्वारा यह जानकारी नहीं दी गई है कि वित्तीय वर्ष के दौरान आवंटित बजट के अनुपात में कितनी परियोजनाएं और बड़े कार्य अधूरे पड़े हैं। इतना ही नहीं उनके द्वारा यह भी नहीं बताया गया कि इन कार्यों के लिए आवंटित बजट में से कितनी राशि बैंकों में जमा है। बताया गया है कि मामला सामने आने के उपरांत

ऑडिटर जनरल कार्यालय द्वारा पिछले पांच माह से राज्य शासन को पत्र लिखा जा रहा है। एजी द्वारा हर माह पत्र लिखे जाने के अलावा वित्त विभाग द्वारा भी इन संबंधित विभागों को कई बार जानकारी भेजने को कहा गया है। जानकारों की मानें तो इससे वित्त विभाग को अपनी वित्तीय रिपोर्टिंग तैयार करने में दिक्कत आ रही है। जिसका प्रभाव राज्य के वित्तीय लेनेदेन का ब्यौरा बनाने में भी पड़ रहा है। जानकारी के अनुसार महालेखाकार द्वारा प्रदेश के मुख्य सचिव को इस संबंध में पत्र लिखा गया,तो सीएस के निर्देश पर वित्त विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि वह तत्काल प्रभाव से वांछित जानकारी भेजे। जिन विभागों द्वारा अब तक यह जानकारी नहीं भेजी है, उनमें जनजातीय कार्य विभाग, राजस्व विभाग, लोक परिसंपत्ति प्रबंधन, एमएसएमई, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा, अनुसूचित जाति कल्याण, कुटरी और ग्रामोद्योग, महिला एवं बाल विकास, संसदीय कार्य, विमानन, वित्त विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन, खनिज, किसान कल्याण एवं कृषि विकास, श्रम विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, गृह विभाग, स्कूल शिक्षा, विधि एवं विधायी कार्य, संस्कृति विभाग, वन विभाग, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विभाग, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता, संरक्षण विभाग प्रमुख है।

यह भी मांगी जानकारी

अधिकारियों के मुताबिक विभागों से अधूरी परियोजनाओं और बैंक में जमा राशि के अलावा आउटसाइड फंड ऑपरेशन की स्थिति, पंचायत राज संस्थाओं को दी जाने वाली बकाया ग्रांट, पीपीपी मोड और जनभागेदारी के तहत निवेश, नई योजनाओं पर लिए गए नीतिगत निर्णयों का संभावित कैश फ्लो, सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम के बारे में भी पूछा गया है।

नहीं दी गईं ये जानकारियां

बताया गया है कि विभागों ने अपूर्ण पड़े कार्यो की सूची के अलावा बिजली योजनाओं के वित्तीय परिणाम, ऋण और अग्रिम का समेकित वितरण, निगम, सरकारी कंपनियों और सहकारी संस्थाओं को दी गई सहायता,ऋण व लाभांश की रिपोर्ट और नए ऋण और एडवांस की जानकारी भी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

आदिवासी क्षेत्रों पर भाजपा का फोकस कांग्रेस को मात देने बनी रणनीति

मंत्रियों और बड़े नेताओं को दी जाएगी जनजाति क्षेत्रों की कमान

विशेष संवाददाता, भोपाल। मध्यप्रदेश में भाजपा एक बार फिर से कांग्रेस मुक्त राज्य बनाने के अभियान में जुटने की तैयारी में है पर पार्टी यह काम गोपनीय ढंग से रणनीति के तहत करेगी। इसके लिए पार्टी के आदिवासी मंत्रियों, विधायकों और वर्ग से आने वाले बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। पिछले दो विधानसभा और लोकसभा चुनाव का विश्लेषण करने के बाद भाजपा ने मध्यप्रदेश में आदिवासी वोट बैंक पर अपनी पकड़ को और मजबूत बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। सूत्रों की मानें तो दल के रणनीतिकारों का कहना है कि यदि मध्यप्रदेश को उत्तरप्रदेश की तरह कांग्रेस मुक्त बनाने या उसे कमजोर करना है, तो सबसे ज्यादा आदिवासी वोट बैंक पर काम करना होगा, क्योंकि इस समुदाय का काफी वोट प्रतिशत अभी भी कांग्रेस के साथ है, जिससे कांग्रेस चुनावों में विशेषकर विधानसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर तब दे रही है, जब कांग्रेस संगठनात्मक तौर पर अपेक्षाकृत कमजोर और बिखरी हुई है। साथ ही पार्टी नेताओं में लगातार आमराय का अभाव बना हुआ है।

भील प्रदेश की मांग पर भी नजर

पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि केन्द्रीय नेतृत्व की नजर भील प्रदेश की मांग पर भी है। उनका मानना है कि आने वाले समय में यदि यह मांग प्रबल हुई, तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को हो सकता है। ऐसे में पार्टी आदिवासी क्षेत्रों में भील वर्ग से प्रतिनिधित्व बढ़ाने के साथ-साथ दूसरे वर्ग के आदिवासियों को भी बढ़ावा देने की रणनीति पर काम करेगी। हालांकि पार्टी इस तरह की मांगों को सिरे से खारिज करती है।

आदिवासी सरकार के साथः नागर

कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान का कहना है कि इस तरह की मांग सैद्धांतिक तौर पर सही नहीं है। मध्यप्रदेश कई वर्ग के आदिवासी है, यहां पर भील के अलावा भिलाला, गोंड, कोल, बैगा, सहरिया, कोरकू, भारिया, और हल्बा. ये जनजातियां राज्य की कुल जनसंख्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ऐसे में यदि भील प्रदेश की मांग उठती है, तो फिर दूसरे वर्ग के लोग भी अपने-अपने प्रदेश की मांग करने लगेंगे। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का आदिवासी बहुत ही समझदार और समाज, प्रदेश व राष्ट्रहित में निर्णय लेने वाला है। उसका पूरा फोकस अपने समुदाय के विकास के साथ-साथ राज्य के उत्थान पर रहता है,ऐसे में अलग से राज्य बनाने की जैसी मांगें चंद लोगों तक ही सीमित रह जाएगी।

मंत्री भी संभालेंगे मोर्चा

बीते दिवस मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने निवास पर प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और संगठन महामंत्री हितानंद के साथ आदिवासी क्षेत्रों में अपना वोट बैंक को और मजबूत बनाने को लेकर मंथन किया था। तब तय किया गया था कि सरकार के मंत्रियों को इन अंचलों पर बार-बार भेजा जाएगा, जहां उनके द्वारा आदिवासियों व जनता से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन पर खुद निगरानी करनी होगी।

आदिवासी वोट का अंतर ज्यादा नहीं

जानकारों का कहना है कि दरअसल भाजपा इसलिए चिंतित है कि उसे यह मालूम है कि प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 1,53,16,784 है जो राज्य की कुल जनसंख्या का 21.1 प्रतिशत हैं। ये वोट प्रतिशत के तौर पर 50.27 प्रतिशत है। अगर पिछले दो विधानसभा चुनावों पर नजर डालें, तो भाजपा को जितना वोट प्रतिशत इस समुदाय को मिला है, उससे कांग्रेस ज्यादा दूर नहीं रही है। यदि इसे सीटों के आधार पर देखा जाए,तो इस वर्ग की आरक्षित 47 सीटों में से भाजपा को वर्ष 2018 के चुनाव में 17 सीटें और वर्ष 2023 के चुनाव में 25 सीटें मिल पाई थी,जबकि कांग्रेस ने क्रमशः30 और 25 सीटें जीती है। इसमें अहम बात यह भी है कि वर्ष 2023 के चुनाव के कुछ सीटों पर कांग्रेस काफी कम वोटों के अंतर से चुनाव हारी है।

प्रचारक भी संभालेंगे कमान

जानकारों की मानें तो भाजपा की इस मुहिम का संघ की विचारधारा से जुड़े कार्यकर्ता भी अपनी सहभागिता निभाएंगे। इनके अलावा संघ के प्रचारकों को भी आदिवासी क्षेत्रों में डेरा जमाने को कहा जाएगा, जिसका उद्देश्य केवल आदिवासियों को हर समझाने का होगा कि उनके हित के लिए भाजपा सरकारों ने ही काम किया है।

कर्मचारियों को 6 साल में भी नहीं मिला आयुष्मान योजना का लाभ

- 3 साल पहले कैबिनेट में हो चुका है निर्णय
- संविदा और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सबसे ज्यादा परेशान

कार्यालय संवाददाता, भोपाल। प्रदेश के लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारियों को बीते 6 साल से आयुष्मान निरामयम योजना का इंतजार है। कर्मचारियों को योजना के लाभ का इंतजार इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि तीन साल पहले मप्र केबिनेट इस पर मुहर लगा चुकी है। इसके बाद मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन हो चुका है। बावजूद इसके अभी तक सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिला है। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़ने की घोषणा की थी। इसके बाद मुख्यमंत्री बने शिवराज सिंह ने भी इस घोषणा को दोहराया। फिर डॉ. मोहन यादव ने इसे आगे बढ़ाते हुए केबिनेट से पारित कराया।

इन कर्मचारियों को मिलना है लाभ

तृतीय श्रेणी कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, शिक्षक संवर्ग, नगर सैनिक, राज्य की स्वशासी संस्थानों में सेवारत कर्मचारी, निगम मंडलों में सेवारत कर्मचारियों और अखिल भारतीय सेवा के लिए योजना वैकल्पिक रखी गई थी। इनके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, आशा व ऊषा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकता, आशा सहयोगी के साथ अन्य मैदानी कर्मचारी।

कई विभाग के अधिकारी समिति में

कर्मचारियों को आयुष्मान योजना से जोड़ने के लिए बनाई गई कमेटी में मुख्य सचिव के अलावा अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा (तब एसीएस विभाग प्रमुख थे अब प्रमुख सचिव हैं), अपर मुख्य सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास (तब एसीएस विभाग प्रमुख थे अब प्रमुख सचिव हैं), प्रमुख सचिव वित्त विभाग (तब प्रमुख सचिव थे अब अपर मुख्य सचिव हैं)। प्रमुख सचिव राजस्व विभाग, सचिव लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, प्रबंध संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश शामिल हैं।

> मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो समिति बनी है, वह ड्राफ्ट तैयार कर रही है। कर्मचारियों को कुछ अन्य सुविधाएं भी योजना के साथ देने पर मंथन चल रहा है। जल्द ही आयुष्मान योजना का लाभ प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा।
>
> ■ **योगेश भरसट, सीईओ,** आयुष्मान निरामय मप्र

3 साल में 100लाख हेक्टेयर क्षेत्र में होगी सिंचाई

विसं, भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गुरुवार को जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान विभिन्न परियोजनाओं से बढ़ रहे सिंचाई क्षेत्र की जानकारी ली। उन्होंने वर्तमान में शासकीय स्रोतों से प्रदेश में सिंचाई प्रतिशत 52 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है। इसे शीघ्र ही दोगुना करने का लक्ष्य ध्यान में रखकर कार्य किया जाए जिससे आने वाले 3 वर्ष में प्रदेश में 100 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र का विस्तार हो जाए। डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश नवकरणीय ऊर्जा के प्रमुख केन्द्र के रूप में उभर रहा है। हरित ऊर्जा के लिए प्रतिबद्ध बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के लिए मध्यप्रदेश आकर्षण का केन्द्र बन रहा है। सीएम ने यह बात सेक्का क्लाइमेट फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट क्ले स्ट्रेंजर और सीमा पॉल, यूनिवर्सिटी ऑफ केलिफोर्निया बर्कले के इंडिया एनर्जी एंड क्लाइमेट सेंटर के सीनियर एडवाइजर मोहित भार्गव से मंत्रालय में हुई सौजन्य भेंट के दौरान यह बात कही।

बाबूजी ने हमेशा कमजोर वर्गों की आवाज उठाईः मुख्यमंत्री

सीएम डॉ. मोहन यादव ने पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री कृष्णा गौर के 74 बंगला स्थित निवास पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्व. बाबूलाल गौर ने प्रदेश के विकास के लिए सभी दिशाओं में दायित्व का निर्वहन किया। उन्होंने श्रमिक, गरीब व कमजोर वर्ग के लिए आवाज उठाई और संघर्ष किया। साथ ही एक आदर्श विधायक के कर्तव्यों का निर्वहन किया। डॉ. यादव ने परिजन से संवेदनाएं साझा करते हुए कहा कि भोपाल ताल पर बना वीआईपी रोड गौर साहब की देन है। मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल सदैव स्मरणीय रहेगा। जनसेवा का मार्ग चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन उनके व्यवहार और सबकी मदद के भाव के कारण लोगों का बाबूजी से आत्मीय संबंध था। इस अवसर पर खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग, विधायक रामेश्वर शर्मा, विधायक भगवानदास सबनानी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल,संगठन महामंत्री हितानंद सहित दूसरे अन्य जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में नगरवासी उपस्थित थे।

श्रद्धांजलि

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पूर्व सीएम बाबूलाल गौर की पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की।

रेल यात्रियों के एक्स्ट्रा लगेज पर नहीं लगेगा कोई जुर्माना: वैष्णव

नई दिल्ली, जेएनएन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बातचीत में हवाई यात्रियों की तरह एक्स्ट्रा लगेज पर ज्यादा किराया लगाने की खबरों का खंडन किया है। उन्होंने साफ कहा कि दशकों से ऐसा नियम है कि यात्री कितने वजन तक का सामान साथ ले सकते हैं, कोई नया नियम नहीं बना है। उन्होंने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि उसके ऊपर वजन होने पर ज्यादा किराया वसूला जाता है। पहले खबर आई थी कि भारतीय रेलवे अब हवाई यात्रा की तरह लगेज को लेकर नियम लागू करने जा रही है, जिसके तहत यात्रा के दौरान ज्यादा सामान साथ ले जाने पर लगेज के हिसाब से एक्स्ट्रा किराया वसूला जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि यह नियम पहले से है, लेकिन इसे पूरी सख्ती के साथ अब लागू किया जाएगा। इस नियम के तहत तय वजन तक का सामान यात्रा में मुफ्त ले जा सकेंगे, लेकिन उससे ज्यादा सामान ले जाना पर अतिरिक्त किराया देना होगा। रिपोर्ट में बताया गया था कि इस नियम के मुताबिक यात्रा की अलग-अलग बोगी कैटेगरी के हिसाब से बिना किसी अतिरिक्त किराए के सामान ले जाने की इजाजत होती है। जैसे कि फर्स्ट क्लास एसी कोच में सफर करने वालों के लिए 70 किलोग्राम तक सामान ले जाने की इजाजत होगी। एसी सेकंड क्लास के यात्रियों के लिए यह लिमिट 50 किलोग्राम और थर्ड एसी और स्लीपर क्लास के यात्रियों के लिए 40 किलोग्राम तक की लिमिट तय होगी।

इसी तरह, जनरल टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को सिर्फ 35 किलोग्राम वजनी सामान अपने साथ ले जाने की इजाजत होगी

सामान का वजन और साइज नहीं होगा चेक

पहले रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया था कि रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट की तरह ही अपने सामान की प्री-बुकिंग करने की सुविधा भी शुरू की गई है। अगर तय लिमिट से ज्यादा वजन का बैग या ब्रीफकेस होगा तो फिर ऐसे यात्रियों पर जुर्माना लगाए जाने का भी प्रावधान है। यह भी बताया गया था कि नियम को लागू करने के लिए रेलवे स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक लगेज मशीनें भी लगाए जाएंगी। रेलवे प्लेटफार्म पर एंट्री से पहले ही यात्रियों के बैग का वजन और उसका साइज चेक होगा। मतलब कि यात्रियों के सामान का वजन ही नहीं, बल्कि उनके ट्रैवल बैग के साइज को भी इस दायरे में रखा जाएगा।

रिपोर्ट व्हिस्की, बीयर और वाइन की खपत में इजाफा, पिछले माह पुलिस ने चलाया था अभियान

नशामुक्ति अभियान में देसी शराब की बिक्री 64 फीसदी गिरी

मुख्य संवाददाता, भोपाल। प्रदेश में पिछले माह पुलिस के नशा मुक्ति अभियान के दौरान राजधानी में शराब की बिक्री में गिरावट आई है। भोपाल जिले के शराब खपत के आंकड़ों के अनुसार जुलाई माह में कुल 2 लाख 65 हजार प्रूफ लीटर देसी शराब बेची गई जबकि पिछले साल इसी अवधि में 7 लाख 20 हजार लीटर से अधिक देसी शराब बेची गई थी। प्रदेश में 15 से 30 जुलाई तक 16 दिन का नशा मुक्ति अभियान पुलिस द्वारा प्रदेश भर में चलाया गया था। इस अभियान के दौरान रैली, पोस्टर, बैनर, मानव श्रृंखला, जागरुकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, प्रतियोगिताओं, सोशल मीडिया के जरिए लोगों को नशे से दूर रहने की अपील की गई थी। इस दौरान जनता को जीवन में नशे से दूर रहने के लिए शपथ भी दिलाई गई थी।

अभियान के दौरान विदेशी शराब वाइन और बीयर की सेल बढ़ी

इस मामले में रोचक तथ्य यह है कि नशा मुक्ति अभियान के दौरान जहां एक तरफ देसी शराब की खपत में भारी कमी आई वहीं विदेशी शराब, बीयर और वाइन की खपत मे इजाफा हुआ है। जुलाई में विदेशी शराब की बिक्री 30 प्रतिशत, बीयर की 13 प्रतिशत, ड्रॉट बीयर की 45 प्रतिशत और वाइन की 26 फीसदी तक बढ़ गई। हालांकि अगर राजधानी में बिक्री के आंकड़ों को देखा जाए तो पिछले साल इस अवधि में कुल 17 लाख 79 हजार 441 लीटर शराब बिकी थी जो इस साल घटकर 15 लाख 41 हजार 816 लीटर रह गई है। जो पिछले साल से 2 लाख 37 हजार 625 लीटर कम है। इस हिसाब से भोपाल में शराब की बिक्री लगभग 15 फीसदी तक गिर गई है।

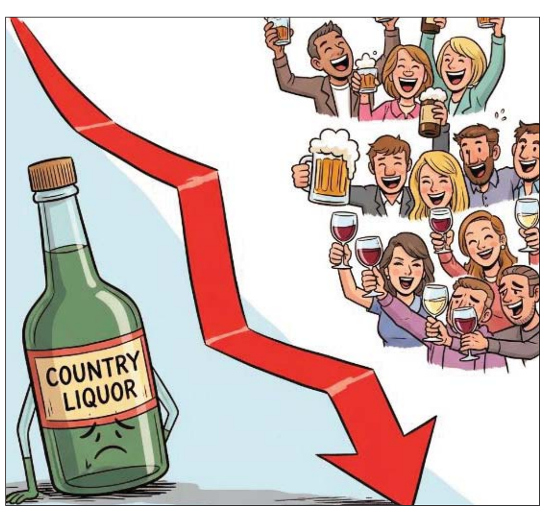

अवैध शराब तस्करी और मदिरापान के केस बढ़े

पिछले साल जुलाई माह में आबकारी अमले ने कुल 753 केस दर्ज किए थे। इनमें से अवैध शराब निर्माण, बिक्री और तस्करी के 360 और अवैध मदिरापान के 393 केस दर्ज किए गए थे। इस साल जुलाई माह में ये आंकड़े बढ़ गए हैं। आबकारी विभाग से मिली जानकारी के अनुसार इस साल जुलाई में कुल 867 केस दर्ज किए गए हैं। इनमें अवैध स्थान पर मदिरापान के 461 और अवैध शराब निर्माण, बिक्री और तस्करी के 406 मामले दर्ज हुए हैं। यह पिछले साल के मुकाबले 15 प्रतिशत अधिक हैं।

भोपाल में शराब बिक्री का आंकड़ा

मद	इस साल	पिछले साल	अंतर(प्रतिशत में)
देसी मदिरा	720774	265309	-63.19
विदेशी शराब	439208	573414	30.56
बीयर	605507	684089	12.98
ड्रॉट बीयर	6895	10052	45.79
वाइन	7057	8952	26.85
टोटल	1779441	1541816	-15

(जुलाई के आंकड़े, बीयर एवं ड्रॉट बीयर बल्क लीटर में, शेष प्रूफ लीटर मे

ये है पर्दे के पीछे की कहानी

आबकारी विभाग के सूत्रों के अनुसार देशी शराब की बिक्री गिरने के आंकड़ों की असल वजह नशा मुक्ति अभियान के साथ ही शराब ठेकेदार भी हैं। भोपाल में इस बार चार समूहों के पास शराब दुकानों के ठेके हैं, जो 80 से ज्यादा दुकानें संचालित करते हैं। पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि ये समूह आबकारी वेयरहाउस से इस साल देसी शराब का बेहद कम स्टॉक उठा रहे हैं। इसके बजाय वे सस्ती व्हिस्की का ज्यादा स्टॉक उठा रहे हैं। आबकारी में फिलहाल ऐसा कोई नियम नहीं है कि वाइन शॉप का ठेका लेने वाले को देसी और विदेशी शराब किसी तय अनुपात में उठाने की कोई बाध्यता हो। इसी कारण देसी शराब की बिक्री में गिरावट आई है और शराब आउटलेट से देसी के शौकीनों को सस्ते दाम वाली विदेशी शराब बेची जा रही है। इस बारे में आबकारी विभाग के अफसर कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं।

योगी पर बनी फिल्म अजेय को पहले हम देखेंगे: सुप्रीम कोर्ट

मुंबई, जेएनएन। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित फिल्म अजेय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी को देखने का फैसला किया है। यह निर्णय फिल्म निर्माताओं द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में लिया गया है। याचिका में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा फिल्म को प्रमाणपत्र देने से इनकार करने के फैसले को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा कि वह फिल्म देखने के बाद सीबीएफसी की आपत्तियों के आधार पर सोमवार को अपना आदेश सुनाएगा। फिल्म अजेय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी पुस्तक द मॉन्क हू बिकेम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित है, जो कथित तौर पर योगी आदित्यनाथ के जीवन पर आधारित है। फिल्म के निर्माता, सम्राट सिनेमैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि सीबीएफसी ने फिल्म, इसके ट्रेलर, टीजर और दो प्रचार गीतों के लिए प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया। 7 अगस्त के अपने पहले के आदेश में, न्यायालय ने सीबीएफसी को निर्देश दिया था कि वह फिल्म देखें और 11 अगस्त तक फिल्म निर्माताओं के साथ अपनी आपत्तियां साझा करें ताकि वे आवश्यक बदलाव करने पर विचार कर सकें। सीबीएफसी की जांच समिति ने 11 अगस्त को 29 आपत्तियां सूचीबद्ध कीं। हालांकि, जब फिल्म निर्माता 12 अगस्त तक कोई जवाब नहीं दे पाए या कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं किया, तो सीबीएफसी की पुनरीक्षण समिति ने फिल्म देखी।

इन्वेस्ट मध्यप्रदेश उद्योग एवं रोज़गार वर्ष 2025

MPSMC

मध्यप्रदेश की खनिज संपदा आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री

मध्यप्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0

खनन क्षेत्र के भविष्य की नई दिशा - क्रमिक । निरंतर । नीतिगत

मुख्य अतिथि

डॉ. मोहन यादव

मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश

23 अगस्त, 2025 । पूर्वाह्न 10:00 बजे
द अरिंदम होटल, कटनी, मध्यप्रदेश

"मध्यप्रदेश खनन और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में उभरा है। प्रदेश खनिजों की प्रचुरता और सरकार की निवेश-अनुकूल नीतियों के कारण देश की औद्योगिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खनन क्षेत्र न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करेगा, बल्कि देश के औद्योगिक विकास और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत मिशन में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। - डॉ. मोहन यादव, मुख्यमंत्री"

राष्ट्रीय उत्पादन में मध्यप्रदेश का योगदान

- हीरा – एकमात्र उत्पादक प्रदेश
- तांबा – 73%
- रॉक फॉस्फेट – 29%
- मैंगनीज – 26%
- चूना पत्थर – 9%
- कोयला – 8%

कॉन्क्लेव के फोकस सेक्टर

- **कोयला और ऊर्जा** – औद्योगिक विकास व विद्युत उत्पादन का आधार
- **ऊर्जा एवं हाइड्रोकार्बन** – आत्मनिर्भर ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण संसाधन
- **प्रौद्योगिकीय प्रगति** – डिजिटल, स्मार्ट और आधुनिक खनन समाधान
- **क्रिटिकल मिनरल्स** – भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक आधार
- **चूना पत्थर और सीमेंट** – निर्माण और अधोसंरचना विकास की रीढ़
- **खनिज एवं खनिज उत्पाद** – आधुनिक खनन तकनीकों और खनन क्षेत्र में डिजिटलीकरण पर विशेष प्रदर्शनी

आइए, मध्यप्रदेश माइनिंग कॉन्क्लेव 2025 का हिस्सा बनें और भविष्य के अवसरों से जुड़ें

मध्यप्रदेश जनसम्पर्क द्वारा जारी

आकल्पन : म.प्र. माध्यम/2025

D-11082/25

सीधा प्रसारण @Cmmadhyapradesh @jansampark.madhyapradesh @Cmmadhyapradesh @jansamparkMP JansamparkMP

IN PARTNERSHIP WITH Deloitte. CII Confederation of Indian Industry

बेंगलुरु से छिनी महिला वर्ल्ड कप मैचों की मेजबानी

आईसीसी ने जारी किया नया कार्यक्रम, तारीख नहीं, स्थान बदले एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले मैच अब नवी मुंबई में होंगे

जेएनएन, नई दिल्ली

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने शुक्रवार को महिला वनडे विश्व कप का नया कार्यक्रम जारी किया है, जिसके मुताबिक बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम से मेजबानी छीन ली गई है। 30 सितंबर से शुरू होने वाले महिला विश्व कप के लिए बेंगलुरु की जगह नवी मुंबई का डीवाई पाटिल स्टेडियम चौथा भारतीय स्थल होगा। मैचों की मेजबानी के लिए पुलिस की मंजूरी प्राप्त करने हेतु बीसीसीआई द्वारा कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन (केएससीए) को बार-बार दी गई समय-सीमा को पूरा न कर पाने के कारण बेंगलुरु में होने वाले महिला विश्व कप मैचों को मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया है। बीसीसीआई ने सभी प्रतिभागी देशों को अपडेट भी भेज दिया है। आठ टीमों के इस टूर्नामेंट की तारीखें वही रहेंगी (30 सितंबर से 2 नवंबर)। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी है। इंदौर, वाइजैग और गुवाहाटी के अलावा नवी मुंबई को चौथा भारतीय स्थल बनाया गया है। पाकिस्तान से जुड़े सभी मैचों और पहले सेमीफाइनल की मेजबानी श्रीलंका की राजधानी कोलंबो को मिली है। जून में आईसीसी ने टूर्नामेंट की तारीखों की घोषणा करते हुए बेंगलुरु को पांच आयोजन स्थलों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया था। मेजबान भारत के साथ टूर्नामेंट के पहले मैच के अलावा बेंगलुरु को 30 अक्टूबर को एक सेमीफाइनल और संभवतः 2 नवंबर को फाइनल की मेजबानी भी करनी थी। (अगर पाकिस्तान फाइनलिस्टों में से एक नहीं होता)।

स्टेडियम बड़े आयोजन के लिए असुरक्षित करार

बीसीसीआई को यह फैसला इसी साल 4 जून को घरेलू टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) द्वारा पहली बार आईपीएल जीतने के बाद स्टेडियम के आसपास मची भगदड़ के बाद से इस स्टेडियम को बड़े आयोजनों के लिए असुरक्षित करार दिए जाने के बाद लेना पड़ा है। कर्नाटक सरकार द्वारा नियुक्त एक सदस्यीय समिति ने स्टेडियम को बड़े पैमाने पर होने वाले आयोजनों के लिए असुरक्षित माना है, जिसके बाद कर्नाटक पुलिस ने केएससीए को वहां कोई भी मैच आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके कारण केएससीए को महाराजा टी-20 को बेंगलुरु से मैसूर स्थानांतरित करना पड़ा था।

■ नवी मुंबई स्थित डीवाई पाटिल स्टेडियम में तीन लीग मैच, एक सेमीफाइनल और संभवतः फाइनल सहित पांच मैच आयोजित किए जाएंगे। आठ टीमों के इस टूर्नामेंट के अन्य स्थानों में गुवाहाटी, इंदौर, विशाखापत्तनम और कोलंबो शामिल हैं।

" अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण हमें कार्यक्रम में बदलाव करते एक स्थान बदलना पड़ा, लेकिन अब हमें खुशी है कि हमारे पास पांच विश्वस्तरीय स्थान हैं, जहां महिला क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ मैच देखने को मिलेंगे। मंच तैयार है और मुझे विश्वास है कि यह टूर्नामेंट कल्पनाओं को नए पंख लगाएगा और प्रशंसकों की नई पीढ़ी को प्रेरित करेगा।

- जय शाह
चेयरमैन, आईसीसी

गत विजेता नॉर्थईस्ट और डायमंड हार्बर में खिताबी जंग आज

फुटबॉल : डूरंड कप चैंपियन को मिलेंगे रिकॉर्ड 1.21 करोड़ रुपए

कोलकाता, जेएनएन। डूरंड कप के मौजूदा 134वें सत्र के चैंपियन को 1.21 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिलेगी, जो एशिया के इस सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट के 137 साल के इतिहास में विजेता टीम के लिए सबसे बड़ी राशि है। डूरंड कप आयोजन समिति (डीसीओसी) ने शनिवार को खेले जाने वाले फाइनल की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा की। विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन में खेले जाने वाले फाइनल में गत विजेता नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी का सामना प्रतियोगिता में पदार्पण कर रही डायमंड हार्बर एफ से होगा। डीसीओसी ने इस साल की शुरुआत में पुरस्कार राशि में 250 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की थी। पिछले सत्र में इस टूर्नामेंट की कुल पुरस्कार राशि 1.2 करोड़ रुपए थी। इस साल इस बढ़ाकर रिकॉर्ड तीन करोड़ रुपए कर दी गई है।

इतिहास रचने का मौका

'जाइंट किलर' डायमंड हार्बर एफसी की नजरें पदार्पण साल में डूरंड कप खिताब जीतने वाली पहली टीम बनने पर लगी होंगी, लेकिन इसके लिए उसे फाइनल में नॉर्थईस्ट युनाइटेड एफसी जैसे धुरंधर को हराना होगा। यह मुकाबला इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि दोनों टीमों के पास इतिहास रचने का मौका है। नॉर्थईस्ट अगर जीतती है, तो यह उसका लगातार दूसरा डूरंड कप खिताब होगा और पिछले 34 साल में कोई टीम ऐसा करने में कामयाब नहीं हुई। पिछली बार ईस्ट बंगाल ने 1989, 1990 और 1991 में जीत की हैट्रिक लगाई थी। वहीं पहली बार डूरंड कप खेल रही डायमंड हार्बर जीतती है, तो आधुनिक दौर में पदार्पण के साथ एशिया की सबसे पुरानी ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी।

पुरस्कार राशि : चैंपियन- 1.21 करोड़, उपविजेता- 60 लाख रुपए
सेमीफाइनल में हारने वाली टीमें- प्रत्येक को 25 लाख रुपए
क्वार्टर फाइनल में हारने वाली टीमें- प्रत्येक को 15 लाख रुपए
व्यक्तिगत पुरस्कारः गोल्डन बॉल (टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी), गोल्डन बूट (सर्वाधिक गोल स्कोरर) और गोल्डन ग्लव्स (सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर) विजेताओं को तीन-तीन लाख रुपए के साथ नई महिंद्रा एक्सयूवी एसयूवी।

मैदान से हटकर

गली क्रिकेट खेला, लेकिन क्रिकेटर बनने के बारे में कभी नहीं सोचा: सारा

महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा ने खुलासा किया कि वे पिता के नक्शे-कदम पर चलती हुईं क्रिकेटर क्यों नहीं बनीं। इसके अलावा उन्होंने बताया कि उनके पिता की कौन सी पारी उनके दिल से सबसे करीब है। दरअसल सारा को टूरिज्म ऑस्ट्रेलिया ने भारतीय दर्शकों के लिए कम एंड से गुड डे कैंपेन का नया फेस बनाया है और वो इसकी वजह से सुर्खियों में हैं। सारा ने एक इंटरव्यू में ऑस्ट्रेलिया से अपने जुड़ाव और अपने निजी जीवन के बारे में चर्चा की। उन्होंने बताया कि जब से उन्हें याद है तब से ऑस्ट्रेलिया उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा है। जब उनके पिता सचिन क्रिकेट खेलते थे तब मैं उनके साथ पहली बार साल 1999 में ऑस्ट्रेलिया गई थी और इस देश से मेरे बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि जब मैं छोटी थी तब मुझे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के महत्व के बारे में ज्यादा अहसास नहीं था, लेकिन समय के साथ मुझे इस जगह के महत्व के बारे में पता लगा। सारा से पूछा गया कि उन्होंने क्रिकेटर बनने के बारे में विचार क्यों नहीं किया। इस पर सारा ने कहा कि मैंने कभी इस विषय पर नहीं सोचा। अर्जुन को क्रिकेट से ज्यादा लगाव था, लेकिन मैंने गली क्रिकेट खेला है पर कभी खुद क्रिकेटर बनने के बारे में सोचा ही नहीं। सारा ने बताया कि उनके पिता ने अनगिनत ऐसी पारियां खेली हैं, जिन्हें याद रखा जा सकता है, लेकिन साल 2013 में उन्होंने जो आखिरी पारी खेली थी वह मेरे दिल के सबसे करीब है। उन्होंने कहा कि अपने पिता की सबसे यादगार पारी चुनने की बात हो तो मैं उनके रिटायरमेंट मैच वाली पारी को चुनूंगी। उस समय मैं इतनी बड़ी हो चुकी थी कि समझ सकती थी कि इसका क्या मतलब है।

(जेएनएन)

राघवी शतक से चूकीं, वीजे जोशीथा का अर्धशतक, भारत-ए की मजबूत स्थिति

अनौपचारिक टेस्ट : भारत के ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ 299 रन

जेएनएन, ब्रिस्बेन

भारतीय महिला ए टीम ने एकमात्र अनौपचारिक टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया-ए के खिलाफ पहली पारी में 299 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। इसके बाद भारत-ए ने दिन का खेल खत्म होने तक ऑस्ट्रेलिया के 158 रन तक पांच विकेट झटक लिए थे। ऑस्ट्रेलिया 141 रन पीछे है और अभी दो दिन का खेल बाकी है। बारिश से प्रभावित पहले दिन भारत-ए पांच विकेट पर 93 रन बनाकर मुश्किल में थी। लेकिन राघवी बिष्ट ने 93 रन की जुझारू पारी खेली, जबकि वीजे जोशीथा (51) ने अंत में अर्धशतक जड़ा। बिष्ट ने बीती रात के 26 रन के स्कोर से आगे खेलते हुए राधा यादव (33) के साथ छठे विकेट के लिए 64 रन की भागीदारी निभाई। इसके बाद उन्होंने मीनू मणि (28) के साथ 75 रन की साझेदारी कर भारत को मुश्किल से निकाला। मध्यम गति की गेंदबाज मैटलन ब्राउन ने 63वें ओवर में उन्हें बोल्ड कर दिया। मणि को भी ब्राउन ने बोल्ड कर दिया। लेकिन जोशीथा और टिटास साधु (23) ने हार नहीं मानी और नौवें विकेट के लिए 75 रन की अहम साझेदारी करके भारत-ए को 300 रन के करीब पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया-ए की जॉर्जिया प्रेस्टविज ने 37 और ब्राउन ने 65 रन देकर तीन-तीन विकेट झटके। जवाब में ऑस्ट्रेलिया 43 ओवर में 158 रन पर पांच विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। भारत-ए के लिए साइमा ठाकोर (21 रन देकर दो विकेट) और स्पिनर राधा यादव (40 रन देकर दो विकेट) ने दो-दो विकेट लिए। कप्तान तहलिला विल्सन ने 49 रन बनाए और रशेल ट्रेनमैन (21) के साथ पहले विकेट के लिए 46 रन जोड़े। स्टंप तक विकेटकीपर निकोल फाल्टम 30 और सियाना जिंजर 24 रन बनाकर क्रीज पर थीं।

सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप : भारत ने बांग्लादेश को 2-0 से हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की

थिम्पू, जेएनएन। भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने शुक्रवार को प्रत्येक हाफ में एक-एक गोल कर बांग्लादेश को 2-0 से हराकर सैफ अंडर-17 महिला चैंपियनशिप में लगातार दूसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूरे मैच में दबदबा बनाए रखा, जिसमें पर्ल फर्नांडिस (14वें मिनट) और बोनिफिलिया शुलाई (76वें मिनट) ने उसके लिए गोल किए। इससे भारतीय टीम ने दो जीत से छह अंक से ग्रुप में अपना शीर्ष स्थान मजबूत किया। दोनों टीमें इससे पहले एक दूसरे से चार फाइनल खेल चुकी हैं, जिसमें प्रत्येक ने दो-दो खिताब जीते हैं। फिर भी यह मैच एकतरफा रहा।

अफ्रीकी टीम दूसरा मुकाबला 84 रन से जीती, तीन मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे

दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया से जीती लगातार 5वीं वनडे सीरीज

जेएनएन, मैके (ऑस्ट्रेलिया)

दक्षिण अफ्रीका ने शुक्रवार को दूसरे वनडे मैच में ऑस्ट्रेलिया पर 84 रन से जीत दर्ज कर तीन मैच की सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली। प्लेयर ऑफ द मैच तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी ने 42 रन देकर पांच विकेट झटके, जिससे ऑस्ट्रेलियाई टीम 278 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 12 ओवर रहते 193 रन पर ढेर हो गई। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगातार पांचवीं द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत हासिल की, जो 2016 के बाद से लगातार जारी है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के कार्यवाहक कप्तान ऐडन मारक्रम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया, जिसके बाद टीम ने मैथ्यू ब्रिट्ज्के (88 रन) और ट्रिस्टन स्टब्स (74 रन) के अर्धशतकों की मदद से 277 रन बनाए। नियमित कप्तान तेम्बा बावुमा को कार्यभार प्रबंधन के अंतर्गत आराम दिया गया था और वह सीरीज के रविवार को होने वाले अंतिम वनडे में टीम की अगुआई के लिए उपलब्ध होंगे। तीन मैच की सीरीज में लगातार दूसरी दफा ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। टीम केर्न्स में पहले वनडे में 98 रन से हारी थी।

■ 2009 के बाद पहली बार ऑस्ट्रेलिया ने घरेलू मैदान पर लगातार चार वनडे गंवाए हैं। दूसरी बार ऐसा हुआ है कि वह लगातार चार घरेलू वनडे मैचों में ऑलआउट हो गया और पहली बार किसी भी मैच में 200 रन का आंकड़ा भी नहीं छू पाया। उन्होंने अपने पिछले आठ वनडे मैचों में से सात गंवाए हैं।

■ मिचेल मार्श की टीम घरेलू मैदान में लगातार चौथे वनडे में 200 रन के अंदर सिमट गई। इससे पहले सिर्फ एक बार ही वे घरेलू मैदान पर लगातार चार बार वनडे में आउट हुए हैं।

■ ब्रीट्ज्के (378 रन) ने वनडे पदार्पण से चार मैचों में किसी भी अन्य खिलाड़ी की तुलना में अधिक रन बनाए हैं। ब्रीट्ज्के पुरुष वनडे में अपने पहले चार वनडे मैचों में 50 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने।

शॉर्ट गेंदों के खिलाफ जूझते रहे कंगारू

चोटिल कागिसो रबाडा की अनुपस्थिति में दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया, जिसमें एनगिडी ने दूसरे ही ओवर में मार्नस लाबुशेन (1) को आउट कर दिया। बर्गर ने ट्रेविस हेड (6) का विकेट लिया। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का शॉर्ट गेंदों के खिलाफ जूझना जारी रहा और कप्तान मार्श (18) भी पावरप्ले में मिडऑन पर लपके गए, जिससे टीम ने 38 रन पर तीन विकेट खो दिए। जोश इंगलिस (87) और कैमरन ग्रीन (35) ने 67 रन की साझेदारी निभाई। बाएं हाथ के स्पिनर सेनुरान मुथुसैमी ने 23वें ओवर में ग्रीन का रिटर्न कैच लेकर इस भागीदारी का अंत किया। एलेक्स कैरी (13) के आउट होने से ऑस्ट्रेलिया ने 133 रन पर पांचवां विकेट गंवाया।

ब्रिट्ज्के का लगातार चौथा अर्धशतक

रेयान रिकल्टन (08) और स्टब्स ने चौथे विकेट के लिए 89 रन की साझेदारी निभाई। मारक्रम (0) स्क्वायर मिड-विकेट पर आसान कैच देकर बिना खाता खोले आउट हो गए। ब्रिट्ज्के ने लगातार चौथा अर्धशतक लगाया, जबकि स्टब्स ने 16 वनडे में पहली बार पचास रन का आंकड़ा पार कर टीम को संभाला। ब्रिट्ज्के अपने दूसरे वनडे शतक से चूक गए। टीम ने लगातार दो विकेट गंवा दिए, लेकिन फिर भी 300 रन से ज्यादा का स्कोर बनाने की ओर बढ़ रही थी। 40वें ओवर में टीम का स्कोर पांच विकेट पर 233 रन था, लेकिन छह ओवर के अंदर 31 रन के अंदर चार विकेट खो दिए।

खेल एक नजर

अजित आगरकर को दो नए सदस्यों का मिलेगा साथ

नई दिल्ली, जेएनएन। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) ने शुक्रवार को पांच सदस्यीय सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चयन समिति में दो पदों के साथ-साथ महिला पैनल में चार पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए। चयनकर्ता पद के लिए पात्रता मानदंडों में पिछले कुछ वर्षों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। आवेदकों को कम से कम सात टेस्ट मैच या 30 प्रथम श्रेणी मैच खेलने चाहिए। इसके अलावा कम से कम 10 वनडे अंतरराष्ट्रीय मैच या 20 प्रथम श्रेणी मैच खेलने वाले उम्मीदवारों के नाम पर भी विचार किया जा सकता है। बीसीसीआई के एक अधिकारी ने कहा, चयनकर्ताओं के अनुबंध का हर साल नवीनीकरण किया जाता है। हमने अभी तक यह तय नहीं किया है कि किन चयनकर्ताओं को बदला जाएगा, लेकिन यह प्रक्रिया जल्द ही शुरू की जाएगी। वर्तमान में पुरुष चयन समिति के अध्यक्ष पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर हैं और इसमें एसएस दास, सुब्रतो बनर्जी, अजय रात्रा और एस शरथ शामिल हैं। इस समिति ने हाल में एशिया कप के लिए टीम का चयन किया था। बोर्ड ने इसके अलावा पुरुष जूनियर क्रिकेट चयन समिति में एक पद को भरने के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं, जो शिविरों, दौरों और टूर्नामेंटों के लिए आयु वर्ग की टीमों (अंडर-22 तक) का चयन करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बीसीसीआई ने महिला राष्ट्रीय चयन समिति के चार पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं। वर्तमान चयन समिति में नीतू डेविड (अध्यक्ष), रेणु मार्ग्रेट, आरती वैद्य, कल्पना वेंकटचार और श्यामा डे शॉ शामिल हैं। इस समिति ने हाल में वनडे विश्व कप के लिए टीम का चयन किया था। सभी आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 10 सितंबर है।

एसए20 फाइनल की मेजबानी करेगा केपटाउन का न्यूलैंड्स

जोहानिसबर्ग, जेएनएन। दक्षिण अफ्रीका की घरेलू टी-20 लीग एसए20 के आगामी सत्र का फाइनल मैच केपटाउन के न्यूलैंड्स में होगा, जिसमें डरबन, सेंचुरियन और जोहानिसबर्ग जैसे स्थानों पर प्लेऑफ के अहम मुकाबले खेले जाएंगे। लीग का चौथा सत्र 26 दिसंबर से शुरू होगा। डरबन एसए20 में पहली बार किसी प्लेऑफ मैच की मेजबानी करेगा, जब प्रतियोगिता की दो सर्वश्रेष्ठ टीमें 21 जनवरी को क्वालिफायर एक में आमने-सामने होंगी। हाईवेल्ड क्षेत्र दो महत्वपूर्ण प्लेऑफ मैचों की मेजबानी करेगा, जिसमें सेंचुरियन 22 जनवरी को एलिमिनेटर और जोहानिसबर्ग के वांडरर्स 23 जनवरी को क्वालिफायर दो के मैच शामिल है। एसए-20 के अब तक के सभी फाइनल मैच दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में खेले गए है। एसए-20 के लीग आयुक्त ग्रीम स्मिथ को आगामी फाइनल में भी दर्शकों के खचाखच भरे होने की उम्मीद जताई। इस सत्र के लिए खिलाड़ियों की नीलामी का आयोजन नौ सितंबर को होगा।

एशियाई चैंपियनशिप: वलारिवान ने जीता स्वर्ण, जूनियर स्पर्धा में दबदबा कायम

शिमकेंट (कजाकिस्तान), जेएनएन। भारतीय निशानेबाज एलावेनिल वलारिवान ने शुक्रवार को 16वीं एशियाई चैंपियनशिप की महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तमिलनाडु की इस 26 वर्षीय खिलाड़ी ने फाइनल में 253.6 का स्कोर बनाकर शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने विश्व कप में कई स्वर्ण पदक जीते हैं और इसके अलावा विश्व चैंपियनशिप में भी शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह उनका एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में दूसरा स्वर्ण पदक है। इससे पहले उन्होंने 2019 में ताइवान में स्वर्ण पदक जीता था। चीन की शिनलू पेंग ने 253 अंक के साथ रजत पदक, जबकि कोरिया की यूंजी क्वोन (231.2) ने कांस्य पदक जीता। अभय सिंह शेखों (65) और गनेमत शेखों (73) ने स्कीट मिश्रित टीम स्पर्धा में क्वालिफिकेशन में 138 अंक हासिल किए तथा दूसरे कांस्य पदक मुकाबले में कुवैत के अब्दुल्ला अलराशिदी और अफराह अलमोहम्मद से भिड़े। इस बीच भारत के जूनियर निशानेबाजों ने दबदबा बनाए रखा। हरमेहर सिंह लाली ने यशस्वी राठौड़ के साथ मिलकर जूनियर स्कीट मिश्रित टीम स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। शाम्भवी श्रवण, हृदया श्री कोंडूर और ईशा अनिल की तिकड़ी ने जूनियर 10 मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में टीम स्पर्धा में 1896.2 अंक के साथ स्वर्ण जीता।

सिंकफील्ड कप : प्रज्ञाननंदा-गुकेश ने चौथे दौर की बाजी भी ड्रॉ खेली

सेंट लुई (अमेरिका), जेएनएन। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञाननंदा ने सिंकफील्ड कप शतरंज टूर्नामेंट के चौथे दौर में अमेरिका के सैमुअल सेवियन के साथ अंक बांटे, जबकि विश्व चैंपियन डी गुकेश और फ्रांस के मैक्सिम वाचियर-लाग्रेव के बीच मुकाबला भी बराबरी पर छूटा। अमेरिका के फैबियानो कारुआना ने दिन के एकमात्र निर्णायक गेम में उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुसत्तोरोव को हराकर लगातार दूसरी जीत दर्ज की। अन्य मुकाबलों में अमेरिका के लेवोन अरोनियन ने पोलैंड के डूडा जान-क्रिस्तोफ के साथ तथा फ्रांस के अलीरेजा फिरोजा ने वेस्ली सो के साथ अंक बांटे। अभी जबकि पांच दौर का खेल होना बाकी है, तब कारुआना तीन अंक के साथ एकल बढ़त पर हैं। उनके बाद प्रज्ञाननंदा और अरोनियन का नंबर आता है, जो 2.5-2.5 अंक के साथ दूसरे स्थान पर हैं।

मप्र का स्वर्णिम चौका, दूसरे दिन के सभी गोल्ड जीते

खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पदक तालिका में शीर्ष पर मध्य प्रदेश

भोपाल, खेप्र। मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी के खिलाड़ियों ने पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल-2025 में शानदार प्रदर्शन करते हुए शुक्रवार को चार स्वर्ण पदक अपनी झोली में डाले। श्रीनगर की डल झील पर खेली जा रही प्रतियोगिता के दूसरे दिन चार स्वर्ण पदक दांव पर लगे थे, जो सभी राज्य के खाते में आए। इस तरह मप्र चार स्वर्ण सहित सात पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर मौजूद है। इसमें एक रजत व दो कांस्य पदक शामिल हैं। दूसरे नंबर पर ओडिशा (एक स्वर्ण व तीन रजत) और तीसरे नंबर पर जम्मू एंड कश्मीर (एक स्वर्ण, एक रजत व एक कांस्य) है। एक दिन पहले मप्र के खिलाड़ियों ने एक रजत व दो कांस्य पदक जीते थे। इसमें कृष्णा जाट ने 1000 मीटर (सी-1) में रजत, मासूमा यादव ने 1000 मी (सी-1) और मयंक ने 1000 मीटर (के-1) में एक-एक कांस्य पदक जीता।

स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी

मप्र की 17 साल की डैली बिश्नोई ने 500 मीटर (के1) में 2:11.093 सेकंड का समय निकाला और स्वर्ण अपने नाम किया। उत्तराखंड की पी रोजी देवी दूसरे और केरल की निकिता सरकार तीसरे स्थान पर रही। 14 साल की निहारिका सिंह और चंद्रकला कुशवाह ने कयाकिंग 500 मीटर (के2) में 02:04.642 सेकंड का समय निकालकर खिताब जीता। केनोइंग (सी2) टीम के सुधीर कुमार और प्रिंस गोस्वामी ने 1:50.943 सेकंड का समय निकालकर पीला तमगा अपने नाम किया। कयाकिंग टीम (के2) के आदित्य सिंह और मनजीत ने 1:41.595 सेकंड में स्वर्ण पदक अपने नाम किया।

टीम इंडिया में विकल्प की कोई कमी नहीं: रॉस टेलर

नई दिल्ली, जेएनएन। न्यूजीलैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉस टेलर ने कहा कि एशिया कप के लिए भारत की टी-20 टीम में श्रेयस अय्यर को जगह नहीं मिलना दिखाता है कि इस देश में प्रतिभावान खिलाड़ियों के विकल्प में कोई कमी नहीं है। अय्यर ने घरेलू क्रिकेट में लगातार शानदार प्रदर्शन किया है। उनके नेतृत्व में केकेआर ने 2024 आईपीएल खिताब को जीता था, जबकि इस साल उनकी कप्तानी में पंजाब ने फाइनल तक का सफर तय किया। टेलर ने कहा, मैंने टीम नहीं देखी है, इसलिए कुछ कह नहीं सकता। जब आप इस तरह के बेहतरीन खिलाड़ी को बाहर रख सकते हैं, तो आपको अपनी टीम में विकल्पों को लेकर काफी सहज होना पड़ेगा। उन्होंने भारत के नए टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की तारीफ की, जिनके नेतृत्व में इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की टेस्ट सीरीज को भारतीय टीम ने 2-2 से बराबर किया। उन्होंने कहा कि आप जब भी टेस्ट क्रिकेट को विदेशी परिस्थितियों में खेलते हैं, तो आपको दिलेरी से परिस्थितियों का सामना करना होता है।

वेस्ट टू आर्ट्स प्रदर्शनी का नगर निगम ने किया आयोजन

सतना। नगर पालिक निगम सतना के आयुक्त महोदय के आदेशानुसार एवं स्वच्छ भारत मिशन सतना के नोडल अधिकारी तथा स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशन में आज दिनांक 22 अगस्त 2025 को आईईसी टीम द्वारा विभिन्न वार्डों में स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।कार्यक्रमों में मुहल्ला सभा, स्वच्छता शपथ, होम कंपोस्टिंग, प्लास्टिक बैन, रेड व येलो स्पॉट, सोर्स सेग्रीगेशन व स्वच्छता ऐप की जानकारी दी गई तथा रीवा रोड पर विशेष सफाई अभियान चलाया गया।

एकेएस सतना एवं ज्ञान गंगा संस्थान,जबलपुर के मध्य एमओयू पर हस्ताक्षर

सतना। एकेएस विश्वविद्यालय सतना के कंप्यूटर साइंस विभाग और जबलपुर स्थित ज्ञान गंगा इंस्टीट्यूट ऑफटेक्नोलॉजी एंड साइंसेज़ के बीच शैक्षणिक, अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने हेतु मेमोरेंडम ऑफअंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता दोनों संस्थानों के मध्य शैक्षणिक सह्योग को नई दिशा प्रदान करेगा। एमओयू पर हस्ताक्षर डॉ अखिलेश ए वाऊ डीन कंप्यूटर साइंस एकेएस विश्वविद्यालय तथा डॉ रजनीत जैन, चेयरमैन,जीजीआईटीएस द्वारा किए गए।

शिव मेडिकल स्टोर को उड़नदस्ता दल ने किया सील

फार्मासिस्ट और मालिक मिले अनुपस्थित, नशे की बढ़ती प्रवृत्ति रोकने की जा रही कार्यवाही

जागरण सतना

नशे की बढती प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए गठित की गई औषधि निरीक्षको के उड़नदस्ता दल ने सतना सहित पन्ना जिले में कई दवा दुकानों पर जांच पड़ताल कर कार्यवाही की है। बताया जाता है कि शुक्रवार को औषधि निरीक्षकों के उड़नदस्ता दल ने सतना के राजेन्द्र नगर में संचालित शिव मेडिकल स्टोर को सील कर दिया है। यहां पर उड़नदस्ता दल को बडे पैमाने पर अनियमितता देखने को मिली है। सतना एवं शहडोल जिले के दल में शरद कुमार जैन औषधि निरीक्षक जबलपुर प्रियंका कुमारी चौबे सतना एवं बिहारी लाल अहिरवार सिंगरौली को शामिल किया गया है।

यहां पर हुई कार्यवाही : सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर संयुक्त टीम के द्वारा 20 अगस्त को पुराना नगर निगम काम्प्लेक्स में स्थित मेसर्स अनुष्का मेडिकल का निरीक्षण किया गया द्य पांच घंटे के निरीक्षण के दौरान दुकानदार के द्वारा नशे के रूप में दुरूपयोग होने वाली विभिन्न औषधियों के स्टॉक में भारी गड़बड़ी पाई गई है द्य अनुष्का मेडिकल से मिले विक्रय रिकॉर्ड के आधार पर अन्य दुकानों का निरीक्षण किया गया तथा स्टॉक का सत्यापन किया गया है अनुष्का मेडिकल के द्वारा जबलपुर में स्थित कंपनी के स्टॉकिस्ट से भारी मात्रा में स्पस्मोप्रोक्सीवोन कैप्सूल का क्रय किया गया है जिसकी लगभग 5614 स्ट्रिप के विक्रय की जानकारी प्रस्तुत नहीं कर सके द्य इसके अलावा एबॉर्शन किट्सए एवं अन्य नारकोटिक औषधियों का विक्रय का रिकॉर्ड भी प्रस्तुत नही किया गया। टीम के द्वारा अस्पताल चौक स्थित डिस्काउंट मेडिसिन प्रकाश मेडिकल एवं सर्जिकल, साईं कृपा मेडिकल एजेंसी कृष्णा नगर सतना, रवि मेडिकल नागोद, सिमना मेडिकल स्टोर्स नागोदए जया मेडिकल दिदौंध, लक्की मेडिकल नागोद, कपिल मेडिकल कोठी, सोनी मेडिकल स्टोर्स देवेन्द्र नगर जिला पन्ना का निरीक्षण किया गया है।

जारी की ये एडवाइजरी

युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिये बेहद जरूरी है कि नींद की दवाओं और अन्य नशे की दवाओं का विक्रय बड़ी ही सावधानी से किया जाये। दवाओं का संग्रहण उचित स्थान पर किया जाये। फ्रिज में उन्ही दवाओ का संग्रहण किया जाना चाहिए जिनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाना है अग्रिम तिमाही में एक्सपायरी डेट की दवाओं को विक्रयार्थ स्टॉक से अलग किया जाये ताकि भूलवश भी एक्सपायरी डेट की दवाओं का विक्रय न हो। यदि कोई व्यापारी नशे की दवाओं के अवैध व्यापार में लिप्त पाया जाता है तो कठोर कार्यवाही की जायेगी। जन मानस से अपेक्षा की जाती है कि यदि आपके आस पास किसी घर या दुकान में किसी भी प्रकार की संदिग्ध स्थिति में नशीली औषधियों का विक्रय या संग्रहण पाया जाता है तो इसकी सूचना पता एवं दुकान की फोटो सहित औषधि निरीक्षक कार्यालय में प्रेषित करे ताकि गलत लोगो पर संयुक्त कार्यवाही की जा सके।

22 अगस्त को टीम द्वारा मेसर्स गोविन्द मेडिकल कोठी रोड, अलोक मेडिकल पन्ना रोड, विनोद मेडिकल स्टोर पन्नीलाल चौक का निरीक्षण किया गया।

आय प्रमाण पत्र में गलत डाटा फीड करने पर आकाश स्टेशनरी एमपी ऑनलाइन केन्द्र सील

तहसीलदार की जांच के बाद एसडीएम राहुल सिलाडियॉ ने की बड़ी कार्यवाही

जागरण सतना। आय प्रमाण पत्र में गलत डाटा फीड करने वाले मामले को प्रशासन ने भांडा फोड़ करते हुये एमपी आनलाइन केन्द्र को सील कर दिया है। यह कार्यवाही तहसीलदार सौरभ द्विवेदी की जांच में प्रमाणित पाये जाने के बाद एसडीएम राहुल सिलाडियॉ द्वारा की गई है।

ये है मामला : बताया जाता है कि विगत दिनो एक आय प्रमाण पत्र में एमपी ऑनलाइन संचालक द्वारा आवेदक की आय 3 रूपये अंकित कर दी गई थी जबकि उसके शपथ पत्र में 45 हजार रूपये प्रतिमाह आय दर्शायी गई थी। यह निश्चित तौर पर एक गलत और भ्रामक डाटा फीडिंग का मामला है इस विषय को बेहद गंभीरता से लेते हुये एसडीएम रघुराजनगर सिटी राहुल सिलाडियॉ ने आकाश स्टेशनरी एमपी ऑनलाइन केन्द्र को सील कर दिया है। इस कार्यवाही के दौरान एसडीएम सिटी राहुल सिलाडियॉ , तहसीलदार सौरभ द्विवेदी, एमपी ऑनलाइन मैनेजर महेन्द्र चौरसिया, पटवारी रामभजन गौतम मौजूद रहे।

लिया गया यह भी निर्णय : बताया जाता है कि इस कार्यवाही के बाद एसडीएम राहुल सिलाडियॉ ने निर्णय लिया है कि केन्द्र पूर्व मे जारी किये गये सभी आवेदनो की विस्तृत जांच की जाये। दोष सिद्ध होने पर एमपी ऑनलाइन आइडी को निरस्त करने का प्रस्ताव भेजा जायेगा। आवश्यकता अनुसार प्रकरण में एफआईआर दर्ज कर अपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जायेगा।

नागौद विधानसभा के किसानों को शीघ्र खाद नहीं मिली तो कांग्रेस करेगी आंदोलन : डॉ रश्मि सिंह

जागरण सतना। चालू खरीफ सीजन में धान की फसल में उर्वरक की भारी कमी के बीच नागौद विधानसभा से डॉ रश्मि सिंह ने किसानों को शीघ्र उर्वरक उपलब्ध न कराने पर गंभीर चिंता जताते हुए बृहद आंदोलन की चेतावनी दी है। डॉ रश्मि सिंह ने बताया कि नागौद क्षेत्र के किसान लगातार शिकायत कर रहे हैं कि प्रभावशाली और सत्ता से जुड़े किसानों को आसानी से उर्वरक पर्ची मिल रही है जबकि लघु एवं सीमांत किसान दिनभर विपणन गोदाम के चक्कर लगाने के बाद भी खाद नहीं ले पा रहे हैं।उन्होंने आरोप लगाया कि स्थानीय राजनैतिक संरक्षण प्राप्त कर्मचारी गोदाम में काबिज हैं, जिसके कारण उर्वरक पर्ची केवल चयनित किसानों को ही मिल रही है। इससे मजबूर होकर कई किसान प्राइवेट दुकानों से ऊँची कीमत पर यूरिया खरीदने को मजबूर हैं। डॉ रश्मि सिंह ने कहा स्थानीय भाजपा नेता और प्रशासन इस गंभीर संकट को केवल औपचारिकता मानकर पल्ला झाड़ रहे हैं। यदि शीघ्र किसानों को पर्याप्त उर्वरक नहीं मिला और बिचौलियों पर लगाम नहीं लगी तो नागौद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बृहद आंदोलन किया जाएगा।

बिगौड़ी अग्निकांड के 02 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने शान्ति व्यवस्था बनाए रखने 160 लोगों के विरुद्ध की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही

जागरण सतना। बिगौड़ी अग्निकांड के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिहाज से 160 लोगो के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। यह कार्यवाही एसपी मैहर सुधीर अग्रवाल के निर्देश, एएसपी डॉ चंचल नागर एवं एसडीओपी ख्याति मिश्रा के मार्गदर्शन में ताला थाना प्रभारी महेन्द्र मिश्रा द्वारा की गई है।

ये है विवरण : थाना ताला क्षेत्रान्तर्गत फरियादी उपस्थित थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि करीब 01 माह पूर्व ग्राम बिगौड़ी मे हुई शिवनारायण उर्फ दोष तिवारी की हत्या मे आरोपी घर न गिराने एवं अन्य मांगो को लेकर 17 अगस्त को ग्राम बिगौड़ी मे हिन्दू संगठन द्वारा महापंचायत का कार्यक्रम किया गया था जो महापंचायत कार्यक्रम मे सभी लोग धर्म को लेकर उत्तेजनापूर्ण भाषण दे रहे थे और प्रशासन द्वारा 01 माह पहले शिवनारायण उर्फ दोष तिवारी की हुई हत्या पर मुलजिम का घर न गिराने को लेकर भाषण दे रहे थे एवं भाषण के बाद रैली निकाली गयी जो रैली के दौरान भीड़ द्वारा उत्तेजनापूर्ण भाषण से प्रभावित होकर ग्राम बिगौड़ी तिराहे मे स्थित फरियादी की दुकान मे पेट्रोल डालकर आग लगा दी जिससे उसका काफी नुकसान हुआ है । घटना से वरिष्ठ अधिकारीगण को अवगत कराया जाकर फरियादी की रिपोर्ट पर 08 नामजद एवं अन्य आरोपीगण के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

ये आरोपी गिरफ्तार : बिगौड़ी अग्निकांड के जिन दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उसमें नीलेश कुमार पटेल पिता भगवानदीन पटेल उम्र 39 वर्ष निवासी ग्राम बिगौड़ी थाना ताला जिला मैहर , अतुल उर्फ छोटे पटेल पिता रामबहोरी पटेल उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बिगौड़ी थाना ताला जिला मैहर का नाम शामिल है।

छेड़खानी करने वाला आरोपी गिरफ्तार

जागरण सतना। घर से दूध लेने गई एक नाबालिग से छेड़खानी करने वाले आरोपी को सिटी कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहा से उसे जेल भेज दिया गया है। यह कार्यवाही एसपी आशुतोष गुप्ता के निर्देश, एएसपी डॉ शिवेश सिंह बघेल एवं सीएसपी देवेन्द्र प्रताप सिंह चौहान के मार्गदर्शन में सिटीकोतवाली टीआई रावेन्द्र द्विवेदी की गई है। बताया जाता है कि पीडिता ने 17 अगस्त को अपने माता पिता के साथ थाना पहुंचकर आरोपी बिल्ला बसोर निवासी बजरहा टोला के विरूद्ध छेड़खानी का आवेदन प्रस्तुत किया था जिस पर पुलिस ने पास्को एक्ट अपराध दर्ज कर नाबालिग के साथ हुई इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी की तलाश में जुट गई। मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने 21 अगस्त की रात बजरहा टोला से आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

पीएम आवास योजना की उच्चस्तरीय जांच हो : सुरेंद्र शर्मा

जागरण सतना। जदयू राष्ट्रीय कार्यसमिति के पूर्व सदस्य अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि गरीबों के लिए चलाई गई योजनाओं में व्यापक स्तर पर अनियमितता बरती जा रही है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना संदेह के घेरे में है कमोवेश यह सम्पूर्ण प्रदेश हो रहा है गरीबों के आशियाने अमीरों की झोली में जा रहे है आवंटन की प्रक्रिया शत.प्रतिशत पारदर्शी प्रतीत नहीं होती इसमें भ्रष्टाचार और अनियमितता को शिरे से नकारा नहीं जा सकता जरुरतमंद लोग इसी के चलते योजनाओं के वास्तविक लाभ से वंचित हैं इस तरह की आवंटन प्रक्रिया में पात्र कितने है और अपात्र कितने है इसकी एक बार उच्चस्तरीय जांच कराई जानी चाहिए जिससे सच्चाई सामने आ सके । श्री शर्मा ने कहा कि इसके अलावा भी शासन की कयी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं जिसमें अन्तोदय अन्न योजनाए प्रधानमंत्री जनधन योजना, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजनाए उज्ज्वला योजना है इनकी भी समीक्षा और जाच की जानी चाहिए जिसके लिए कमेटी बने और पारदर्शिता के साथ उच्चस्तरीय जांच की जाए।

जागरण पब्लिकेशन प्रा. लिमि. के लिए मुद्रक/प्रकाशक मदन मोहन गुप्ता द्वारा दैनिक जागरण प्रेस गांधी नगर उर्रहट रीवा (म.प्र.)से मुद्रित एवं प्रकाशित। सम्पादकः **मदन मोहन गुप्ता।** आर.एन.आई. नं- 1505/57, डाक पंजीयन क्र.- रीवा संभाग 04 /म.प्र. संस्थापक **स्व. गुरुदेव गुप्त**
कार्यालयः- मोबाइल नं रीवा- 9098357869, 9425018958 **सतना** - 9993315949 **सीधी**-7089620900 **सिंगरौली**-9424652999 E-mail: rewajagrannew2015@gmail.com